राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 7 अंक 280

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, सोमवार, 18 मार्च, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

लगातार दूसरी बार संघ के सरकार्यवाह चुने गए दत्तात्रेय होसबाले

>> 5

सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टियों ने नहीं बताए नाम

आदेश पर अमल ▶ चुनाव आयोग ने चुनावी बांड का सारा ब्योरा और पार्टियों का पत्र व्यवहार किया सार्वजनिक

चुनावी चंदे में सबसे बड़ा हिस्सा भाजपा, तृणमूल और कांग्रेस का

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

चुनावी बांड के जरिये जिन पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, वे इससे जुड़ी सूचना सार्वजनिक करने में आनाकानी कर रही हैं। चुनाव आयोग ने रविवार (17 मार्च, 2024) को चुनावी बांड और इस बारे में सभी राजनीतिक दलों से जुड़े पत्र व्यवहार का ब्योरा सार्वजनिक किया है। द्रमुक, अन्नाद्रमुक, राकांपा, जनता दल (एस) जैसी गिनी-चुनी क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश दलों ने यह नहीं बताया है कि उन्हें किस कंपनी या व्यक्ति से चुनावी चंदा मिला है। भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यह तो बताया है कि उन्हें कब और कितनी राशि के बांड मिले, लेकिन इसे किस कंपनी ने दिया है, इससे जुड़ी सूचना उन्होंने नहीं दी है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने एसबीआइ पर दारोमदार डाल दिया है कि वह उसे मिले बांड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा सकता है। ध्यान रहे कि कुछ राजनीतिक दल चुनावी बांड में पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद सूचना नहीं दे रहे हैं। भाजपा ने तर्क दिया है कि उसे लोक प्रतिनिधि कानून, 1951 और आयकर अधिनियम, 1960 के तहत जो भी चुनावी चंदा मिला है, उसे सार्वजनिक नहीं करने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने पूर्व में चुनावी बांड से जुड़ी सारी जानकारी बंद लिफाफे में शीर्ष अदालत को दे दी थी। ये बंद लिफाफे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक दलों ने आयोग को दिए थे। बाद में कोर्ट ने इसे चुनाव आयोग को लौटा दिया था। इसे 17 मार्च को वेबसाइट पर डाला गया है। यह कयास लगाया जा रहा था कि इससे किस कंपनी ने किस पार्टी के पक्ष में चुनावी बांड खरीदा है, यह पता चल जाएगा। लेकिन, ऐसा नहीं हो सका। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत शुरुआती जानकारी में 12 अप्रैल, 2019 से चुनावी बांड योजना निरस्त किए जाने तक दलों को दिए गए चंदे का विवरण था। लेकिन, एसबीआइ ने रविवार को अपलोड की गई फाइल में एक साल पहले अप्रैल 2018 से कितने चुनावी बांड राजनीतिक दलों को जारी किए गए, इसका ब्योरा दिया है।

क्षेत्रीय दलों द्वारा चंदा देने वाली कंपनियों का नाम सार्वजनिक किए जाने से यह भी पता चलता है कि जिस पार्टी की राज्य में सरकार है, उसे स्थानीय कंपनियों की तरफ से ज्यादा चंदा दिया गया है। राकांपा को 2019 में उद्योगपति साइरस पूनावाला ने अलग-अलग मौकों पर कुल 3.75 करोड़ रुपये का चंदा दिया। अन्नाद्रमुक को चेन्नई सुपरकिंग (सीएसके) की तरफ से चंदा दिया गया है। जदयू को इंफोसिस, एम्बेसी समूह और बायकान जैसी बेंगलुरु की बड़ी कंपनियों ने चंदा दिया है।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ 12 अप्रैल, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद हुए पत्र व्यवहार का ब्योरा सार्वजनिक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को तब चुनावी बांड से प्राप्त राशि और इसे किस खाते में जमा कराया गया है, इसकी सूचना चुनाव आयोग को देने को कहा था। इसमें तृणमूल और कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र भी हैं। इन दोनों पार्टियों ने एसबीआइ के साथ इस बारे में हुए पत्राचार का ब्योरा दिया है।

चुनावी बांड पर किस पार्टी ने क्या कहा पेज>>5

अप्रैल, 2019 से पहले के चुनावी बांड के आंकड़े भी हुए जारी

अप्रैल 2018 से अब तक किस पार्टी को कितना मिला चंदा

पार्टी	राशि करोड़ रु. में
भाजपा	6,986.5
तृणमूल	1,396.94
कांग्रेस	1,334.35
बीजद	944.5
द्रमुक	656.5
वाइएसआर कांग्रेस	442.8
तेदेपा	181.35

(राशि करोड़ रु. में)

फ्यूचर गेमिंग ने द्रमुक को दिया 509 करोड़ रुपये का चंदा

लाटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन। (फाइल/ रायटर)

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक को सबसे ज्यादा 509 करोड़ रुपये का चंदा विवादास्पद कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड ने दिया है। 14 मार्च, 2024 को जब चुनाव आयोग ने बांड खरीदने वाली कंपनियों की सूची सार्वजनिक की थी, उसमें फ्यूचर गेमिंग सबसे ऊपर थी। लाटरी किंग के नाम से प्रसिद्ध सैंटियागो मार्टिन इस कंपनी के प्रवर्तक हैं। इस कंपनी ने कुल 1,368 करोड़ रुपये का चुनावी चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। चेन्नई इसके संचालन का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी को भारी-भरकम चंदा देना चुनावी साल में खासा रंग दिखा सकता है। द्रमुक को मेघा इंजीनियरिंग ने भी 85 करोड़ रुपये का चंदा दिया है।

मथुरा के लाडलीजी मंदिर में रेलिंग टूटी, दो दर्जन श्रद्धालु दबे

बरसाना (मथुरा) : विश्वविख्यात लाडलीजी मंदिर की लड्डू होली में उमड़ी भीड़ के दबाव में मंदिर की सीढ़ियों पर लगी रेलिंग टूट गई और दो दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु नीचे गिरकर दब गए। दो घंटे तक घायल श्रद्धालु तड़पते रहे, लेकिन उन्हें उपचार नहीं मिल सका। शाम छह बजे घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पांच की हालत गंभीर है। (पेज-6)

पुणे में आतंकी संगठन आइएस की चार संपत्तियां कुर्क

नई दिल्ली : एनआइए ने पुणे में आतंकी संगठन आइएस के माड्यूल के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 11 आतंकियों की चार अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। जांच एजेंसी के अनुसार यह कार्रवाई देश में वैश्विक आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए की गई है। (पेज-7)

पुतिन जीते, 2030 तक बने रहेंगे रूस के राष्ट्रपति

मास्को : रूस में तीन दिनों की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई मतगणना में कुल पड़े मतों में 87 प्रतिशत मत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिले हैं। इस प्रकार से पुतिन ने चुनाव जीत लिया है और वह 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अमेरिका ने कहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। (पेज-11)

जागरण विशेष

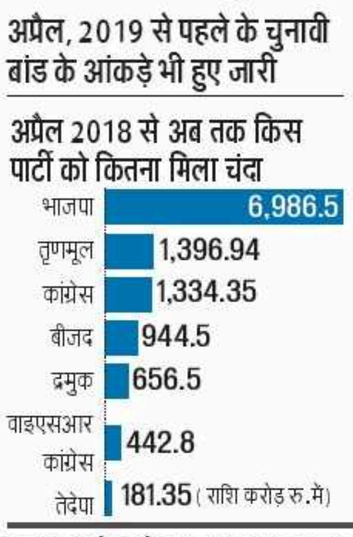

कर्मठ किसान

सरकारी योजनाओं का मिला साथ तो बनी बात

अलीगढ़: सरकारी योजनाओं के सहारे किसान अपना संकल्प पूरा करने के साथ नवाचार की सुनहरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बबलू शर्मा के एफपीओ का व्यापार पिछले तीन वर्ष में 25 गुना बढ़ा है। अब वे निर्यात की तैयारी में जुटे हैं। (पेज-6)

संपादकीय

महासमर का मौजूदा परिदृश्य: चुनावी माहौल मतदान तक बदलता रह सकता है, लेकिन आज के परिदृश्य में भाजपा के नेतृत्व वाला राजग सत्ता हासिल करने की होड़ में आगे नजर आता है। **राजकुमार सिंह** का आकलन।

सेक्युलरिज्म की भ्रामक अवधारणा: 'धर्म एवं संविधान' तथा 'धर्म एवं सत्य' में परस्पर विरोध न होकर वास्तव में सहयोग का एक भाव ही निहित है। **प्रणय कुमार** का दृष्टिकोण। ● पेज 8

विमर्श

मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण : मदरसों को आम तौर पर एक धार्मिक विद्यालय की नजर से देखा जाता है, जहां पर मुस्लिम मत से संबंधित शिक्षा दी जाती है। मदरसों के बारे में अन्य समुदायों में बनी नकारात्मक धारणा को तोड़ने के लिए उनका आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक बता रहे हैं, **लालजी जायसवाल**।

चुनावी बयार में जागती अंतरात्मा की आवाजें: लोकसभा चुनाव की आहट शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में निष्ठा बदलने का जो मौसम शुरू हुआ, वह अब अपने चरम पर है और राजनीति के शातिर ऐसे मोहरों की घेरेबंदी में जुटे हुए हैं जो उनके लिए बाजी जीत सकें। **हरिशंकर मिश्र** की डायरी। ● पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

साहित्य और संगीत का

वसंत की पुष्पिता भाषा हिंदी

शहनाई को दिलाया शास्त्रीय संगीत में मान ● पेज-13

गुजरात विवि के छात्रावास में विदेशी छात्रों पर हमला

अहमदाबाद : अहमदाबाद में कुछ लोगों ने गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रावास में नमाज पढ़ने के दौरान विभिन्न देशों के छात्रों पर हमला कर दिया। शनिवार रात को हुई इस घटना के बाद श्रीलंका और ताजिकिस्तान के एक-एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो आरोपितों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने बताया कि 20-25 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना की जांच के लिए सुरक्षाकर्मियों के नौ दल गठित किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त तरुण दुग्गल ने बताया कि पुलिस ने अन्य आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। (पेज-6)

देश में जानबूझकर फैलाया जा रहा है द्वेष : राहुल गांधी

मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए की रैली के दौरान एकजुटता प्रदर्शित करते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन, राकांपा नेता शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला आदि नेता। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर आइएनडीआइए ने मुंबई में किया शक्ति प्रदर्शन
- कांग्रेस नेता ने कहा- सरकार छोटे उद्यमियों एवं कारोबारियों को खत्म करना चाहती है
- मोदी ईवीएम, ईडी, सीबीआइ और आयकर के बिना लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जानबूझकर द्वेष फैलाया जा रहा है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से यही संदेश सामने आया है कि द्वेष मत फैलने दो, बल्कि नफरत के बाजार में मुहब्बत की दुकान खोलो।

राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली रविवार को मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में आइएनडीआइए के शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन गई। इसमें महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के नेताओं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से आए विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इनमें बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नेशनल कांफ्रेंस के नेता व जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, महाराष्ट्र की वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर आदि ने भाग लिया। रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी उपस्थित रहे।

रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने केंद्र पर चीन से स्पर्धा करने वाले लघु उद्योगों को नष्ट करने का आरोप लगाया। कहा कि जीएसटी एवं नोटबंदी के कारण रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं। सरकार छोटे उद्यमियों एवं कारोबारियों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस सबके विरुद्ध खड़े हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ईवीएम, ईडी, सीबीआइ और आयकर के बिना लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हमने चुनाव आयोग से वीवीपैट (वोटर वेरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल) की भी गिनती करने को कहा, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी की गारंटी अमीरों के लिए है जबकि हमारी गारंटी आम आदमी के लिए है।

शरद पवार बोले, देश की स्थिति में बदलाव लाना आवश्यक पेज>>4

सहयोगियों को इस्तेमाल कर छोड़ना कांग्रेस का एजेंडा : मोदी

- आंध्र की जनसभा में बोले पीएम, कांग्रेस-वाईएसआरसीपी को बताया एक जैसा
- कहा- क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्रगति को लेकर आगे बढ़ रहा राजग

लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद रविवार को पीएम नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पहली चुनावी जनसभा की। इसमें तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी उपस्थित रहे। एएनआइ

अमरावती (आंध्र प्रदेश), प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा अपने सहयोगी दलों को इस्तेमाल करके छोड़ देना है। पलनाडु जिले के बोप्पुदी गांव में राजग की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस दोनों एक जैसी हैं और दोनों एक परिवार द्वारा संचालित हैं। उन्होंने कहा, 'राजग में हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का सिर्फ एक ही एजेंडा है- सहयोगियों का इस्तेमाल करो और छोड़ दो। आज कांग्रेस को मजबूरी में आइएनडीआइए बनाना पड़ा, लेकिन उनका सोच वही है। आप देख सकते हैं कि वामदल और कांग्रेस केरल में एक-दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वामदल एक-दूसरे से क्या कह रहे हैं और पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के विरुद्ध कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव से पहले ये लोग अपने फायदे के लिए इस तरह लड़ रहे हैं तो सोचिए चुनाव के बाद वे क्या करेंगे।' प्रधानमंत्री ने कहा कि राजग क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्रगति को लेकर आगे बढ़ रहा है और चुनाव के बाद तीसरे कार्यकाल के दौरान देश कई और बड़े फैसले लेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजग का लक्ष्य विकसित भारत और विकसित आंध्र प्रदेश बनाना है, आंध्र प्रदेश में डबल इंजन की राजग सरकार राज्य में त्वरित विकास सुनिश्चित करेगी।

मोदी ने कहा कि आगामी चुनावों में आंध्र प्रदेश के लोगों ने दो बड़ी चीजों का संकल्प लिया है। पहला केंद्र में राजग की सरकार को वापस लाना और दूसरा- वे यहां की राज्य सरकार से बेहद नाराज हैं और उन्होंने उसे सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है।

'आपका जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है'

सभा को जब जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण संबोधित कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने देखा कि कुछ लोग उस जगह पर चढ़ रहे थे जहां बिजली के तार लगे थे। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए लोगों से अनुरोध किया, 'वहां बिजली के तार हैं। आप लोग वहां क्या कर रहे हैं। आपका जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है। कृपया नीचे आ जाइए। अगर कुछ गलत होता है तो यह हमारे लिए पीड़ादायी होगा।' इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और पवन कल्याण ने अपना भाषण पूरा किया। सभा में तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव जीतकर राजग सरकार बनाएगा। भाजपा-तेदेपा-जसेपा के झंडे अलग-अलग हैं, एजेंडा नहीं।

ईडी ने केजरीवाल को एक ही दिन भेजे दो समन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में 18 मार्च को होना होगा पेश

अरविंद केजरीवाल। फाइल

आबकारी घोटाले से जुड़े नौवें समन में केजरीवाल को 21 मार्च को बुलाया

आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने केजरीवाल को पहली बार एक साथ दो समन भेजे हैं। इनमें एक समन आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जारी कर उनको 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में यह नौवां समन है। वहीं, दूसरा समन दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जारी हुआ है। इस मामले में जारी इस पहले समन में केजरीवाल को बयान देने के लिए 18 मार्च को एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित कार्यालय में कार्यालय में बुलाया गया है।

ईडी का दावा है कि डीजेबी द्वारा अनुबंध में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन को कथित तौर पर दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी आप को चुनावी फंड के रूप में भेजा गया था। फरवरी में ईडी ने इस जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक, आप के एक राज्यसभा सदस्य, एक पूर्व डीजेबी सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के आवासों पर छापेमारी की थी। ईडी का मामला सीबीआइ की एफआइआर पर आधारित है, जिसमें डीजेबी अनुबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी से 38 करोड़ रुपये की राशि लिए जाने की बात कही गई है। आरोप है कि कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है फिर भी इसे अनियमितता कर काम दिया गया। इस मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए लोगों में डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल शामिल हैं। ईडी ने दावा किया कि एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके बोली हासिल की और अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी थी कि कंपनी तकनीकी पात्रता पूरी नहीं करती है। ईडी ने आरोप लगाया कि डीजेबी ने अनुबंध से संबंधित रिश्वत लेने के लिए ठेकेदारों से मिलने वाली राशि को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था।

वहीं, आबकारी घोटाला मामले में भी आप पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने दावा किया है कि 2021-22 की आबकारी नीति से प्राप्त धन का इस्तेमाल पार्टी द्वारा गोवा विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए किया गया था। बता दें कि, ईडी इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल को आठ बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन वह सभी समन को गैरकानूनी बताते हुए पेश होने से इन्कार कर चुके हैं। ईडी ने केजरीवाल को समन गत दो नवंबर, 21 नवंबर, तीन जनवरी, 18 जनवरी, दो फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और चार मार्च को भेजा था।

अब चीनी सेना ने अरुणाचल को बताया चीन का अभिन्न भाग

बीजिंग : अरुणाचल प्रदेश के संबंध में अब चीन की सेना के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उसने अरुणाचल प्रदेश को चीन का परंपरागत (अभिन्न) हिस्सा बताया है। चीनी सेना की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्ति को नकार दिए जाने के बाद आई है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग शियाओगांग ने कहा, शिजांग (तिब्बत का चीनी नाम) का दक्षिणी भाग चीन का परंपरागत हिस्सा है। (पेज-11)

महासमर 2024

बदलते समीकरण से उप्र में रोमांचक होता चुनावी संग्राम पेज>>3

सामाजिक समीकरण साधकर भाजपा को चुनौती देगी कांग्रेस पेज>>3

बिहार में भाजपा-जदयू की ताकत से टकराना राजद के लिए बड़ी चुनौती पेज>>3

उप्र में एक-दूसरे के वार रूम में बैठेंगे सपा और कांग्रेस के नेता पेज>>4

आयोग ने पर्यावरण अनुकूल चुनाव सुनिश्चित करने के दिए निर्देश पेज>>5

दिखाई ताकत

40 घंटे चला आपरेशन, नौसेना ने पकड़े 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरे

हिंद महासागर में फिर दिखा नौसेना का शौर्य, अपहृत जहाज के चालक दल के 17 सदस्य भी बचाए, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आइएनएस कोलकाता का आपरेशन में किया इस्तेमाल, मार्कोस भी उतारे

नई दिल्ली, प्रेट्र : हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का शौर्य एक बार फिर दिखा। भारतीय तट से लगभग 2,600 किमी दूर करीब 40 घंटे तक चलाए गए आपरेशन के दौरान उसने न केवल पूर्व माल्टीज ध्वज वाले अपहृत व्यापारिक जहाज एमवी रुएन के चालक दल के 17 सदस्यों को सुरक्षित रिहा कराया बल्कि 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को भी पकड़ लिया। रुएन को पिछले साल दिसंबर में सोमालिया के तट से समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में लिया था। वह इस पर सवार होकर अन्य व्यापारिक जहाज को निशाना बनाने की फिराक में थे। भारतीय नौसेना ने रविवार को कहा कि यह कार्रवाई हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को मजबूत करने और क्षेत्र में समुद्री डकैती के प्रयासों को विफल करने के उसके संकल्प को दर्शाती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले लगभग सात वर्षों में सोमाली समुद्री डाकुओं से किसी जहाज को पहली बार इस तरह का आपरेशन चलाकर जब्त किया गया है। आपरेशन के दौरान नौसेना ने अपने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आइएनएस कोलकाता, गश्ती जहाज आइएनएस सुभद्रा, लंबे समय तक चलने वाले सी गार्डियन ड्रोन का इस्तेमाल किया। यही नहीं, उसने सी-17 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर मार्कोस (विशिष्ट समुद्री कमांडो) को एमवी रुएन पर एयरड्राप किया।

नौसेना प्रवक्ता ने कहा कि लगभग 10 लाख अमेरिकी डालर की कीमत वाले लगभग 37,800 टन माल से लदे इस जहाज को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाउती समर्थित आतंकियों द्वारा लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर बढ़ते हमलों के बाद रणनीतिक जलमार्गों पर निगरानी रखने के लिए नौसेना ने 10 से अधिक युद्धपोत तैनात किए हैं।

भारतीय तट से 2600 किमी दूर विशेष आपरेशन के अंतर्गत माल्टीज ध्वज वाले जहाज एमवी रुएन से चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकालता भारतीय नौसेना का हेलीकाप्टर। नौसेना ने जहाज से 35 लुटेरों को भी पकड़ा है। प्रेट्र

यूं चली कार्रवाई

नौसेना प्रवक्ता ने कहा कि युद्धपोत आइएनएस कोलकाता ने बुधवार सुबह रुएन को रोका। इस दौरान सी गार्डियन ड्रोन उक्त जहाज के ऊपर उड़ाया गया, उसने जहाज पर समुद्री डाकुओं की पुष्टि की। इस दौरान समुद्री डाकुओं ने ड्रोन को मार गिराया और भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर गोलीबारी की। नौसेना ने बताया कि इसके बाद आइएनएस कोलकाता ने एमवी रुएन जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम और नेविगेशनल सहायता को अक्षम बना कर दिया, जिससे उन्हें जहाज बंद करना पड़ा। इसके बाद सी-17 विमान से मार्कोस कमांडो जहाज पर उतारे गए और उन्होंने समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया और उस पर सवार चालक दल के सदस्यों को भी बचा लिया।

महादेव एप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश समेत 19 के खिलाफ केस

नईदुनिया, रायपुर

▶ लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज केस से बढ़ सकती हैं बघेल की मुश्किलें

भूपेश बघेल (फाइल)। प्रेट्र

एफआइआर के अनुसार, नेता और पुलिस अधिकारी प्रोटेक्शन मनी लेकर कारोबार में कर रहे थे मदद

लोकसभा चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने ईडी की सौंपी रिपोर्ट के आधार पर महादेव सट्टा एप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 19 आरोपितों पर केस दर्ज किया है। एफआइआर के अनुसार, नेता और पुलिस अधिकारी प्रोटेक्शन मनी लेकर कारोबार में मदद कर रहे थे।

बघेल राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ईडी महादेव एप सट्टेबाजी मामले की एक वर्ष से जांच कर रही है। हालिया हुए विधानसभा चुनाव से पहले 6,000 करोड़ रुपये की अवैध आय वाले सट्टेबाजी मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल का नाम जुड़ा था। ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआइआर में छठे नंबर पर बघेल का नाम है।

भूपेश बघेल ने एफआइआर को राजनीतिक साजिश बताया है। रविवार को पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के बावजूद प्रदेश व अन्य राज्यों में महादेव एप सट्टा अभी भी संचालित किया जा रहा है।

कैसे आया भूपेश का नाम पेज>>10

****

मौसम का हाल

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
18 मार्च	31.0	13.0
19 मार्च	32.0	13.0
नोएडा		
18 मार्च	32.0	15.0
19 मार्च	32.0	15.0
गुरुग्राम		
18 मार्च	28.0	13.0
19 मार्च	30.0	13.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

होली पर डीयू में छात्राओं की तैयार होगा कंट्रोल रूम

नई दिल्ली: होली पर दिल्ली विश्वविद्यालय में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। डीयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस मिलकर काम करेंगे। उत्तरी और दक्षिण परिसर में संयुक्त रूप से कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय की गाड़ी परिसर का निरीक्षण करती रहेगी। लड़कियों के कालेज में सुरक्षा अत्यधिक कड़ी रहेगी। पिछले वर्षों में होली पर हुए हुड़दंग को देखते हुए सुरक्षा को कड़ा किया गया है। डीयू के कुलसचिव डा. विकास गुप्ता ने बताया कि परिसर सुरक्षा व्हीकल 'वामिका' से 24 घंटे परिसर में नजर रखी जाएगी। (जासं)

शराब के नशे में हवलदार ने कई वाहनों में मारी टक्कर

नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार रात नशे में धुल दिल्ली पुलिस के हलवादार ने मध्य दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक के बाद एक कई वाहनों में टक्कर मार दी। हादसे के बाद हवलदार ने मौके से भागने की कोशिश की मगर स्थानीय लोगों ने कार का पीछा कर उसे लाल बत्ती के पास रोक लिया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है। (जासं)

गुलाब गैंग के तीन झपटमार और वाहन चोर गिरफ्तार

नई दिल्ली: मध्य दिल्ली पुलिस के एएटीएस स्टाफ द्वारा तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर गुलाब गैंग के नाम से चलने वाले झपटमारों और वाहन चारों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपितों ने अपने हाथों पर गुलाब का टैटू गुदवाया हुआ है। आरोपितों के पास से एक छीनी गई सोने की चेन, छीना हुआ मोबाइल, एक बटन वाला चाकू व पांच दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपित ऋषभ उर्फ बिलोरा पर 26, शौरब उर्फ बंटी पर 23 और दीपक पर नौ मामले दर्ज हैं। (जासं)

13.68 करोड़ से फेज-4 के मेट्रो स्टेशनों पर लगेंगे सोलर पैनल

बिजली की बचत ▶ 27 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों पर लगाए जाएंगे पैनल

2026 के मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगे पैनल, डीएमआरसी ने शुरू की टेंडर प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

35 प्रतिशत बिजली की जरूरतें फिलहाल सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है डीएमआरसी दिल्ली में मेट्रो के संचालन में

एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों के छत पर सोलर पैनल। फाइल

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) बिजली की बचत के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में जुटा है। इसी क्रम में फेज-चार के निर्माणाधीन कारिडोर के सभी एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए डीएमआरसी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 13.68 करोड़ की लागत से 27 एलिवेटेड स्टेशनों के छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिनसे 3.5 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी।

वर्तमान में डीएमआरसी 142 जगहों पर लगे सोलर पैनल से प्रतिदिन 50 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। ये सोलर पैनल विभिन्न एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों व मेट्रो डिपो में लगाए गए हैं। डीएमआरसी रीवा सोलर पावर प्लांट से करीब 120 मेगावाट बिजली लेता है। इस तरह डीएमआरसी मेट्रो में करीब 35 प्रतिशत बिजली की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है।

सौर ऊर्जा का इस्तेमाल मेट्रो के परिचालन में भी हो रहा है, ताकि मेट्रो के परिचालन का खर्च कम हो सके। इसी क्रम में डीएमआरसी ने फेज चार के निर्माणाधीन स्टेशनों पर भी सोलर पैनल लगाने की पहल की है। फेज चार में तीन कारिडोर निर्माणाधीन है, जिसकी कुल लंबाई 65.20 किमी होगी और 45 स्टेशन होंगे, जिसमें से 27 एलिवेटेड व 18 भूमिगत स्टेशन होंगे। इन एलिवेटेड स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जाऐंगे। फेज-चार के ये कारिडोर मार्च 2026 तक बनकर तैयार होंगे। इससे दिल्ली के लोगों को सुविधा होगी। मेट्रो स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने वाली एजेंसी 25 वर्ष तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेगी।

फेज के चार के निर्माणाधीन कारिडोर

कारिडोर	कारिडोर की लंबाई	स्टेशन	एलिवेटेड	भूमिगत
जनकपुरी प.-आरके आश्रम	29.262	22	15	07
एरोसिटी-तुगलकाबाद	23.622	15	04	11
मजलिस पार्क-मौजपुर	12.138	08	08	0
कारिडोर की कुल लंबाई	65.202	45	27	18

केटीआर ने ईडी कार्यालय में बहन के कविता से की मुलाकात

नई दिल्ली, प्रेट्र: बीआरएस नेता केटी रामा राव ने रविवार को ईडी कार्यालय में अपनी बहन के कविता से मुलाकात की। के कविता दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में हैं। 46 वर्षीय कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया। अगले दिन उन्हें विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

कविता को ईडी की हिरासत में भेजते समय कोर्ट ने भाई केटीआर और पति अनिल डी सहित कुछ रिश्तेदारों को रिमांड अवधि के दौरान हर दिन शाम 6-7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए उससे मिलने की अनुमति दी थी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केटीआर ने अदालत द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार कविता से मुलाकात की। के कविता 'साउथ ग्रुप' की प्रमुख सदस्य हैं, जिस पर दिल्ली में शराब लाइसेंस के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। ईडी ने अदालत को रिश्वत की लेन-देन, घोटाले के आरोपितों की बैठकों व आबकारी नीति को बदलवाने में के कविता की भूमिका के बारे में बताया। इन आरोपों की पुष्टि के लिए ईडी ने गवाहों के बयानों का हवाला भी दिया। कहा कि 192 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई करने वाली इंडो स्प्रिट में के कविता की 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी।

केजरीवाल को ईडी ने 'फर्जी' मामले में समन भेजा : आतिशी

आतिशी ने कहा- भाजपा और केंद्र सरकार किसी न किसी तरह केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है

केजरीवाल को समन पर शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी ने की प्रेस कांफ्रेंस। प्रेट्र >>

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आप की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक फर्जी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन भेजा है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि यह डीजेबी (दिल्ली जल बोर्ड) का मामला किस बारे में है। यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की भाजपा की एक साजिश है। उधर, मंत्री के दावे पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। सचदेवा ने केजरीवाल पर बार-बार कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया।

आतिशी ने प्रेसवार्ता कर कहा कि शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के कुछ घंटों बाद केजरीवाल को अगले सप्ताह ईडी के सामने पेश होने के लिए दो समन मिले हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से एक आबकारी नीति मामले से संबंधित है और दूसरा डीजेबी से संबंधित है।

आप नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआइ को अपने ''गुंडों'' के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

एक अन्य प्रेसवार्ता में आप विधायक दिलीप पांडेय ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि ईडी ने खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत के आदेशों का इंतजार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह बजट सत्र के बाद अदालत में पेश होंगे और शनिवार को वह अदालत के सामने पेश हुए।

उन्होंने कहा कि ईडी का बार-बार समन भेजना भाजपा की हताशा को दर्शाता है। वह किसी तरह दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करना चाह रही है।

सर्पविष तस्करी मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा

20 एमएल स्नेक वेनम के अलावा कोबरा, अजगर, घोड़ा पछाड़ समेत मिले थे नौ सांप

मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फार एनिमल के अधिकारी ने दर्ज कराई थी एफआइआर

गिरफ्तारी के बाद एल्विश यादव को नोएडा में जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एएनआइ

बिग बास ओटीटी-2 जीतने के बाद से सुर्खियों में आए गुरुग्राम के यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सर्पविष की तस्करी के मामले में एल्विश को एनडीपीएस की गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

इस मामले में भाजपा सांसद मेनका गांधी द्वारा संचालित संस्था पीपुल्स फार एनिमल (पीएफए) की ओर से एफआइआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें एल्विश यादव का नाम भी शामिल था। 3 नवंबर, 2023 को पुलिस ने पांच लोगों को पकड़ा था, जिनके पास से 20 मिलीलीटर स्नेक वेनम, पांच कोबरा, एक अजगर, दो दोमुही, एक घोड़ा पछाड़ सांप बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपितों को उसी समय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था, लेकिन एल्विश के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर रही थी। डीसीपी विद्या सागर मिश्र ने बताया कि रविवार दोपहर एल्विश को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कराने के बाद उसे सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। आरोप है कि एल्विश यादव नोएडा-एनसीआर के फार्म हाउसों में अन्य यूट्यूबर के साथ स्नेक वेनम के साथ वीडियो शूट कराता है।

कुत्ते पर तेजाब फेंकने के मामले में आरोपित को दिया दोषी करार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: तेजाब डालकर कुत्ते को मारने की कोशिश करने के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपित महेंद्र सिंह के खिलाफ पेश की सामग्री व गवाहों की गवाही के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा है।

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि आरोपित द्वारा तेजाब फेंकने के कारण ही कुत्ता घायल हुआ था। अदालत ने कहा कि आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा-429 (जानवरों को जहर देकर मारने का अपराध) के तहत दोषी करार दिया जाता है। यह मामला वर्ष 2020 का है। पहाड़गंज निवासी शिकायतकर्ता ओमवती ने प्राथमिकी कराई थी कि आरोपित ने कुत्ते पर सात फरवरी 2020 को तेजाब फेंक दिया था। उन्होंने जब कुत्ते को डाक्टर को दिखाया, तो बताया कि तेजाब के कारण कुत्ते की आंखों को नुकसान हुआ है।

गाजियाबाद में प्रार्थना सभा में हिंदुओं का मतांतरण, अमेरिकी नागरिक थे मौजूद

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद

ईसाइयों पर मतांतरण कराने का आरोप, हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस से की शिकायत

सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। जांच की गई तो मतांतरण का मामला सामने नहीं आया है।
- निमिष पाटिल, पुलिस उपायुक्त, ट्रांस हिंडन

कौशांबी के डी ब्लाक में चल रही ईसाइयों की प्रार्थना सभा में हिंदुओं का मतांतरण कराने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभा में लोगों से पूछताछ कर कागजों की जांच की। सभा में अमेरिका सहित अन्य देश के नागरिक भी मौजूद थे।

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। कौशांबी में डी ब्लाक के बी 12 की बिल्डिंग में एक हाल बुक था। रविवार सुबह नौ बजे से इसमें प्रार्थना सभा कराने की तैयारी शुरू हुई। सुबह 11:15 बजे सभा शुरू हुई। इसमें 100 से ज्यादा लोग पहुंचे। सभा आयोजित होने से पहले इसका प्रचार प्रसार हुआ था। करीब तीन बजे हिंदू संगठन के लोगों को इस सभा के बारे में पता चला। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को इसकी सूचना दी।

मौके पर सहायक पुलिस आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह व कौशांबी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक पुलिस ने सभा में दस्तावेजों की छानबीन की। विहिप विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ब्रह्म कुमार गुप्ता ने पुलिस को दी गई शिकायत में लिखा है कि लोगों को बरगलाया गया। इसके लिए पर्चे छपवाए गए। इसमें लिखा गया कि मरे हुए लोग फिर से जिंदा होंगे। अपने धर्म को सबसे ऊपर व अन्य धर्मों को नीचा दिखाया गया है। इसमें गरीब व निर्बल लोग भी मौजूद थे। बिना अनुमति के सभा का आयोजन हुआ। इसकी सूचना प्रशासन को नहीं थी। लोगों का ब्रेन वाश कर मतांतरण कराया जा रहा था।

दवाओं की आनलाइन बिक्री पर नीति बनाने को केंद्र को दिया आखिरी मौका

जासं, नई दिल्ली : दवाओं की आनलाइन बिक्री पर नीति बनाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आखिरी मौका दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि सुनवाई की अगली तारीख से पहले मसौदा नीति तैयार नहीं होती है, तो इस अदालत के पास मामले को आगे बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।

अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नीति तैयार करने के लिए चार महीने का अंतिम अवसर दिया। केंद्र ने पीठ से कहा कि यह मुद्दा जटिल है और दवाओं की बिक्री के तरीके में किसी भी संशोधन के दूरगामी परिणाम होंगे। अदालत ने उक्त निर्देश आनलाइन दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और ड्रग्स और कास्मेटिक्स नियमों में और संशोधन करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मसौदा नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले में अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।

आप-कांग्रेस एक दूसरे को जुटा रहे समर्थन

वी के शुक्ला, नई दिल्ली

18 प्रतिशत मत मिले थे पिछले लोस चुनाव में आम आदमी पार्टी को

22 प्रतिशत मतों से संतोष करना पड़ा था कांग्रेस को

कांग्रेस और आप के चुनाव चिन्ह। फाइल

राजनीति के अखाड़े में इस बार आप और कांग्रेस के सूरमा एकजुट होकर उतर रहे हैं। दलों के गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच गठबंधन कराने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए आप अपने कार्यकर्ताओं को हर मतदाता तक पहुंचने की मंत्र दे रही है, ताकि कांग्रेस के कोर वोटर को आप के साथ जोड़ भाजपा को चुनौती दी जा सके। पिछले लोकसभा चुनाव में आप को 18 प्रतिशत मत मिले थे, जबकि कांग्रेस को 22 प्रतिशत मत मिले थे। ऐसे में आप के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि यह 40 प्रतिशत वोट एकजुट होकर गठबंधन के पक्ष में मतदान करते हैं तो राजधानी में मुकाबला कांटे का हो सकता है।

पिछले साल राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए यह पहला चुनाव है। पिछले दो लोकसभा चुनाव में आप बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी, हालांकि 2014 की अपेक्षा 2019 के चुनाव में आप का मत प्रतिशत कम हुआ है। 2014 में आप ने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसे दिल्ली में 32 प्रतिशत मत मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आप को 18.1 प्रतिशत मत मिले थे। इस बार आप ने गठबंधन में नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं।

दिल्ली की सातों सीटों की बात करें, तो पिछली बार यानी 2019 में आप दो सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। उसे दक्षिणी दिल्ली सीट पर 26.34 प्रतिशत वोट मिले थे, यहां से राघव चड्ढा चुनाव मैदान में उतरे थे, वहीं उत्तर-पश्चिमी दिल्ली सीट पर भी आप दूसरे नंबर पर रही थी। इस सीट पर आप को 21.01 प्रतिशत वोट मिले थे। आप ने दिल्ली में जिस गणित के आधार पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उसके अनुसार दिल्ली में दोनों को मिलाकर कुल मत प्रतिशत 40 के करीब बैठता है। आप के नेता मान रहे हैं कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार अच्छी स्थिति में है।

लोकसभा चुनाव 2019 में किस सीट पर आप को कितने मिले मत

सीट	कुल मत	मत प्रतिशत
चांदनी चौक	144551	14.74
उत्तर-पश्चिमी	294760	21.01
पश्चिमी दिल्ली	251872	17.46
नई दिल्ली	150342	16.33
दक्षिणी दिल्ली	319971	26.34
उत्तर-पूर्वी दिल्ली	190856	13.05
पूर्वी दिल्ली	219328	17.43

हाईटेक लोकसभा चुनाव में लोगों के लिए एप बनेंगे मददगार

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

जीवन के हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही चुनाव भी अब हाईटेक हो गया है। इस लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में नाम शामिल करने से लेकर चुनाव प्रबंधन तक के कार्य के लिए करीब दस मोबाइल एप इस्तेमाल होंगे, जो मतदाताओं के साथ-साथ प्रत्याशियों के लिए भी मददगार होंगे।

छह एप का इस्तेमाल मतदाता कर सकते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वोटर हेल्पलाइन एप है। इस एप के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आनलाइन आवेदन दे सकते हैं। मतदाता सूची में आनलाइन नाम दे सकते हैं। ई-मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो इस एप के माध्य से ही शिकायत भी की जा सकती है। चुनाव से संबंधित ताजा जानकारी भी मिल सकती है। इसलिए यह एप मतदाताओं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसी तरह सुविधा कैंडिडेट एप के मध्यम से उम्मीदवार चुनावी सभा, रैली इत्यादि के लिए आनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

चुनाव में ये एप होंगे इस्तेमाल

1. वोटर हेल्पलाइन : मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से लेकर चुनाव से संबंधित सभी सेवाओं के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप के माध्यम से लोग मतदाता सूची में अपना नाम आसानी से देख सकते हैं। नाम शामिल नहीं होने या कट जाने पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए इस एप से ही आनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। मतदान के दिन इस एप से वोटर स्लिप तैयार कर डाउनलोड किया जा सकता है। इसका प्रिंटआउट निकालकर मतदाता अपने साथ मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। इस एप के माध्यम से अपने मतदान केंद्र की जानकारी भी मिल सकती है।

2. सक्षम-ईसीआइ: इस एप का दिव्यांग मतदाता इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आनलाइन आवेदन दे सकते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मतदान के दिन व्हील चेयर के लिए पहले से अनुरोध देकर बुक कर सकते हैं।

3. नो योर कैंडिडेट: इस एप से कोई भी व्यक्ति या मतदाता संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम, शिक्षा, उनके आपराधिक रिकार्ड इत्यादि की जानकारी ली जा सकती है। इसलिए मतदाता इस एप का इस्तेमाल प्रत्याशियों के बारे में जानकारी लेकर उम्मीद के अनुसार मतदान के लिए फैसला लेने में इस्तेमाल कर सकते हैं।

चुनाव के लिए मोबाइल एप। फाइल

4. सी-विजिल एप : इस एप से लोग चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में चुनाव आयोग को शिकायत देकर सूचित कर सकते हैं। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित कोई चीजें दिखने पर उसका वीडियो या फोटो भी अपलोड किया जा सकता है।

5. ई-लर्निंग : मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस एप का इस्तेमाल किया जा रहा है।

6. वोटर टर्न आउट : मतगणना के समय यह एप सक्रिय होता है। इस एप के माध्यम से मतगणना से संबंधित जानकारी ली जा सकती है।

उम्मीदवारों के लिए

7. सुविधा कैंडिडेट: इस एप के माध्यम से उम्मीदवार चुनावी सभा, रैली इत्यादि की स्वीकृति के लिए आनलाइन आवेदन दे सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया में भी ये एप मददगार होंगे।

चुनाव प्रबंधन के लिए तीन एप

इनकोर (ईएनसीओआरई), ईएसएमएस (इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम) व आब्जर्वर एप जैसे मोबाइल एप का इस्तेमाल चुनाव प्रबंधन के लिए अधिकारी कर सकेंगे।

छूटेंगे पसीने

मतदान के समय होगी गर्मी, स्कूलों की हो चुकी होंगी छुट्टियां, गर्मी में छुट्टियों के दौरान बहुत लोग चले जाते हैं दिल्ली से बाहर

दिल्ली में लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाना होगी चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

25 मई को दिल्ली में होगा सात सीटों पर लोकसभा के लिए मतदान

लोस चुनाव के दौरान करना होगा मतदान। फाइल

दिल्ली में एक तो पहले से ही लोग मतदान के लिए कम निकलते हैं। इस वजह से पिछले नौ लोकसभा चुनावों में दिल्ली में मतदान राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के बाद इस बार दिल्ली में मतदान बढ़ा पाना सीईओ कार्यालय के लिए और भी बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि मतदान के दौरान एक तो भीषण गर्मी होने की संभावना है। साथ ही स्कूलों की छुट्टियां भी हो चुकी होंगी। गर्मी की छुट्टियों में काफी संख्या में लोग दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। ऐसे में मतदान बढ़ाने के लिए सीईओ कार्यालय को पहले से अधिक प्रयास करने पड़ेंगे।

आंकड़े भी बताते हैं ज्यादा गर्मी हो या बरसात, मतदान पर मौसम के मिजाज का भी खासा असर पड़ता है। दिल्ली में मई में जब भी दिल्ली में चुनाव हुए तब मतदान ज्यादा कम हुआ। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 10 अप्रैल को मतदान हुआ था तब 65.10 प्रतिशत मतदान हुआ था। पिछले लोकसभा चुनाव में 12 मई को मतदान हुआ था तब दिल्ली में 60.6 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो वर्ष 2019 के मुकाबले साढ़े चार प्रतिशत कम था। इसके पहले मई में हुए चुनावों में मतदान और भी कम रहा था। इस बार दिल्ली में 25 मई को मतदान होगा। तब तक ज्येष्ठ माह की तपिश शुरू हो जाएगी। इस बार सरकारी स्कूलों में 11 मई से स्कूलों में छुट्टियां होंगी। निजी स्कूलों में भी 20 मई तक छुट्टी हो जाती हैं। ऐसे में यदि मतदान से पहले लोग गर्मी की छुट्टियों से बाहर निकलें तो मतदान प्रतिशत बढ़ पाना आसान नहीं होगा। यह सोचकर चुनाव से जुड़े अधिकारियों के अभी से ही पसीने आने लगे हैं। वैसे दिल्ली में मतदान होने में अभी दो माह से अधिक समय है। इसलिए सीईओ कार्यालय के पास मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी पर्याप्त समय है।

11 मई से सरकारी स्कूलों में और 20 मई से निजी स्कूलों में शुरू होंगी छुट्टियां

पिछले लोकसभा चुनावों में मतदान

वर्ष	देश में मतदान	दिल्ली में मतदान	दिल्ली में मतदान की तारीख
2019	67.4	60.6	12 मई
2014	66.44	65.10	10 अप्रैल
2009	58.13	51.85	07 मई
2004	58.07	47.09	10 मई

****

80 की उम्र में पुरुषों से अधिक महिला मतदाता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राजधानी का लिंगानुपात भले ही एक हजार पुरुषों की तुलना में 932 हो, लेकिन 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं में महिलाएं पुरुषों पर भारी हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में 1,47,18,119 मतदाताओं में से 2,63,771 मतदाता ऐसे हैं जो 80 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं। खास बात यह है कि यहां पर भी महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से ज्यादा हैं। दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2,63,771 मतदाता 80 से अधिक आयु वाले हैं। इसमें पुरुषों की अपेक्षा में इस आयु श्रेणी में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसमें 1,34,705 महिला मतदाता हैं जबकि 1,29,059 पुरुष मतदाता हैं।

दिल्ली में सात लोकसभा क्षेत्रों में 80 से अधिक आयु वर्ग में सर्वाधिक मतदाता पश्चिमी दिल्ली में है। यहां पर इस श्रेणी में 50,208 मतदाता हैं। इसमें 25,523 महिलाएं तो 24,683 पुरुष हैं।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

1950 टोल फ्री नंबर पर मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में

बदलते समीकरण से उप्र में रोमांचक होता चुनावी संग्राम

दलबदलुओं से बदलता दिख रहा है सीटों का गणित, जमीनी समीकरण दुरुस्त करने की मुहिम में सपा-कांग्रेस गठबंधन

अजय जायसवाल ● लखनऊ

उत्तर प्रदेश में अभी सभी राजनीतिक दल अपने पूरे प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सके हैं, पर बदलते समीकरणों से चुनावी माहौल रोचक होता जा रहा है। राजग में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के शामिल होने से जहां उसकी ताकत में इजाफा हुआ है, वहीं आइएनडीआइए में सपा और कांग्रेस को आप की बैसाखी हासिल हुई है। बसपा इस पूरे खेल में एक्सट्रा प्लेयर के रूप में खेलेगी और चुनावी परिणाम का रुख तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। गठबंधन और दलबदलुओं के इधर-उधर होने से लोकसभा सीटों के समीकरण बन-बिगड़ रहे हैं और राज्य का सियासी संग्राम रोमांचक होता जा रहा है। सपा ने तृणमूल कांग्रेस के लिए एक सीट छोड़कर नई संभावनाओं को जन्म दिया है।

2014 के लोकसभा चुनाव में सहयोगी दल संग 73 सीटें जीतने वाली भाजपा को पिछले चुनाव में विरोधी विचारधारा वाले सपा-बसपा व रालोद के गठजोड़ से झटका लगा था। सहयोगी संग उसकी सीटें घटकर 64 ही रह गईं थीं। दो वर्ष पहले के विस चुनाव में भी सपा की पहले से बेहतर स्थिति को देखते हुए भाजपा ने अबकी लोस चुनाव में उतरने से पहले न केवल बूथ स्तर तक मजबूत संगठन खड़ा किया है बल्कि उसने विस चुनाव में सपा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताकत रहे रालोद और पूर्वी उत्तर प्रदेश से सुभासपा को अपने पाले में खड़ा कर लिया है। हाल ही में सुभासपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने के साथ ही सपा से भाजपा में वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान जैसे पिछड़े वर्ग के नेता भी मंत्री पद से नवाजे गए हैं। अपनी ताकत बढ़ाने के साथ ही दूसरों में सेंधमारी कर उन्हें कमजोर करने की रणनीति पर काम करते हुए भाजपा की नजर विरोधियों के सांसदों, पूर्व सांसदों व विधायकों के साथ ही अन्य प्रभावशाली नेताओं पर भी है।

लोस चुनाव 2019 में उप्र की दलगत स्थिति

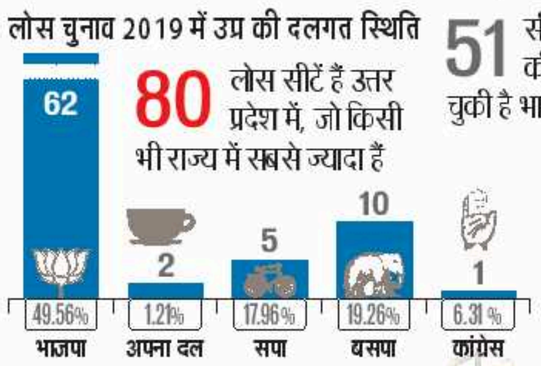

80 लोस सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जो किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं

51 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है भाजपा

17 सीटें मिली हैं कांग्रेस को सपा से गठबंधन के तहत

41 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से हाथ पर हाथ धरे बैठी है सपा

2022 के विस चुनाव में प्रमुख दलों की स्थिति

पार्टी	सीटें	मत प्राप्त किए (% में)
भाजपा	255	41.6
सपा	111	32.3
अपना दल (एस)	12	1.6
रालोद	8	2.9
निषाद पार्टी	6	0.9
अन्य	11	20.7

ये नेता अब कमल के साथ: भाजपा ने बसपा सांसद रितेश पाण्डेय को पार्टी में शामिल करने के साथ ही उन्हें आंबेडकरनगर से प्रत्याशी बना दिया है। वाराणसी से कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्र, बसपा के पूर्व सांसद नरेन्द्र सिंह कुशवाहा, सपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य बनवारी लाल, कानपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय कपूर जैसे दूसरी पार्टियों के नेता अब 'कमल' के साथ हैं।

सहयोगियों को दी जाने वाली सीटों पर सबकी नजर: राजग के सहयोगी अपना दल (एस) व निषाद पार्टी को भी साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरने वाली भाजपा 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इनमें 44 वर्तमान सांसद हैं। माना जा रहा है कि छह सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ने के अलावा 23 और पर वह खुद लड़ेगी। इनमें 20 मौजूदा सांसदों में से ज्यादातर के टिकट कट सकते हैं। इसलिए सभी को प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है। सबकी नजर इस पर भी है कि भाजपा सहयोगियों को कौन सी सीटें देगी?

कांग्रेस अब तक घोषित नहीं कर सकी प्रत्याशी: महीनों की तल्ख बयानबाजी के बाद पिछले महीने जैसे-तैसे कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो हुआ, लेकिन इस बीच रालोद ने साथ छोड़ दिया। रालोद के किनारा करने से गठबंधन की ताकत घटने का ही नतीजा रहा कि तीन हफ्ते से ज्यादा गुजरने के बाद भी कांग्रेस अपने कोटे की 17 सीटों में से एक पर भी अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है। पुराने कांग्रेसी भी चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में वे देख चुके हैं कि जमीनी समीकरण दुरुस्त न होने से सपा-कांग्रेस का गठबंधन कोई कमाल नहीं दिखा सका था। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां एक सीट, वहीं वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ दो सीट जीत सकी थी।

बसपा के चलते बिगड़ सकता है सपा-कांग्रेस का खेल: कांग्रेस से गठबंधन का इंतजार किए बिना ही प्रत्याशियों की सूची जारी करने में सबसे आगे रहने वाली सपा भी 41 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हालांकि, उसने एक सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़कर बंगाल में अपनी उपस्थिति की संभावनाएं भी खड़ी की हैं। जिस तरह से बसपा अबकी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने पर अड़ी है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान सपा-कांग्रेस गठबंधन को ही होने के आसार हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर गठबंधन का खेल बिगाड़ने के लिए बसपा, मुस्लिम प्रत्याशियों को तवज्जो दे रही है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बसपा के अब तक तय किए गए नौ प्रत्याशियों मे से पांच मुस्लिम समुदाय के ही हैं। आम आदमी पार्टी (आप)ने इस बार चुनाव में प्रत्याशी न उतारने का निर्णय किया है, हालांकि, उसके नेता आइएनडीआइए के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते दिखाई देंगे।

सामाजिक समीकरण साधकर भाजपा को चुनौती देगी कांग्रेस

रविंद्र बड़थ्वाल ● देहरादून

- हरिद्वार और नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय सीटों पर उम्मीद
- मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग का मिल सकता लाभ

टिकट की टिकटिक

उत्तराखंड की कुल पांच में से दो संसदीय सीट हरिद्वार और नैनीताल-ऊधम सिंह नगर ऐसी हैं, जहां कांग्रेस जीत की संभावनाएं बेहतर मान रही है। इस भरोसे के पीछे सामाजिक समीकरण हैं। अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ मुस्लिम मतदाताओं की संख्याबल के सहारे जीत का गणित बैठा रही पार्टी के सामने बड़ी चुनौती भाजपा के कब्जवर प्रत्याशी हैं। हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत व नैनीताल-ऊधमसिंहनगर सीट पर रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। इससे बदले समीकरण में कांग्रेस को ऐसे दमदार प्रत्याशियों की तलाश है, जो भाजपा को अच्छी टक्कर दे सकें।

उत्तराखंड की पांचों संसदीय सीटों पर जातीय और क्षेत्रीय राजनीति की बिसात पर ही मुकाबला होना है। कांग्रेस की रणनीति के केंद्र में यही सामाजिक समीकरण हैं। पार्टी ने अभी तक पांच में से तीन सीटों गढ़वाल, टिहरी और अल्मोड़ा पर प्रत्याशी तय किए हैं। ठाकुर मतदाता बहुल गढ़वाल संसदीय सीट से पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी गणेश गोदियाल को टिकट दिया है। टिहरी संसदीय सीट पर राज परिवार की माला राज्य लक्ष्मी शाह के मुकाबले ठाकुर प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला को उतारा गया है। अल्मोड़ा सुरक्षित सीट पर अनुसूचित जाति से पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पर्वतीय बहुल इन तीनों सीटों पर राजनीतिक दलों का ज्यादा जोर ठाकुर और ब्राह्मण के साथ अन्य जातियों को साधने पर रहता है। कांग्रेस के साथ ही भाजपा ने भी इन्हीं समीकरणों के साथ संतुलन बैठाते हुए प्रत्याशी घोषित किए हैं।

कांग्रेस के लिए जनाधार को वापस पाने की चुनौती: कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में सबसे बड़ी चुनौती खोए हुए जनाधार को वापस पाने की है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं आ सकी। कभी पर्वतीय बहुल सीटों पर वर्चस्व रखने वाली पार्टी अब संघर्ष करने को मजबूर है। ऐसे में पार्टी ने अपनी जीत की उम्मीदों को देखते हुए हरिद्वार और नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है। वर्ष 2022 के विस चुनाव में इन क्षेत्रों के अंतर्गत विस सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। विशेष रूप से हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की 14 विस सीटों में से मात्र छह पर भाजपा विधायक हैं, जबकि आठ पर विपक्षी दल और निर्दलीय काबिज हैं। इनमें कांग्रेस के पास पांच सीट हैं, जबकि बसपा के पास दो। हरिद्वार संसदीय सीट पर वर्तमान सामाजिक समीकरणों का सबसे अधिक लाभ कांग्रेस को हुआ है। इसके अंतर्गत सभी सुरक्षित सीट पर कांग्रेस और मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय को जीत मिली। हरिद्वार सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा-कांग्रेस के बीच होना है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि वह भाजपा के इस किले में सेंधमारी कर सकती है। नैनीताल-ऊधमसिंहनगर सीट पर भी लगभग 16 प्रतिशत मुस्लिम, 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति और पांच प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। ठाकुर 27 व ब्राह्मण मतदाता 17 प्रतिशत हैं। मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समेत जातीय समीकरण को कांग्रेस अपने लिए बेहतर आंक रही है। पार्टी इन दोनों सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों की तलाश कर रही है, जिनसे इन समीकरण को साधकर भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके।

5 सीटें हैं उत्तराखंड में लोकसभा की, सभी पर भाजपा है काबिज

14 विस सीटों में से मात्र छह पर भाजपा विधायक जीते हैं हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में

कांग्रेस अपने खोए जनाधार को पाने को जोर लगा रही है। लोस चुनाव में जीत की रणनीति इसे ध्यान में रखकर बना रहे।

यशपाल आर्य, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए पार्टी शीघ्र शेष दो सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित करेगी।

करन माहरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

अतीत के आईने से

इन मुश्किलों में हुआ पहला आम चुनाव

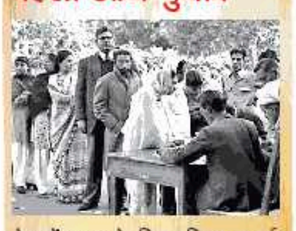

देश में चुनाव के लिए प्रक्रिया जुलाई 1948 में ही शुरू हो गई थी, मगर संविधान न होने से चुनाव कराना आसान नहीं था। ऐसे में पहले 26 नवंबर, 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी, 1950 को इसे लागू किया गया। इसके बाद भारत को चुनाव कराने के लिए नियम और उप-नियम मिले। हालांकि, यह एक असाधारण सफर की सिर्फ शुरुआत थी। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन किया गया।

चुनाव चिह्न, मतपत्र और अधिकारियों को प्रशिक्षण

चुनाव के लिए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाने थे, जो 1951 में हो पाया। फिर देश की ज्यादातर अशिक्षित आबादी के लिए, सभी दलों के चुनाव चिह्न डिजाइन करने, मतपत्र और मतदान पेटी बनाने से जुड़ी समस्याएं भी सामने खड़ी थीं। मतदान केंद्र भी बनाए जाने थे, साथ ही यह भी पक्का करना था कि केंद्रों के बीच सही दूरी हो। मतदान अधिकारियों को नियुक्त कर प्रशिक्षण देना भी जरूरी था, क्योंकि चुनाव पहली बार हो रहे थे तो यह सबसे बड़ी समस्याओं में से एक था।

...और फिर भारत बना विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र

भारत में स्वतंत्रता के पांच वर्ष बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव के समय देश की जनसंख्या करीब 36 करोड़ थी। मतदान करने के लिए उसी उम्र को योग्य माना गया, जो उस समय विश्व भर में अपनाई जा चुकी थी। ऐसे में तय हुआ कि 21 वर्ष और उससे ज्यादा आयु वाले सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिले। इसके बाद जब चुनाव हुए तो देश के करीब 17.3 करोड़ नागरिक मतदान करने की योग्यता रखते थे। और फिर जब चुनाव हुए तो चुनाव योग्य आबादी में से 45.7% मतदाता पहली बार मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। इसके साथ ही भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया था। जहां लोगों ने, लोगों के लिए एक सरकार चुनी।

महासमर की अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

आम चुनाव 2024: महिलाएं, युवा, किसान और गरीब तय करेंगे चुनाव की दिशा

देश में जब विपक्ष जाति आधारित राजनीति कर सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जाति की नई परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए चार ही जातियां हैं और वे हैं-युवा, किसान, महिलाएं और गरीब। महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के जीवन को आसान बना कर ही विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ चुनावी महासमर की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। उक्त मतदाता आगामी चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी संख्या कितनी है और इनके मुद्दे क्या हैं। **महेंद्र सिंह की रिपोर्ट**

भारत को महाशक्ति बनाएंगे युवा

96.8 करोड़ हैं कुल मतदाता हैं देश में

21.5 करोड़ मतदाताओं की उम्र है 29 साल से कम

1.84 करोड़ मतदाता हैं 18 से 19 वर्ष की उम्र के

युवा मतदाताओं के मुद्दे
- कम लागत में उच्च शिक्षा की सुविधाएं
- शोध एवं नवाचार के लिए सरकारी मदद और प्रोत्साहन
- उद्यमिता के लिए कर्ज की उपलब्धता

गरीबों को मदद की जरूरत

16.1% लोग गरीब हैं भारत की कुल आबादी में

गरीबों के मुद्दे
- स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता
- सस्ती स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक आसान पहुंच
- रोजगार

महिलाएं: आधी आबादी का सशक्तीकरण जरूरी

47 करोड़ हो गई है महिला मतदाताओं की संख्या

43.8 करोड़ थी महिला मतदाताओं की संख्या 2019 में

पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने वोट दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में

67.2% महिला मतदाताओं ने वोट दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में

5.1% बढ़ी है महिला मतदाताओं की संख्या 2019 से 2022 के दौरान

महिलाओं के मुद्दे
- महिला सुरक्षा
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच
- सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलने चाहिए
- कार्यालय में मिले काम का बेहतर माहौल

किसान

11.3 करोड़ किसान पंजीकृत हैं पीएम किसान योजना में

किसानों के मुद्दे
- उपज का लाभकारी मूल्य मिले
- उत्पाद बेचने के लिए नजदीक बाजार उपलब्ध हों
- आधुनिक तरीके से खेती के लिए जरूरी तकनीक और सलाह मुहैया होनी चाहिए

वोट-ए-थान...

आगामी आम चुनावों में 100 प्रतिशत मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा बेंगलुरु में रविवार को जागरूकता अभियान वोट-ए-थान का आयोजन किया गया। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री के साथ वोटिंग साइन बोर्ड के पास से गुजरता एक प्रतिभागी ● एएफपी

बिहार में भाजपा-जदयू की ताकत से टकराना राजद के लिए बड़ी चुनौती

दलों का दमखम

सुनील राज ● पटना

नरेन्द्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ●

सुनहरे दौर के बाद अचानक आई मुसीबत से बचने के लिए लालू प्रसाद ने ढाई दशक पहले जिस राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का गठन किया था, उसकी कमान अब तेजस्वी यादव के हाथ में है। लालू के बिना राजनीति के प्रथम पाठ में ही तेजस्वी को 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था। राजद का खाता तक नहीं खुल सका। किंतु कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद को उभारने का श्रेय भी मिला। चुनौतियों के साथ फिर बिसात सज रही है। बिहार में विपक्ष की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी बैठे हैं, लेकिन भाजपा-जदयू के मजबूत किले को ध्वस्त करना आसान नहीं होगा।

तेजस्वी के पक्ष में अच्छी बात है कि राजनीति में लालू पुत्र की छवि से निकलकर उन्होंने परिपक्व नेता के रूप में पहचान बना ली है। कमान मिलने के बाद पार्टी की छवि भी बदलने का प्रयास किया है। राजद अब पुरानी पार्टी नहीं रही, जो जाति समीकरण के दायरे में अपनी जमीन मजबूत करेगी। एम-वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण पर चलने वाली पार्टी में तेजस्वी ने बाप (बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर यानी गरीब) तो जोड़ा ही, इसमें विकास का एजेंडा भी शामिल कर दिया।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में 17 महीने बिताने वाले राजद ने नीतीश कुमार के अलग होते ही अपना चुनावी एजेंडा तय कर लिया था। जदयू और भाजपा सरकार की घेराबंदी के लिए 17 वर्ष बनाम 17 महीने में हुए काम को राजद ने अपना आधार बनाया है। 17 महीने की महागठबंधन सरकार में हुए कामों की जानकारी बिहार में जन-जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने जन-विश्वास यात्रा तक निकाली और बिहार में घूम-घूमकर यह बताया कि जितने काम 17 महीने में राजद ने करा दिए, उतने काम 17 वर्ष की राजग सरकार नहीं करा पाई। पांच लाख युवाओं को नौकरी, बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने समेत अन्य कार्यों की बदौलत राजद यह बताने में सफल रहा है कि उसके लिए जाति समीकरण जरूरी है तो विकास-रोजगार भी महत्वपूर्ण हैं। अपने इस एजेंडे को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए राजद आइएनडीआइए के साथ मिलकर चुनाव मैदान में जाएगा।

आइएनडीआइए में सीटों के बंटवारे में पेच

बिहार में आइएनडीआइए में सीटों के बंटवारे में पेच है, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी राजद के खिलाफ मुखर होने की स्थिति में नहीं। वाम दलों को लेकर राजद का नजरिया लचीला है। माना जा रहा कि पिछली बार 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाला राजद 28 सीटें खुद रखेगा। पार्टी का प्रयास होगा राजग को विकास के एजेंडे पर घेरना व अपनी पिच पर खेलने को मजबूर करना।

अतीत के झरोखे

कभी बीहड़ के फरमान पर डोलती थी राजनीति

- चुनाव से पहले 'वोट पड़ेगा.....पर, नहीं तो लाश मिलेगी घाटी पर- जैसे नारे गूंजते थे
- अब चुनाव में इन डकैतों का कोई नामलेवा नहीं, ज्यादातर गिरोह का हो चुका सफाया

जागरण टीम, कानपुर: लोकतंत्र के इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि एक दौर वह भी था, जब बीहड़ (जंगली इलाका) से निकले फरमान पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सियासत डोल जाती थी। चुनाव से पहले 'वोट पड़ेगा.....पर, नहीं तो लाश मिलेगी घाटी पर-जैसे नारे गूंजते थे। औरैया, इटावा, बांदा, जालौन व चित्रकूट तक दुर्दांत डकैतों का सियासत में हस्तक्षेप रहा। अब चुनाव में इन डकैतों का कोई नामलेवा नहीं है। या तो इनके गिरोहों का सफाया हो चुका है या इनके सदस्य सलाखों के पीछे हैं। पढ़िए कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की सियासत में डकैतों के दखल पर रिपोर्ट...

चित्रकूट का नाम आते ही वे जंगल याद आते हैं, जहां श्रीराम ने वनवास के दौरान विचरण किया था। चुनावी दौर में डकैतों की वजह से इनकी याद ताजा हो जाती है। डकैत दद्दुआ की 1982 से 2000 तक करीब 52 गांवों में तूती बोलती थी। वह विधानसभा व लोकसभा चुनाव का रुख तय करता था। पहले उसका हाथ कम्युनिस्ट पार्टी की पीठ पर था, पर राजनीतिक गुरु के कहने पर बसपा के पक्ष में माहौल तैयार करने लगा। पाठा के जंगलों में हाथी दौड़ा। 2004 में उसने दल बदल लिया और पूरे परिवार को सपा की लाल टोपी पहना दी। भाई बाल कुमार पटेल, बेटा वीर सिंह पटेल और भतीजे राम सिंह पटेल साइकिल की सवारी कर सांसद, विधायक बन गए। बुंदेलखंड में मुलायम सिंह की राजनीति की फसल खड़ी हो गई। इससे दद्दुआ और बसपा के बीच बैर का बीज पनप उठा। फिर दौर आया 2007 के विस चुनाव का। इसमें बसपा की सरकार बनी और दद्दुआ के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 22 जुलाई, 2007 को एसटीएफ से मुठभेड़ में दद्दुआ का अंत हो गया। दद्दुआ के अलावा इनामी डकैत ठोकिया, रागिया, बलखड़िया, बबली कोल और गौरी यादव का भी फरमान चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, सतना, रीवा, पन्ना और छतरपुर तक चलता था। फरमान आते ही चुनावी माहौल बदल जाता था। हालांकि, अब पूरा इलाका दस्यु विहीन हो चुका है। 2014 लोस चुनाव डकैतों के दखल के बिना पूरा हुआ था, तब से ग्राम प्रधान से लेकर सांसद और विधायक तक के चुनाव में लोग खुलकर मतदान कर रहे हैं।

ये गिरोह रहे हैं सक्रिय

दद्दुआ, निर्भय गुर्जर, ठोकिया, रागिया, बलखड़िया, बबली कोल, लालाराम, श्रीराम, फूलनदेवी, रामआसरे फक्कड़, रामवीर और गौरी यादव आदि।

2009 तक चंबल में चलती थी दस्युओं की हुकूमत, राजनीति में मदद लेते थे प्रत्याशी

2009 तक चंबल में दस्युओं की एक तरह से हुकूमत चलती थी। पहले निर्भय गुर्जर, जगजीवन परिहार, रामआसरे फक्कड़, रामवीर सिंह गुर्जर, अरविंद गुर्जर, चंदन यादव, मंगली केवट, रघुवीर ढीमर जैसे बड़े गिरोह सक्रिय थे। बीहड़ से जुड़े हुए प्रत्येक गांव में डकैतों की की तूती बोलती थी। कई बार मतदाताओं को पक्ष में करने के लिए प्रत्याशी डकैतों की मदद लेने से भी नहीं चूकते थे। निर्भय गुर्जर, जगजीवन परिहार एवं पहलवान गुर्जर जैसे डकैत जिस प्रत्याशी के पक्ष में भी फरमान जारी करते थे, उसी को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे। निर्भय गुर्जर तो लेटर पैड पर फरमान लिखता था, जिसके ऊपर दस्यु सम्राट निर्भय वीर गुर्जर लिखा रहता था। वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में डकैत रामआसरे उर्फ फक्कड़ ने इटावा से भाजपा प्रत्याशी सुखदा मिश्रा के पक्ष में वोट डालने का फरमान घार पट्टी के गांवों में सुनाया था। सुखदा जीत भी गई थीं। हालांकि, 2009 के बाद डकैत गिरोहों का पतन शुरू हो गया। अभी कोई दस्यु बीहड़ में सक्रिय नहीं है।

मैदानी क्षेत्र भी डाकुओं से अछूते नहीं रहे: फर्रुखाबाद, मैनपुरी और एटा के मैदानी क्षेत्र भी डाकुओं से अछूते नहीं रहे। 1970 से 1992 तक इनामी डकैत छविराम यादव की तूती बोलती थी। चुनाव में सजातीय नेता के पक्ष में छविराम का फरमान आता था। छविराम की फर्रुखाबाद की तत्कालीन मोहम्मदाबाद एवं एटा की अलीगंज क्षेत्र में खासी रुचि थी। उसके मारे जाने के बाद पोथी यादव ने गैंग की कमान संभाली थी। गंगा की कटरी किंग के नाम से मशहूर डकैत कलुआ यादव कायमगंज विस क्षेत्र में दखल रखता था। कानपुर देहात के भोगनीपुर व सिकंदरा के यमुनापट्टी का कुछ इलाका बीहड़ में आता है। यहां पर चार दशक पहले श्रीराम-लालाराम व फूलन के गिरोह का आना-जाना था, पर इन लोगों ने कभी कोई फरमान जारी नहीं किया। न चुनाव में खलल डाला।

****

56 मतदान दल तीन दिन पहले यानी 19 अप्रैल को पहुंच जाएंगे छत्तीसगढ़ के अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर। यह सभी मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ विस चुनाव के दौरान भी नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान हुए थे।

उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक भंडारी का इस्तीफा, भाजपा में शामिल

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका
- दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में थामा भाजपा का दामन

लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के अगले ही दिन भाजपा ने गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की बदरीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी को अपने पाले में कर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। भंडारी ने रविवार को कांग्रेस से त्यागपत्र देकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व गढ़वाल सीट से पार्टी प्रत्याशी अनिल बलूनी की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले भंडारी ने विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। साथ ही, बदरीनाथ सीट को रिक्त घोषित कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उधर, टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि वह भी भाजपा में वापसी कर सकते हैं।

पूर्व कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह भंडारी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। एएनआइ

बदरीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी के लंबे समय से भाजपा में शामिल होने की चर्चा चल रही थी। हाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चमोली जिले के दौरे में भंडारी की मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लंबी बातचीत हुई थी। भंडारी के भाजपा में शामिल होने से गढ़वाल संसदीय सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी ने वर्ष 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और पहली बार विधानसभा पहुंचे। तब उन्होंने तत्कालीन भाजपा सरकार को समर्थन दिया और वह पहले खंडूड़ी, फिर निशंक सरकार में मंत्री रहे। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले वह कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से विधायक चुने गए। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में वह हार गए थे, जबकि वर्ष 2022 में वह तीसरी बार विधायक चुने गए थे।

आज जारी होगी अधिसूचना: विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भंडारी का त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सोमवार को अधिसूचना जारी करचुनाव आयोग को सूचित कर दिया जाएगा।

तेलंगाना में बीआरएस के सांसद और विधायक कांग्रेस में शामिल

बीआरएस के पूर्व नेता रंजीत रेड्डी रविवार को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआइसीसी तेलंगाना प्रभारी दीपादास मुंशी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। प्रेट्र

हैदराबाद, प्रेट्र : तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को बड़ा झटका लगा है। चेवेल्ला से पार्टी के मौजूदा सांसद रंजीत रेड्डी और खैरताबाद से विधायक डी. नागेंद्र राव लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। रंजीत रेड्डी ने एक पोस्ट में कहा कि मैंने बीआरएस पार्टी को त्यागपत्र सौंप दिया है। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मैंने अपना इस्तीफा सौंपने का यह कठिन निर्णय लिया है। रंजीत रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज हमने अन्य पार्टी नेताओं के लिए द्वार खोल दिए हैं। वारंगल से सांसद पसुनूरी दयाकर शनिवार को सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए थे।

लालू की बेटी रोहिणी छपरा से लड़ेगी लोकसभा चुनाव

राज्य ब्यूरो, पटना

- मीसा भारती एक बार फिर पाटलिपुत्र सीट से आजमाएंगी किस्मत

अपने बीमार पिता लालू प्रसाद को किडनी दान देकर रातों-रात सुर्खियों में आई लालू प्रसाद की छोटी पुत्री रोहिणी आचार्य छपरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। जबकि, उनकी बड़ी बेटी डा. मीसा भारती पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगी। पाटलिपुत्र सीट से मीसा तीसरी बार चुनाव लड़ेंगी, वह दो बार यहां से हार चुकी हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और इसके अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन महागठबंधन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। सोमवार को महागठबंधन में सीट विभाजन को लेकर एक बार फिर दिल्ली में बैठक संभावित है। इस बैठक में राजद की ओर से राज्यसभा सदस्य मनोज झा और संजय यादव भाग लेंगे। बैठक के पूर्व यह खबर जोरों पर है कि लालू ने दो लोकसभा

रोहिणी यादव। फाइल

सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। लालू और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने आपसी सहमति से निर्णय लिया है कि लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य को छपरा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। जबकि, बड़ी बेटी डा. मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव को टक्कर देंगी।

भाजपा में संविधान बदलने की हिम्मत नहीं : राहुल

समापन यात्रा ▶ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद तेजपाल हाल में किया सभा को संबोधित

कहा- देश में जो नफरत दिखाई देती है, वह सिर्फ अन्याय के कारण

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- राहुल गांधी ने दो चरणों में चली अपनी करीब 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया मुंबई में
- उन्होंने दावा किया कि सिर्फ पांच प्रतिशत लोगों को मिलता है न्याय, कांग्रेस शेष लोगों की लड़ाई लड़ेगी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने रविवार को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन करते हुए कहा कि भाजपा में संविधान बदलने की हिम्मत नहीं है।

राहुल गांधी मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक पदयात्रा करने के बाद उसी गोकुलदास तेजपाल हाल में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां 28 दिसंबर, 1885 को 72 नेताओं ने बैठकर कांग्रेस की स्थापना की थी। इन तीनों स्थानों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। मणि भवन मुंबई में महात्मा गांधी का आवास था, तो अगस्त क्रांति मैदान, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के लिए जाना जाता है और तेजपाल हाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राहुल गांधी ने दो चरणों में चली अपनी करीब 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का समापन तेजपाल सभागार में ही किया। यह अगस्त क्रांति मैदान के बिल्कुल बगल में स्थित है।

रविवार सुबह मणि भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद

मुंबई में रविवार को गोकुलदास तेजपाल हाल में सभा को संबोधित करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एएनआइ

पैदल ही अगस्त क्रांति मैदान की ओर निकले राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता एवं कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। तेजपाल हाल में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि आदर एवं मोहब्बत भारत के डीएनए में है। हमें दो वर्ष की यात्रा के दौरान पता चला कि देश में जो नफरत दिखाई देती है, वह सिर्फ अन्याय के कारण है। इसीलिए हमने अपनी यात्रा के दूसरे चरण में 'न्याय' शब्द भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत पहला देश है, जिसने अपनी आजादी की लड़ाई भी प्यार से लड़ी। जब वह दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहां नेल्सन मंडेला ने उनसे कहा था कि गांधी जी और भारत ने उन्हें आजादी की राह दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और संघ सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं के पास ज्ञान है। आज एक ओर कुछ लोगों के पास देश की सारी संपत्ति है, दूसरी ओर किसानों, युवाओं और मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे बहुत शोर करते हैं, लेकिन उनमें (भाजपा और आरएसएस) देश का संविधान बदलने की हिम्मत नहीं है। सत्य और हिंदुस्तान हम सबके साथ है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान लड़ाई सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि दो अभिव्यक्तियों के बीच है। एक की सोच है कि देश को केंद्र से चलाया जाना चाहिए जहां एक व्यक्ति के पास सारा ज्ञान है। इसके विपरीत हमारा मानना है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और लोगों की आवाज सुनी जाना चाहिए। अगर किसी के पास आइआइटी की डिग्री है तो इससे वह एक किसान से अधिक ज्ञानवान नहीं हो जाता। मोदी और आरएसएस का विजन है कि ज्ञान एक व्यक्ति के पास है... किसान, मजदूर और बेरोजगारी युवाओं के पास ज्ञान नहीं है।

राहुल ने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का आह्वान करते हुए कहा कि देश के लोगों में कोई संयुक्त चेतना नहीं है। उन्होंने कहा, 'लोग अपने साथ हुए अन्याय को तो देखते हैं, लेकिन साथी नागरिक के साथ हो रहे अन्याय की अनदेखी करते हैं। जब तक आप अपने साथी नागरिक के साथ हो रहे अन्याय को नहीं देखेंगे, तब तक कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता।' उन्होंने दावा किया कि देश में सिर्फ पांच प्रतिशत लोगों को न्याय मिलता है। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वह अकेले नहीं थे, लाखों लोग उनके साथ चल रहे थे। यात्रा की ताकत राहुल गांधी नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो उनके साथ खड़े थे।

कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को कल मिलेगी सीडब्ल्यूसी की मंजूरी

नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र को मंगलवार को मंजूरी देगी। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक भी 19 या 20 मार्च को हो सकती है। कांग्रेस ने अब तक दो अलग-अलग सूचियों में कुल 82 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सीडब्ल्यूसी 19 मार्च को बैठक करेगी और मसौदा घोषणापत्र पर चर्चा कर उसे मंजूरी देगी जिसमें न्याय के लिए पांच 'गारंटियां' दी गई हैं।

देश की स्थिति में बदलाव लाना आवश्यक : शरद पवार

विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए की रैली के दौरान एकजुटता प्रदर्शित करतीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजद नेता तेजस्वी यादव और वंचित बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश आंबेडकर। प्रेट्र

प्रथम पृष्ठ से आगे

राकांपा (शरद पवार गुट) अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि आज देश में जो स्थिति है, उसमें बदलाव लाना आवश्यक है। जिनके हाथ में सत्ता है, उन्होंने अपने किए वायदे पूरे नहीं किए। इसलिए अब चुनाव में वोट देकर उन्हें हटाने की जरूरत है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि हम लोग साथ मिलकर लड़ें, या अकेले लड़ें लेकिन इस सरकार से लड़ने की जरूरत है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने के लिए राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में तो कुछ विधायक ही टूट कर गए हैं। बिहार में तो हमारे चाचा (इशारा नीतीश कुमार की ओर) को ही हाईजैक कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई नफरत की विचारधारा के खिलाफ है, व्यक्तिगत रूप से पीएम नरेन्द्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि मेरे पति को एक साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें भारत को सभी लोगों के लिए सुरक्षित रखना है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना था कि भाजपा का 400 से अधिक सीटें जीतने की बात करती है लेकिन वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब लोग एकजुट होते हैं तो तानाशाही समाप्त हो जाती है।

मप्र की 10 लोकसभा सीटों पर होगा कांग्रेस-भाजपा में कड़ा संघर्ष

सौरभ सोनी, भोपाल

- विंस चुनाव की दृष्टि से पांच संसदीय सीटों पर भाजपा की रही बढ़त, यहां कांग्रेस का कमजोर जनाधार

वर्ष 2019 के आम चुनाव में 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा के लिए मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं। इनमें छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, मंडला, बालाघाट, रतलाम, धार और खरगोन लोकसभा सीट शामिल है। इन संसदीय क्षेत्रों में आने वाली विधानसभा सीटों में से अधिकांश पर पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी सातों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती थी। विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने पहले हुए हैं और यदि मतदाताओं का वही मूड रहता है तो इन लोकसभा सीटों पर कड़ा संघर्ष होने की पूरी संभावना है।

मध्य प्रदेश

इस बीच, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इन सीटों पर मैदानी स्तर पर चुनावी जमावट शुरू कर दी है। भाजपा ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने केवल 10 प्रत्याशी घोषित किए हैं। कड़े संघर्ष वाली केवल चार सीटों पर ही फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तय हुआ है। मुरैना, मंडला, धार और खरगोन की पांच-पांच, भिंड, ग्वालियर, बालाघाट, रतलाम लोकसभा क्षेत्र की चार-चार, टीकमगढ़ की तीन विधानसभा सीटों पर भाजपा हारी है। ऐसे में इन सीटों पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में मिले परिणामों के अनुरूप तैयारी की है। इन लोकसभा सीटों पर पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी भी उतारे हैं। पांच लोकसभा क्षेत्र खजुराहो, होशंगाबाद, देवास, इंदौर और खंडवा भाजपा के सुरक्षित मानी जाती है। सभी विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में है।

इस बार आएंगे चौंकाने वाले परिणाम: तेजस्वी

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है। दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हम पूरी तरह से आशान्वित हैं और चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार भी। रविवार को मुंबई रवाना होने के पूर्व तेजस्वी ने राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और पेपर लीक प्रकरण पर भी सवाल उठाते हुए कहा इसे कहते हैं असल माफिया राज।

तेजस्वी ने कहा कि नीतीश भले ही महागठबंधन छोड़ राजग में चले गए हों, लेकिन बिहार की जनता वहीं खड़ी है। यहां के लोगों के अंदर करंट है। 17 वर्ष बनाम 17 महीने के अपने एजेंडे को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार ने अपने कार्यकाल के 17 वर्ष में और केंद्र की मोदी सरकार ने 10 वर्ष में बिहार के लिए क्या किया? केंद्र सरकार ने न तो किसानों की समस्या पर ध्यान दिया न ही रोजगार पर। तेजस्वी ने कहा नीतीश राजग में जाने के बाद कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हम उनकी मजबूरियों से परिचित हैं।

एक दूसरे के वार रूम में बैठेंगे सपा नेता और कांग्रेसी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वार रूम में दोनों दलों के नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस संदर्भ में आइएनडीआइए ने चुनावी तैयारी की रूपरेखा तय कर ली है। दोनों पार्टियां एक-दूसरे के वार रूम में दो-दो नेताओं की ड्यूटी लगाने पर सहमत हैं। हर सीट पर दोनों की तरफ से तरफ से दो-दो नेताओं को तालमेल के लिए तैनात किया जा रहा है। इसके ऊपर राज्य स्तर पर पांच-पांच नेताओं की टीम बनाकर तालमेल स्थापित किए जाने की रणनीति बनाई गई है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में खुले वार रूम के बारे में अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि सपा के दो नेता भी यहां बैठेंगे। दोनों दलों ने मिलकर चुनावी रणनीति तय कर ली है। सपा के वार रूम में कांग्रेस के दो नेताओं को बैठाया जाएगा। इसी प्रकार सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की तरफ से दो और सपा की तरफ से दो नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। सपा ने अपने नेताओं की सूची सौंप दी है। सीट वार दोनों दलों के नेताओं की एक बैठक हो चुकी है। वहीं, कांग्रेस नेता अंशू अवस्थी ने बताया कि राज्य स्तर पर दोनों दलों की तरफ से पांच-पांच नेताओं को कोआर्डिनेटर के तौर पर तैनात किया जा रहा है।

राहुल की यात्रा में नहीं पहुंचे अखिलेश, लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लोकसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में मुंबई नहीं गए। इस कार्यक्रम में विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। अखिलेश ने राहुल को पत्र लिखकर यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने में अपनी असमर्थता जताई है। उन्होंने लिखा कि 20 मार्च से यूपी में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियों के चलते मैं यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। अखिलेश ने पत्र में लिखा... 'आज मुंबई में आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो रहा है। बिरले ही लोग हैं जो ऐसी यात्रा कर सकते हैं। आपके दृढ़ संकल्प के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपने इस यात्रा की मणिपुर से शुरुआत की, जो भाजपा सरकार की नाकामी के कारण जल रहा है। पूर्वोत्तर से आपने तानाशाह सरकार के विरुद्ध मजबूत संदेश दिया। पूरी यात्रा के दौरान आपकी किसान, नौजवान, महिला, बुजुर्ग समेत समाज के हर वर्ग से मुलाकात हुई। आप उनकी समस्याओं से नजदीक से रूबरू हुए।' अखिलेश ने आगे लिखा... '20 मार्च से यूपी में नामांकन प्रारंभ है, जिसकी तैयारियों के चलते मैं यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि किसान, नौजवान, पिछड़ा, दलित और महिला विरोधी भाजपा को जनता इस चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। इस यात्रा की असली सफलता इसी मायने में होगी कि भाजपा को इस चुनाव में पराजय मिले।'

अखिलेश यादव।

'एमवीए में सीट बंटवारे की अंतिम दौर की बातचीत समाप्त, शीघ्र होगी घोषणा'

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि महाविकास आघाडी (एमवीए) के नेताओं ने सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की चर्चा कर ली है। जल्द ही सीट बंटवारे के फार्मूले की घोषणा की जाएगी। वह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमवीए के घटक दलों शिवसेना (उद्धव गुट), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस ने शनिवार को महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए अपनी अंतिम बैठक की। बैठक में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस दौरान सीट बंटवारे से संबंधित छोटी-छोटी बारीकियों को सुलझा लिया गया है। एमवीए वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर के साथ बातचीत कर रही है। चार सीटों की पेशकश पर उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है।

उम्मीदवारी

भाजपा नेतृत्व की तरफ से नेताओं को कोई निर्देश या संकेत नहीं दिया गया, दोनों गठबंधनों में सीटों के तालमेल पर होने वाली है बड़ी बैठक

बिहार में तलवार की धार पर भाजपा के आधा दर्जन सांसद

अरविंद शर्मा, नई दिल्ली

बिहार में अभी तक किसी पक्ष ने साफ नहीं किया है कि किसका टिकट पक्का है और किसका नहीं। दोनों गठबंधन अभी सीट बंटवारे की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जदयू में ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं है, लेकिन भाजपा के लगभग आधा दर्जन सांसदों की दावेदारी तलवार की धार से गुजर रही है। नेतृत्व की तरफ से उन्हें कोई निर्देश या संकेत नहीं दिया गया है। न बताया गया है और न उनके पास किसी माध्यम से कोई सूचना पहुंची है। ऐसे में उनका पटना-दिल्ली का दौरा बढ़ गया है। अनिश्चितता भी कि आगे क्या होगा। चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) में भी कुछ न कुछ पेच फंस रहा है, किंतु अभी एक-दो दिन बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोनों गठबंधनों में सीटों के तालमेल पर बड़ी बैठक होने वाली है। फिर प्रत्याशियों की घोषणा में विलंब नहीं होगा। सीटों के तालमेल और फेरबदल के मुद्दे पर बिहार राजग के सभी दलों के शीर्ष नेताओं के साथ भाजपा का अंतिम विमर्श सोमवार को होने जा रहा है। मुख्यमंत्री एवं जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार सोमवार शाम दिल्ली आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के जीतन राम मांझी भी पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि देर रात सभी दलों के बीच बातचीत में अंतिम सहमति बना ली जाएगी। इस बीच, भाजपा ने कुछ क्षेत्रों को विचाराधीन रखा है, उनमें बक्सर, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, शिवहर एवं पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। वहां से पूर्व आइपीएस अफसर आनंद मिश्रा की प्रबल दावेदारी है। असम कैडर के 2011 बैच के इस आइपीएस अफसर की दुर्गम इलाके में बहादुरी के कई किस्से हैं। मात्र 12 वर्ष की नौकरी के बाद राजनीति में प्रवेश को साहसिक फैसला बताया जा रहा है।

चिराग पासवान। फाइल

इस तरह हो सकता है बंटवारा... भाजपा 17 और जदयू को 16 सीटें

राजग के दोनों बड़े घटक दलों भाजपा और जदयू में सहमति बन चुकी है। भाजपा 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और जदयू के हिस्से में 16 सीटें आई हैं। एक-एक सीट कुशवाहा एवं मांझी की पार्टी को मिली है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आर) के हिस्से में पांच सीटें गई हैं। जदयू को लवली आनंद के लिए राजपूत बहुल एक सीट चाहिए। औरंगाबाद से उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जहां अभी भाजपा के सुशील सिंह सांसद हैं। जदयू के हिस्से की गया और काराकाट सीट जीतन राम मांझी एवं कुशवाहा के लिए छोड़ी गई है। चिराग के हिस्से में आई पांच सीटों में नवादा को लेकर जिच है। वैशाली-नवादा भूमिहार बहुल है। वैशाली में लोजपा से भूमिहार जाति की विनीता विजय का लड़ना तय है। पांच सीटों वाली लोजपा से दो भूमिहार प्रत्याशी उतारने पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में नवादा के बदले चिराग को कोई अन्य सीट की दरकार है। चिराग ने नवादा अगर लौटा दिया तो भाजपा यहां से विवेक ठाकुर या आइपीएस अफसर विकास वैभव पर दांव लगा सकती है। पशुपति पारस के गुट के सूरजभान सिंह को भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है।

बंसल को अपनों से मिल रही चुनौती

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़

- चंडीगढ़ से आठ बार चुनाव लड़ चुके हैं पवन बंसल, इस बार टिकट के लिए कई दावेदार

आठ बार चंडीगढ़ सीट से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल को इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है। 9वीं बार टिकट के लिए उनके अपने रोड़े अटका रहे हैं। वह साल 1991 से अब तक लगातार कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इस सीट के लिए बंसल के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री व आनंदपुर साहिब के सांसद मनीष तिवारी प्रबल दावेदार हैं। टिकट के लिए कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने भी बंसल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बंसल पिछले दो माह से चुनाव प्रचार में जुटते हुए लगातार शहर के मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 मार्च को हैं, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि चंडीगढ़ सीट का चुनाव अंतिम फेज में होना है। ऐसे में चुनाव देरी से होने के कारण हाईकमान टिकट तय करने में कुछ समय और ले सकता है। लक्की गुट दो सप्ताह पहले टिकट के लिए हाईकमान के नेताओं को भी मिलकर आया है। बंसल को अब तक आठ बार टिकट मिली है जिनमें से उन्होंने चार चुनाव जीते हैं और चार चुनाव हारे हैं। पिछले दो चुनाव वह भाजपा की सांसद किरण खेर से हारते रहे हैं। इससे पहले तक यह होता था कि टिकट के लिए बंसल को कांग्रेस अध्यक्ष का साथ मिलता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अध्यक्ष लक्की मजबूती से टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मेयर रविंदर सिंह पाली, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनोज लुभाना, पूर्व युकां अध्यक्ष हरमेल केसरी और सतीश मंचाल ने भी आवेदन किया है।

पवन बंसल। फाइल

****

59 लाख नकद जब्त हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद। जिले के पुलिस अधीक्षक केनी बागरा ने बताया यह नकदी पड़ोसी कामले जिले के बोआसिमला निवासी बोआ टेरी के पास से जब्त की गई। जांच आयकर विभाग द्वारा की जा रही है।

आयोग ने पर्यावरण अनुकूल चुनाव सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

पहल ▶ कागज का न्यूनतम इस्तेमाल, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग और कार पूल करने पर दिया जोर

नई दिल्ली, प्रेट्र: चुनाव आयोग ने पर्यावरण अनुकूल चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं। आयोग के निर्देशों में एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने, कागज का न्यूनतम इस्तेमाल करने, पर्यावरण अनुकूल वाहनों का उपयोग करने और कार पूल करने पर जोर दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार, आयोग पर्यावरण अनुकूल चुनाव के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने शनिवार को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हम एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने और चुनाव प्रक्रिया में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, कागज का न्यूनतम उपयोग करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए चुनाव मशीनरी और राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किये गए हैं।

आयोग ने मतदाता सूची और चुनावी सामग्री के लिए कागज के उपयोग को कम करने, दोनों ओर मुद्रण सुनिश्चित करने और संचार के इलेक्ट्रानिक माध्यमों को प्रोत्साहित करने को कहा है। आयोग ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों से प्रचार और चुनाव प्रक्रिया के दौरान कार पूलिंग को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही प्रचार कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने, अधिकारियों एवं मतदाताओं द्वारा तय की जाने वाली दूरी को कम करने के लिए मतदान केंद्रों को समेकित करने का भी आग्रह किया है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए मतदान सात चरणों में होगा। मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल को होगी। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती चार जून को होगी।

मतदाता सूची और चुनावी सामग्री के दोनों ओर मुद्रण सुनिश्चित करने और संचार के इलेक्ट्रानिक माध्यमों को प्रोत्साहित करने को कहा है

राजीव कुमार। फाइल

लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बंगाल में हिंसा की घटनाएं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही बंगाल में जगह-जगह हिंसा की घटनाएं घटने लगी हैं। पश्चिम बर्द्धमान में एक भाजपा कार्यकर्ता की दुकान में तोड़फोड़ करने के साथ आग लगाने की घटना सामने आई है।

वहीं दक्षिण दिनाजपुर में एक भाजपा कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई की गई है। इसके अलावा नदिया में एक टीएमसी नेता के घर पर बम से हमला किया गया है।

जानकारी के मुताबिक पश्चिम बर्द्धमान के पांडेश्वर में शनिवार देर रात भाजपा महिला मोर्चा की नेता रीना ठाकुर की दुकान में तोड़फोड़ करने के साथ आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि वह छह महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुई हैं और तभी से उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से धमकियां मिल रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के उपद्रवियों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की है। वहीं दक्षिण दिनाजपुर के गंगारामपुर में शनिवार को तृणमूल कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्यकर्ता जयदीप दास की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। इस घटना में जयदीप का सिर फूट गया है। घायल भाजपा कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सूत्रों के मुताबिक जयदीप के भाई की पत्नी मिताली दास पिछले पंचायत चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार थीं। तभी से जयदीप को टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा परेशान किया जा रहा है। नदिया जिला अंतर्गत कृष्णानगर में टीएमसी के अल्पसंख्यक सेल के नेता खोकोन खान के घर पर शनिवार रात उपद्रवियों ने बम फेंके।

तृणमूल नेता प्रसून बनर्जी पर केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग को धमकाने का आरोप

नई दिल्ली, एएनआइ: लोकसभा चुनाव के लिए मालदा उत्तर सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसून बनर्जी के एक कथित वीडियो को लेकर भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने हमला बोला है। मालवीय ने कहा, प्रसून जिन्होंने आइपीएस पद छोड़ दिया और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए अब चुनाव आयोग को डरा रहे हैं। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के रूप में क्या किया! भाजपा आइटी सेल के प्रमुख ने प्रसून बनर्जी का वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रसून धमकाते दिख रहे हैं। हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे दो जून को आएंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र: चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होने वाले विधानासभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदल दी है। चुनाव आयोग ने पहले मतगणना की तारीख चार जून घोषित की थी।

इसे बदलकर अब दो जून कर दिया है। दोनों राज्यों में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, दोनों राज्यों में विधानसभा कार्यकाल दो जून को खत्म हो रहा है इसलिए तारीख बदली गई। गौरतलब है कि दो जून के केवल विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी, लोकसभा चुनाव की मतगणना चार जून को ही होगी। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले 16 मार्च को चुनाव आयोग ने चार राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान किया था।

अरुणाचल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में मतगणना लोकसभा चुनावों के साथ चार जून को होगी। इनके अलावा गुजरात की पांच, यूपी की चार, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु की 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। यहां उस क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही नोटिफिकेशन जारी होगा और वोटिंग होगी।

दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल दो जून को हो रहा खत्म

चुनाव आयोग ने पूर्व में जारी तिथियों में किया बदलाव

मैं लौटूंगा वाली पंक्ति के लिए मेरा मजाक उड़ाया गया: फडणवीस

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में जब मैंने कहा था कि मैं लौटूंगा तो मेरा मजाक उड़ाया गया, लेकिन मैं दो दलों को विभाजित कर सत्ता में लौट आया। उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार की अगुवाई वाली राकांपा के विभाजन की ओर इशारा करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद जून 2022 में शिवसेना विभाजित हो गई थी। जबकि पिछले साल अजीत पवार के भाजपा से हाथ मिलने के बाद राकांपा दो धड़ों में बंट गई थी।

देवेंद्र फडणवीस। फाइल

फडणवीस ने एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान कहा कि मैं न केवल वापस आया, बल्कि दो पार्टियों को विभाजित करके लौटा। सत्ता में वापस आने में ढाई साल लग गए।

मैंने 2019 के विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान एक कविता पढ़ी थी, लेकिन इसकी केवल एक पंक्ति ही लोकप्रिय हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बड़ी संख्या में सीटें जीतीं और 2019 विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के साथ सरकार बना सकती थी। लेकिन, उद्धव ठाकरे ने हमें धोखा दिया। हमें विपक्ष में बैठना पड़ा।

अमरनाथ यात्रा के बाद ही होगी जम्मू-कश्मीर में विस चुनाव

नवीन नवाज, जम्मू

लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही यह भी साफ हो गया है कि इन चुनाव के साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन यह जून-जुलाई में होंगे, इसकी संभावना क्षीण है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर में पांच चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जून में श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक व सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए विधनसभा चुनाव अमरनाथ यात्रा संपन्न होने के बाद अगस्त-सितंबर में ही करवाए जाने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर में अंतिम बार विधानसभा चुनाव वर्ष 2014 में हुए थे। जून 2018 में तत्कालीन पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार गिर जाने के बाद से विधानसभा चुनाव लंबित पड़े हुए हैं।

जम्मू कश्मीर

जम्मू-कश्मीर की पांच सीटों के लिए लोस चुनाव पांच चरण में

- **19 अप्रैल:** ऊधमपुर-डोडा-कठुआ संसदीय सीट
- **26 अप्रैल:** जम्मू-रियासी सीट
- **7 मई:** अनंतनाग-राजौरी सीट
- **13 मई:** श्रीनगर-गांदरबल सीट
- **20 मई:** बारामुला-कुपवाड़ा सीट

इन कारणों से लंबित पड़े हैं चुनाव

जम्मू-कश्मीर में जून 2018 में तत्कालीन पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार गिरने के बाद वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण, जम्मू-कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में पुनर्गठित होने, सुरक्षा कारणों, जम्मू-कश्मीर में परिसीमन व मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया संबंधी विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा किए जाने के कारण विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सके हैं।

कराए जाने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते वर्ष केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का गठन करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और देश में एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा समिति गठित किए जाने के बाद सभी को उम्मीद थी कि जम्मू-कश्मीर में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। भाजपा इस मुद्दे पर हालांकि चुप थी, लेकिन नेशनल कान्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कान्फ्रेंस, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी जैसे विभिन्न राजनीतिक दल दोनों चुनाव एक-साथ कराए जाने पर जोर दे रहे थे।

दोनों चुनाव साथ कराने पर ये होतीं चुनौतियां: चुनाव अयोग के निर्णय पर सभी की अपनी-अपनी राय हो सकती है, लेकिन आयोग ने दोनों चुनाव एक साथ न कराने का निर्णय परिवर्तन काल से गुजर रहे जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ही लिया है, ऐसा कहना उचित रहेगा। लोकसभा चुनाव के साथ अगर विधानसभा चुनाव कराए जाते तो बेशक मतदान केंद्रों, मतदान कर्मियों की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, लेकिन सुरक्षा प्रबंध को पूरी तरह चाक चौबंद बनाए रखना, सभी प्रत्याशियों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती रहता।

किसान अपनी मर्जी के दल को वोट करें, नोटा न दबाएं: राकेश टिकैत

जासं, मुजफ्फरनगर : भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने लोकसभा चुनाव में संगठन के रुख को मासिक पंचायत में स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, किसान अपनी मर्जी के दल को वोट करें। नोटा दबाकर वोट खराब न करें। संगठन को मजबूत किया जाए, ताकि किसान हित में सरकार से मुकाबला किया जा सके। रविवार को सिसौली के किसान भवन में भाकियू की मासिक पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि अमेरिका में 40-50 वर्ष पहले यहां की तरह किसान थे, लेकिन अब वहां कोई भी किसान नहीं है। यही व्यवस्था भारत में भी लागू होने वाली है।

राकेश टिकैत। फाइल

बंगाल में अभिषेक को चुनौती दे सकते हैं आइएसएफ के नौशाद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल की हाई प्रोफाइल डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) अपने एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी को उतार सकती है। नौशाद ने रविवार को खुद भी वहां से लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा- 'मैं डायमंड हार्बर सीट पर लड़ने के लिए 100 प्रतिशत तैयार हूं। उम्मीद है कि मेरी पार्टी सोमवार को इसकी मंजूरी दे देगी।' दूसरी तरफ माकपा ने नौशाद का समर्थन करने की बात कही है। माकपा की केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा-'नौशाद अगर डायमंड हार्बर सीट पर लड़ेंगे तो आइएसएफ की पुरानी साझेदार होने के नाते हम उनका समर्थन करेंगे और वहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। मालूम हो कि आइएसएफ ने पिछला विधानसभा चुनाव माकपा की अगुआई वाले वाममोर्चा के साथ मिलकर लड़ा था। उस चुनाव में नौशाद ने भांगड़ सीट पर जीत दर्ज की थी। अभिषेक डायमंड हार्बर से दो बार के सांसद हैं।

जस्टिस गांगुली से चुनाव नहीं लड़ने का अनुरोध: तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने भाजपा में शामिल हुए कलकत्ता हाइ कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गांगुली से चुनाव नहीं लड़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने तमलुक में एक सभा में कहा-आप (जस्टिस गांगुली) जिस सुवेंदु अधिकारी का हाथ पकड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, चुनाव में खड़े होने पर वही आपको जीतने नहीं देंगे। भाजपा के किसी भी नेता को वह बंगाल में स्थापित होने नहीं देंगे।

राष्ट्रीय फलक

दो राष्ट्रीय दल समेत कुछ क्षेत्रीय दलों को चुनावी बांड से नहीं मिला चंदा

संजय मिश्र, नई दिल्ली

चुनावी बांड के जरिये कई प्रमुख पार्टियों को सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपये का चंदा मिला है। हालांकि, दो राष्ट्रीय और दर्जनभर क्षेत्रीय दलों समेत पांच सौ पंजीकृत पार्टियों को एक पैसा भी नहीं मिला है। राष्ट्रीय पार्टियों बसपा और माकपा को चुनावी बांड से कोई पैसा नहीं मिला है। वैसे माकपा समेत वामपंथी विचारधारा से जुड़ी लगभग सभी पार्टियों ने चुनावी बांड कानून का सैद्धांतिक विरोध करते हुए चुनावी बांड के जरिये चंदा लेने से इन्कार कर दिया था। मालूम हो कि चुनावी बांड को रद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर तीन याचिकाओं में एक याचिका माकपा की थी।

चुनावी बांड के दानदाताओं का ब्योरा सार्वजनिक नहीं करने के भारतीय स्टेट बैंक के रुख पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले रविवार को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों की ओर से उसे दिए गए विवरण को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। इसमें भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, बीजद, अन्नाद्रमुक जैसे दलों ने मार्च 2018 में चुनावी बांड योजना लागू होने के बाद उन्हें मिले चंदे का ब्योरा दिया है। इस ब्योरे का दिलचस्प पहलू यह है कि राष्ट्रीय दल होते हुए भी बसपा का चुनावी बांड का खाता भी नहीं खुला है। सात नवंबर, 2023 को आयोग को भेजी चिट्ठी में पार्टी ने कहा है कि जब से चुनावी बांड लागू हुआ है, तब से पार्टी को एक रुपये का भी चंदा नहीं मिला है। माकपा ने आयोग को भेजे पत्र में कहा कि चूंकि पार्टी प्रारंभ से चुनावी बांड के खिलाफ मुखर थी, इसलिए हमने बांड के जरिये चंदा लेने से इन्कार कर दिया। पिछले साल राष्ट्रीय दल का दर्जा गंवाने वाली भाकपा ने कहा कि अभी तक पार्टी ने चुनावी बांड से एक रुपया भी किसी व्यक्ति या संगठन से हासिल नहीं किया है। वामपंथी मोर्चे की एक अन्य पार्टी फारवर्ड ब्लाक ने आयोग को बताया है कि चुनावी बांड का सैद्धांतिक विरोध करने के कारण पार्टी ने इसके माध्यम से कोई दान स्वीकार नहीं किया है।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उसे भी चुनावी बांड से कोई चंदा नहीं मिला है। महाराष्ट्र-मुंबई की राजनीति में अपनी मुखर शैली के लिए चर्चित नेता राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी चुनावी बांड योजना शुरू होने से अब तक कोई दान नहीं मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट की ओर से उसके महासचिव अब्दुल खालिक ने आयोग को भेजे ई-मेल में कहा है कि उनकी पार्टी को कोई चंदा नहीं मिला है। पीपुल्स फ्रंट से लेकर असम के चर्चित नेता बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआइयूडीएफ जैसी कई पार्टियों ने चुनाव आयोग को अपना ब्योरा भेजते हुए साफ कहा है कि चुनावी बांड से उन्हें एक रुपये का भी चंदा नहीं मिला है।

माकपा ने सैद्धांतिक विरोध के कारण बांड से चंदे को नहीं किया स्वीकार

वसपा ने कहा, योजना शुरू होने से अब तक उसका खाता शून्य

भाकपा समेत वामपंथी खेमे की किसी पार्टी ने बांड से नहीं लिया चंदा

चुनावी बांड। प्रतीकात्मक

चुनावी बांड पर किस पार्टी ने क्या कहा

प्रथम पृष्ठ से आगे

भाजपा: चुनावी बांड से जुड़ी जानकारियों को साझा करने से छूट मिली हुई है। चुनावी बांड इस उद्देश्य से लाया गया था कि इसमें सिर्फ वैध राशि का इस्तेमाल हो। इसमें चंदा देने वालों को किसी दूसरे प्रभाव से बचाने की भी व्यवस्था है।

तृणमूल: ज्यादातर बांड हमारे आफिस भेजे गए या ड्राप बाक्स में डाले गए। इन्हें देने वालों के नाम या दूसरी जानकारी हमारे पास नहीं है। संभव है कि एसबीआइ के पास इन सभी लोगों की जानकारी हो। एसबीआइ सीधे चुनाव आयोग को इनकी जानकारी दे।

कांग्रेस: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसबीआइ को कहा गया है कि वह चुनावी बांड स्कीम, 2018 से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध कराए। एसबीआइ से किसने बांड लिए और इसकी राशि कितनी थी, इसे किस खाते से लिया गया, इसकी जानकारी मांगी है।

द्रमुक: चुनावी बांड योजना के तहत चंदा देने वाले पक्ष का नाम गोपनीय रखने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने पार्टी को बांड देने वाली कंपनियों से संपर्क किया और उनसे संबंधित जानकारी ली।

भाकपा: हमारी पार्टी ने चुनावी बांड योजना में हिस्सा नहीं लिया है, क्योंकि यह पारदर्शी नहीं है। हमें कोई चुनावी बांड नहीं मिला है।

माकपा: चुनावी बांड का हम हमेशा से विरोधी रहे हैं, क्योंकि यह राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। हमारी पार्टी इस तरह के किसी भी बांड को स्वीकार नहीं करती।

समाजवादी पार्टी: बैंक ने हमसे चंदा देने वाले की जानकारी साझा नहीं की है। इसलिए पार्टी चंदा देने वालों का नाम बताने में सक्षम नहीं है।

वाईएसआर कांग्रेस: चुनावी बांड योजना से खरीदार की जानकारी को नहीं जोड़ा गया है। जानकारी नहीं दी जा सकती।

तेदेपा: चुनावी बांड योजना के तहत चंदा देने वाले का नाम इकट्ठा करना पार्टी का दायित्व नहीं है। इसलिए हम यह जानकारी नहीं दे सकते।

मार्च, 2018 से अप्रैल, 2019 तक बेचे गए चुनावी बांड की जानकारी साझा की जाए

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एक मार्च 2018 से लेकर 11 अप्रैल 2019 के बीच खरीदे गए चुनावी बांड की जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि योजना शुरू होने के बाद से पूरी अवधि तक राजनीतिक दलों को मिले चंदे के बारे में जानने के मतदाता हकदार हैं।

शीर्ष कोर्ट ने पिछले दिनों ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक बताकर रद कर दिया था। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) को 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक खरीदे गए बांड का विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपने का आदेश दिया था। सिटीजन राइट्स ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मार्च 2018 से अप्रैल 2019 के बीच 4,002 करोड़ रुपये के 9,159 बांड बेचे गए हैं और इनकी भी जानकारी दी जानी चाहिए।

दूसरी बार संघ के सरकार्यवाह चुने गए दत्तात्रेय होसबाले

वाद में कहा- प्रयोग है चुनावी वांड, समय वताएगा यह कितना प्रभावी रहा

समान नागरिक संहिता का स्वागत करता है आरएसएस, देशभर में लागू हो

नागपुर में दत्तात्रेय होसबाले को तीन वर्ष के लिए पुनः सरकार्यवाह चुने जाने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, मुंबई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने रविवार को दत्तात्रेय होसबाले को सर्वसम्मति से लगातार दूसरी बार सरकार्यवाह चुन लिया। वह 2021 से सरकार्यवाह के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उनका पुनःनिर्वाचन 2024 से 2027 की अवधि के लिए हुआ है। सभा में अयोध्या स्थित राम मंदिर पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को विश्व इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ करार दिया गया।

प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय वार्षिक बैठक शुक्रवार को नागपुर के रेशिमबाग स्थित समिति भवन परिसर में प्रारंभ हुई थी। इसमें आरएसएस से जुड़े विभिन्न संगठनों के 1,500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में होसबाले ने छह सहसरकार्यवाह नियुक्त किए जिनमें कृष्ण गोपाल, मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, अतुल लिमये और आलोक कुमार शामिल हैं। रविवार की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित थे। बाद में संवाददाता सम्मेलन में होसबाले ने कहा कि चुनावी बांड एक प्रयोग है और वक्त आने पर पता चलेगा कि यह कितना फायदेमंद और प्रभावी रहा। संघ ने अभी तक इसके बारे में चर्चा नहीं की है। उन्होंने कहा, 'यह नियंत्रण व संतुलन के साथ किया गया और ऐसा नहीं है कि चुनावी बांड आज अचानक पेश कर दिया गया, ऐसी योजना पहले भी लाई गई थी। जब भी कोई बदलाव होता है तो सवाल उठाए जाते हैं। जब ईवीएम लाई गई थीं, तब भी सवाल उठाए गए थे। जब नई चीजें आती हैं तो लोगों का सवाल उठाना लाजिमी है।' उन्होंने कहा कि आरएसएस समान नागरिक संहिता का स्वागत करता है। कई वर्ष पहले अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने इसे कानूनी रूप देने की मांग संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया था। इसे उत्तराखंड में लागू किया गया है। हम चाहेंगे कि इसे देशभर में लागू किया जाए। उत्तराधिकार, गोद लेना, विवाह और कुछ अन्य मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है और उसके बाद वे आगे बढ़ सकते हैं। मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल के बारे में होसबाले ने कहा, लोगों ने देखा है कि देश ने पिछले 10 वर्षों में कितनी प्रगति की है और यहां तक कि प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और राजनीतिक विचारकों ने भी दोहराया है कि वर्तमान सदी भारत की है। उन्होंने कहा, 'ऐसा कहने से उनके लिए कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। वैसे भी लोग चार जून को अपना फैसला सुनाएंगे।' इस सवाल कि क्या सीएए की वर्तमान कटआफ डेट 31 दिसंबर, 2014 बढ़ायी जानी चाहिए, होसबाले ने कहा- जरूरत पड़ने पर अधिकारी ऐसा कर सकते हैं। काशी एवं मथुरा से जुड़े विवाद के संबंध में उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो किया गया, वह हर चीज के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है। मामला अदालत में है। अगर यह अदालत में हल होता है तो आंदोलन की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यकों के संबंध में होसबाले ने कहा, 'यह देश सभी का है और (समुदायों को) अल्पसंख्य कहने की पद्धति या विचार दशकों से चला आ रहा है।

चुनावी बांड से इंफोसिस ने भी दिए एक करोड़

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: मुख्य रूप से कर्नाटक में राजनीति करने वाली एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर को इंफोसिस ने चुनावी बांड के जरिये एक करोड़ रुपए दिए। जदएस ने खुद यह जानकारी दी है। 20 मार्च, 2018 को इंफोसिस टेक्नोलाजी नाम से जदएस को चुनावी बांड के माध्यम से एक करोड़ रुपये दिए गए। उस समय राज्य में विधानसभा चुनाव का वक्त था और मई में चुनाव आयोजित किया गया था। जदएस को कुल 89.75 करोड़ रुपये चुनावी बांड से मिले। दिलचस्प बात है कि भाजपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को चुनावी बांड से एक-एक हजार रुपये भी मिले जबकि राज्य स्तर की अन्य पार्टियों को चुनावी बांड के तहत 1,00,000 रुपये से कम नहीं प्राप्त हुए। भाजपा को वर्ष 2018 में पांच व सात मई को 1,000-1,000 रुपये बांड से मिले।

'भाजपा चुनावी बांड से करती है काला धन सफेद'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर चुनावी बांड से चंदा हासिल करने के लिए कंपनियों को फायदा पहुंचाकर उसके बदले बांड के माध्यम से भाजपा के खातों में काले धन को स्थानांतरित करने की 'साजिश' करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि एक ओर चुनावी बांड 'घोटाले' पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चुप हैं तो दूसरी ओर सरकार के दबाव में लोकसभा चुनाव से पहले आयकर अधिकारियों के जरिये कांग्रेस के खाते फ्रीज कराए गए हैं। सरकार का 'कर आतंकवाद' और कांग्रेस पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' करने का आरोप लगाते हुए जयराम ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया गया है।

जयराम रमेश बोले- यह जबरन वसूली का सबसे बड़ा रैकेट

कहा-इसका जवाब दें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनावी बांड का ब्योरा बाहर आने से गरमाई सियासत पर रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि 2018 में शुरू की गई चुनावी बांड योजना सरकार द्वारा चलाया गया अब तक का 'सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट' था। जब यह पता चला कि भाजपा ने चुनावी बांड से करीब 6,800 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं, जबकि कांग्रेस को 1300 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए। जयराम ने दावा किया कि 2018 में वित्त मंत्रालय ने जिन 19 कंपनियों को 'उच्च जोखिम' के रूप में चिह्नित किया था, उन्होंने सामूहिक रूप से 2717 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे। बांड खरीदने वाली इन 19 में से 18 कंपनियां 'उच्च जोखिम' वाली कंपनियों की बाद की वार्षिक सूची में शामिल नहीं थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें सत्तारूढ़ भाजपा के खजाने में योगदान के कारण इस सूची से हटाया गया था। कांग्रेस महासचिव ने दोहराया कि भाजपा ने धन उगाही के लिए चुनावी बांड के जरिये चार तरीकों से घोटाले को अंजाम दिया जिसमें पहला तो 'चंदा दो-धंधा लो' था, दूसरा तरीका हफ्ता वसूली था जिसमें कंपनियों पर छापेमारी के बाद चुनावी बांड खरीदे गए। तीसरा तरीका कांट्रेक्ट लो-रिश्वत दो था। इसमें भाजपा सांसद को कांट्रेक्ट मिला और उसने चुनावी बांड खरीदा। चौथा तरीका शेल कंपनी बनाओ और चंदा देते जाओ था। पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना होगा। जिन कंपनियों का मुनाफा 20 करोड़ रुपये है, वे 400 करोड़ का चुनावी बांड खरीदती हैं।

****

270 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बिहार में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इन सभी पेपर लीक मामले में शुक्रवार को हजारीबाग में पकड़ा था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 18 मार्च, 2024

छात्रावास में नमाज पढ़ने के दौरान विदेशी छात्रों पर हमला

गुजरात विश्वविद्यालय ▸ शनिवार रात की घटना, दो आरोपित गिरफ्तार

कुछ लोगों ने नमाज पढ़ रहे छात्रों से मस्जिद जाने को कहा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

अहमदाबाद में कुछ लोगों ने गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रावास में नमाज पढ़ने के दौरान विभिन्न देशों के छात्रों पर हमला कर दिया। शनिवार रात को हुई इस घटना के बाद श्रीलंका और ताजिकिस्तान के एक-एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो आरोपितों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने बताया कि 20-25 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। घटना की जांच को सुरक्षाकर्मियों के नौ दल गठित किए गए हैं।

मलिक ने बताया कि घटना की सूचना शनिवार रात करीब 10.50 बजे मिली, जब करीब दो दर्जन लोग गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रावास में घुस गए। उन्होंने अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा अन्य देशों के छात्रों

अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय छात्रावास में नमाज पढ़ने के दौरान विभिन्न देशों के छात्रों पर हमला करते कुछ लोग। (स्क्रीन ग्रैब)। प्रेट्र

द्वारा छात्रावास में नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई और उनसे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कहा। उनकी इस मुद्दे पर बहस हुई और उन्होंने उनसे मारपीट की तथा पथराव किया। पुलिस उपायुक्त तरुण दुग्गल ने बताया कि पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात विश्वविद्यालय में करीब 300 विदेशी छात्रों ने नामांकन करवाया है। करीब 75 विदेशी छात्र विश्वविद्यालय के ए-ब्लाक छात्रावास में रहते हैं, जहां यह घटना हुई।

हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई : भारत सरकार ने रविवार को कहा कि अहमदाबाद के एक विश्वविद्यालय में हिंसा करने वालों के खिलाफ गुजरात सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंसा में घायल दो विदेशी छात्रों में से एक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, कल गुजरात विश्वविद्यालय में हिंसा की घटना हुई। विदेश मंत्रालय राज्य सरकार के साथ संपर्क में है।

विहिप ने दिल्ली में खोला पहला सीएए सहायता केंद्र

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लागू होने के बाद से पड़ोसी देशों से आए सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई शरणार्थियों के लिए आनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। शरणार्थियों की सहायता के लिए विश्व हिंदू परिषद की देशभर में एक हजार से अधिक सीएए सहायता केंद्र खोलने की तैयारी है। पहला केंद्र राष्ट्रीय राजधानी के आदर्श नगर स्थित पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की बस्ती में खोला गया है। दिल्ली में कुल पांच सीएए सहायता केंद्र खोले जाएंगे।

विहिप के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक, इन केंद्रों में आवेदकों को बताया जाएगा कि नागरिकता के आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की जरूरत है। दस्तावेज नहीं हैं तो आवेदन कैसे होगा आदि। यह केंद्र शरणार्थियों को ठगी से बचाने में भी सहायक होगा, क्योंकि नागरिकता दिलाने को लेकर ठगी की भी आशंका है। विहिप के दिल्ली मंत्री सुरेंद्र गुप्ता के अनुसार, ऐसे कुछ मामले पूर्व में आ चुके हैं। इसलिए इन केंद्रों से शरणार्थियों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहायता में वे स्वयंसेवक तैनात हैं, जो शरणार्थियों के बीच पहले से कार्य कर रहे हैं।

तृकां को झूठा साबित करने को नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे केंद्रीय मंत्री

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद मतुआ समुदाय (देश विभाजन के बाद बांग्लादेश से बंगाल आए हिंदू शरणार्थी) से आने वाले केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था कि वह नए कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके माता-पिता और वह खुद इसी देश में पैदा हुए हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही इस कानून की आलोचना करती रही है। उसका दावा है कि सीएए लागू होने के बाद सभी पहचान पत्र रद कर दिए जाएंगे और सरकारी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वह तृकां के इस दावे को झूठा साबित करने के लिए नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। अगर किसी के पास बांग्लादेश का कोई दस्तावेज है तो उसे आवेदन के साथ जमा किया जाना चाहिए। अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है।

ममता के खिलाफ थाने में शिकायत : उधर, सीएए के दुष्प्रचार को लेकर उत्तर 24 परगना जिले के बागदा निवासी गोपाल गोवाली ने बागदा थाने में

तृकां का दावा- सीएए लागू होने से सभी पहचान पत्र कर दिए जाएंगे रद

शांतनु ठाकुर। फाइल

मुख्यमंत्री ममता के खिलाफ शिकायत दी है। कहा है कि मुख्यमंत्री सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने के साथ उन्हें उकसा भी रही हैं। इससे राज्य में अशांति पैदा हो सकती है।

पाकिस्तान के पूर्व विधायक ने किया सीएए का समर्थन : वहीं, खन्ना (लुधियाना) से जागरण संवाददाता के मुताबिक, पाकिस्तान में विधायक रहे बलदेव सिंह ने सीएए का समर्थन किया है। उन्होंने इस कानून का विरोध करने वालों को सलाह दी है कि मुस्लिम देशों में जाकर अल्पसंख्यकों की हालत देखें। खैबर पख्तूनख्वा तीय एसेंबली के सदस्य रहे बलदेव सिंह वर्ष 2019 में पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे।

केरल ने सुप्रीम कोर्ट से की सीएए पर रोक लगाने की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : केरल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है और दलील दी है कि ये नियम भेदभावपूर्ण, मनमाने और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

शीर्ष कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निस्तारण होने तक केंद्र को सीएए नियमावली, 2024 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया था। न्यायालय इस मामले पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा।

ओवैसी ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया : आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

नई सरकार के पहले सौ दिन व पांच वर्षों का रोडमैप बनाएं मंत्री : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने मंत्रियों से कहा कि वे नई सरकार के लिए पहले सौ दिनों और अगले पांच वर्षों के लिए रोडमैप का मसौदा तैयार करें। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा करने के लिए कहा कि नई सरकार के पहले 100 दिन और अगले पांच वर्षों के एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। यह बैठक निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद हुई है।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को निर्वाचन आयोग की सिफारिश भेजकर सात चरण के संसदीय चुनावों की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू की। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान के लिए पहली अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही किसी विशेष चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

कहा, अपने-अपने मंत्रालयों के सचिवों व अधिकारियों से मुलाकात कर करें चर्चा

अधिसूचना के लिए कैबिनेट ने राष्ट्रपति को भेजीं लोकसभा चुनावों की तिथियां

नरेन्द्र मोदी। फाइल

प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ने तीन मार्च को 'विकसित भारत : 2047' के लिए विजन डाक्यूमेंट और अगले पांच वर्षों के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर मंथन किया था। दिनभर चली बैठक के दौरान जून में नई सरकार बनने के बाद उठाए जाने वाले कदमों के सौ दिनों के एजेंडे पर विचार-विमर्श किया गया था।

पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 15 से 31 मई तक होगी सीयूईटी-यूजी

नई दिल्ली, प्रेट्र : संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा- स्नातक (सीयूइटी-यूजी) पूर्व घोषित कार्यक्रम 15 मई से 31 मई 2024 के बीच होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने रविवार को घोषणा की कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की वजह से इस परीक्षा के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा के लिए समय-सारिणी जारी की जाएगी।

यूजीसी अध्यक्ष ने कहा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई, 2024 के बीच सीयूईटी-यूजी का आयोजन करेगी। इस अवधि में परीक्षा की दो तारीखें 20 और 25 मई चुनाव की तारीखों के साथ पड़ेंगी। उन्होंने बताया, आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2024 है। इसके बाद हमें सीयूईटी-यूजी के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या का पता चल पाएगा। इन आंकड़ों और चुनाव की तारीखों के आधार पर एनटीए, सीयूईटी-यूजी के लिए समयसारिणी की घोषणा करेगी। लेकिन तारीखें नहीं बदलेंगी।

मथुरा के लाडलीजी मंदिर में भीड़ के दबाव से टूटी रेलिंग, दो दर्जन श्रद्धालु दबे

जागरण संवाददाता, बरसाना (मथुरा)

बरसाना में लड्डू होली के दौरान हुआ हादसा, पांच की हालत गंभीर

घटना के बाद अफरातफरी, दो घंटे तक न मिल सका उपचार, तड़पते रहे घायल

मथुरा : बरसाना के लाडलीजी मंदिर में भगदड़ के दौरान दबे श्रद्धालुओं का हाल। दबे श्रद्धालुओं को निकालते लोग। वीडियो ग्रैब

विश्वविख्यात लाडलीजी मंदिर की लड्डू होली में उमड़ी भीड़ से पुलिस-प्रशासन की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। भीड़ के दबाव में मंदिर की सीढ़ियों पर लगी रेलिंग टूट गई और दो दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु नीचे गिरकर दब गए। दो घंटे तक घायल श्रद्धालु तड़पते रहे, लेकिन उन्हें उपचार नहीं मिल सका। शाम छह बजे घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। घायलों में पांच की हालत गंभीर है।

रविवार को लाडलीजी मंदिर में लड्डू होली का आयोजन था। शनिवार रात से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। सुबह से दर्शन चलते रहे। दोपहर दो बजे मंदिर के पट बंद हो गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अंदर रह गए। शाम चार बजे से लड्डू होली के लिए मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा हो गए। शाम चार बजे जैसे ही मंदिर के पट खुले तो मुख्य गेट की सीढ़ियों पर लगी रेलिंग भीड़ के दबाव में टूट गई। इससे तमाम श्रद्धालु नीचे गिरकर दब गए। काफी देर बाद श्रद्धालुओं को सीढ़ियों के समीप से उठाकर राधारानी रसोई, मंदिर हाल तथा सीढ़ियों के पास पहुंचाया गया। शाम छह बजे बाद घायलों को बरसाना सीएचसी पर लाया गया और फिर उपचार मिल सका। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि भीड़ के दबाव में तीन लोग घायल हो गए हैं, उन्हें इलाज दिया गया है। बाकी भीड़ नियंत्रित है। श्रद्धालुओं को आराम से दर्शन कराए जा रहे हैं।

लड्डू लूटने की होड़ : बताते हैं मंदिर के पट खुलते ही लड्डू की होली शुरू हो गई। मंदिर की सीढ़ियों पर पहले से खड़े श्रद्धालु लड्डू लूटने में लग गए। इसी दौरान सीढ़ियों की रेलिंग टूट गई। गेट के समीप स्थित सफेद छतरी पर आधा दर्जन पुलिसकर्मी तैनात थे। गिरे श्रद्धालु चीखते रहे, लेकिन पुलिसकर्मी लड्डू लूटने में मस्त रहे। घायल श्रद्धालुओं को नहीं उठाया।

संदेशखाली में स्थानीय लोगों का फिर विरोध प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के संदेशखाली में कुछ इलाकों में रविवार को फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों ने तीन और तृणमूल कांग्रेस नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इन तीन नेताओं में एक सत्तारूढ़ पार्टी के ग्राम पंचायत प्रमुख हाजी सिद्दीक मोल्ला व उसके सहयोगी जुल्फिकार मोल्ला और हासेम मोल्ला शामिल हैं। ये सभी निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। शाहजहां फिलहाल सीबीआइ की हिरासत में है। इन नेताओं के खिलाफ ग्रामीणों की कृषि भूमि को जबरन हड़पने, खारे पानी प्रवाहित करके कृषि भूमि को अवैध रूप से मछली पालन के फार्म में बदलने और महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप हैं।

ताजा विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब एक दिन पहले ही सीबीआइ ने शाहजहां के छोटे भाई शेख आलमगीर और उसके दो सहयोगियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने यह मूल्यांकन करने को एक समिति बनाने का निर्णय लिया है कि जमीन को कैसे फिर से खेती योग्य बनाया जा सकता है।

काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह हिंदुओं को सौंप देना चाहिए : केके मुहम्मद

शैलेश अस्थाना, वाराणसी

अयोध्या विवाद के हल में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के पूर्व अधिकारी पद्मश्री केके मुहम्मद ने कहा कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। यह स्पष्ट दिखता है। मुसलमानों को चाहिए कि इन्हें हिंदुओं को सौंपकर भाईचारे का परिचय दें। यह भी कहा कि अयोध्या में उत्खनन के बाद सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी वामपंथी इतिहासकारों ने झूठे नैरेटिव गढ़े। विशेष रूप से इरफान हबीब और उनकी टीम ने। दुर्भाग्य यह कि कांग्रेस की सरकार ने उस कट्टरपंथी टीम को खूब बढ़ावा दिया।

मुहम्मद बीएचयू के कला-इतिहास विभाग में आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के लिए काशी आए थे। दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि ऐसा कहा गया कि अयोध्या में हुई खोदाई में एएसआइ के महानिदेशक रहे प्रो.

ख्यात पुरातत्वविद ने कहा, अयोध्या को लेकर वामपंथी इतिहासकारों ने गढ़े झूठे नैरेटिव

कुतुबमीनार नहीं, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनी है मंदिर तोड़कर

केके मुहम्मद ने कहा कि उप्र, मप्र, राजस्थान में 200 से अधिक मस्जिदें हैं, जिन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। बिहार में इनकी संख्या अधिक नहीं है। कई बौद्ध स्तूपों को दरगाह में बदला गया। कुतुबमीनार भी क्या हिंदू मंदिर था, इस सवाल पर कहा कि कुतुबमीनार नहीं, बल्कि उसके बगल में बनी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। कुतुबमीनार इस्लामिक संरचना है।

बीबी लाल को कुछ मिला ही नहीं। तब उन्होंने मीडिया को बताया कि वह अकेले मुस्लिम थे जो अयोध्या में हुए उत्खनन में शामिल थे और वहां मंदिर होने के तमाम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद भी नवंबर, 2019 में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने से एक माह पूर्व इरफान हबीब और एएमयू के इतिहासकार नदीम रिजवी ने लिखा कि केके मुहम्मद झूठ बोलता है। वह उत्खनन में शामिल नहीं था। तब बीबी लाल सर ने जवाब दिया कि वह मेरे साथ था।

इस्लामिक शिक्षा बनाती है कट्टर : मंदिरों को ध्वंस कर मस्जिद बनाने के पीछे उन्होंने इस्लामिक शिक्षा को दोषी बताया। कहा, मुसलमानों को शुरू से पढ़ाया जाता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बाकी सब काफिर हैं। उनको मुसलमान बनाना भी हमारा फर्ज है। मदरसों का पाठ्यक्रम बदलना चाहिए। दीनी तालीम की जगह आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए तभी माहौल बदलेगा। सच बोलने का कीमत अदा करने पर कहा कि आज भी केरल में अपने घर में सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा के दायरे में रहता हूं। मेरे खिलाफ फतवा है कि कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। मृत देह मेडिकल कालेज को दान दूंगा।

आइएफएस संजीव चतुर्वेदी मामले की सुनवाई को विशेष पीठ का गठन

जागरण संवाददाता, नैनीताल : केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) के चेयरमैन जस्टिस रंजीत मोरे ने आइएफएस व मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान) संजीव चतुर्वेदी के सेवा से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया है। इस पीठ के गठन की अधिसूचना 15 मार्च को जारी की गई है। पीठ में न्यायिक सदस्य जस्टिस राजीव जोशी व प्रशासनिक सदस्य दिल्ली बेंच के एएस खाती होंगे। मामले की सुनवाई नैनीताल सर्किट बेंच में होगी।

आइएफएस संजीव नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति संबंधित कमेटी ने संयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर के अधिकारी पद पर इंपैनलमेंट में आइएफएस संजीव के नाम को खारिज कर दिया था। संजीव चतुर्वेदी ने कमेटी की ओर से उनका नाम खारिज करने का आधार बनाई गई मूल्यांकन रिपोर्ट दिलाने की प्रार्थना की थी। इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में चार याचिकाएं व दो अवमानना याचिका भी दायर हो चुकी हैं।

झारखंड पीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न, पेपर लीक के आरोप

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को विभिन्न जिलों के 834 केंद्रों पर संपन्न हो गई। आयोग के अनुसार कुछ केंद्रों पर अभ्यर्थियों के हंगामे को छोड़कर अन्य केंद्रों पर परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण हुई है। हालांकि, जामताड़ा तथा चतरा के एक-एक केंद्र पर पेपर लीक होने के आरोप लगे। इंटरनेट पर कथित रूप से जामताड़ा का एक वीडियो भी तेजी से प्रसारित हुआ जिसकी जांच के आदेश जिले के उपायुक्तों ने दिए हैं।

इधर, आयोग ने जामताड़ा तथा चतरा समेत सभी जिलों के उपायुक्त से इसपर रिपोर्ट मांगी है। आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह के अनुसार उपायुक्तों की रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर विधिसम्मत निर्णय होगा। परीक्षा के जिला नोडल पदाधिकारी अरविंद कुमार ने पेपर लीक होने के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि प्रश्नपत्र पैकेट केंद्र अधीक्षक व अन्य की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते

परीक्षा का वहु प्रसारित वीडियो, जिसमें कुछ परीक्षार्थी मोवाइल की मदद से आंसरशीट भरते दिख रहे हैं। स्रोत : इंटरनेट मीडिया

हुए खोला गया। जामताड़ा की उपायुक्त कुमुद सहाय के अनुसार एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसे जामताड़ा का वीडियो बताया जा रहा है। जांच के लिए एसआइटी गठित की गई है।

बीपीएससी ने ईओयू से पेपर लीक के मांगे सुबूत

जागरण संवाददाता, पटना : बिहार में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-3.0) के प्रश्नपत्र लीक को लेकर अब आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) आमने-सामने हो गए हैं। बीपीएससी ने ईओयू से पेपर लीक होने से संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग की है। इसके बाद आयोग परीक्षा को लेकर कोई निर्णय लेगा।

विदित हो कि एक दिन पूर्व ईओयू ने टीआरई 3.0 के पेपर लीक होने के संदर्भ में आयोग को साक्ष्य सौंपा था। इस मामले में 270 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ईओयू की ओर से 16 मार्च को एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। इसकी समीक्षा में यह बात सामने आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

जागरण विशेष कर्मठ किसान

संकल्प को सरकारी योजनाओं का मिला साथ तो बनी बात

उप्र के चाऊपुर होज के किसान ने नवाचार से पेश की सुनहरी तस्वीर, एफपीओ का व्यापार 25 गुना तक बढ़ा, अब निर्यात की तैयारी

लोकेश शर्मा ● अलीगढ़

हरित क्रांति के सुखद आगाज की तस्वीरें खेतों में नजर आ रही हैं। सरकारी योजनाओं के सहारे किसान न सिर्फ अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं बल्कि, नवाचार की सुनहरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से संगठित हुए किसानों ने नए आयाम गढ़े हैं। एफपीओ शक्ति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का व्यापार पिछले तीन वर्ष में 25 गुना बढ़ा है। एफपीओ निदेशक बबलू शर्मा ने अपना ब्रांड बनाकर बाजार में कृषि उत्पाद उतारे हैं। अब इनके निर्यात की तैयारी है।

उप्र में अलीगढ़ जनपद की तहसील अतरौली के गांव चाऊपुर होज के किसान बबलू शर्मा ने सितंबर, 2021 में 10 किसानों को जुटाकर एफपीओ (शक्ति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी) का गठन किया था। तब 25-30 हेक्टेयर

फसल का निरीक्षण करते संयुक्त कृषि निदेशक राकेश बाबू (बाएं से तीसरे) ● सौ. एफपीओ

> एफपीओ के माध्यम से किसान उचित मूल्य में कृषि उत्पाद बेच रहे हैं। सरकारी योजनाओं में एफपीओ को प्राथमिकता दी जाती है। अनुदान पर कृषि यंत्र, बीज, खाद आदि के अलावा सीड्स प्लांट, फ्लोर मिल, मिलेट मिल, प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए भी सरकार सहयोग कर रही है।
>
> **- यशराज सिंह**, उप कृषि निदेशक

में खेतीबाड़ी थी। धीरे-धीरे अन्य किसान भी एफपीओ से जुड़ते गए। अब इस समूह में 400 किसान हैं, जो 800 हेक्टेयर में गेहूं, धान, बाजरा, सब्जियां, दहलन व तिलहन की फसलें उगा रहे हैं। बबलू बताते हैं कि एफपीओ में सभी किसानों की हिस्सेदारी है। बाजार से अधिक मूल्य पर किसानों से कृषि उत्पाद खरीद कर बड़े व्यापारी व कंपनियों को बेचा जाता है। कृषि कार्य के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदकर किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। उच्च कोटि के बीज और खाद भी दिया जाता है। कृषि अधिकारी व कृषि विज्ञानी समय-समय पर फसलों का निरीक्षण करते हैं। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वे बताते हैं कि शुरुआत में दो लाख रुपये का सालाना टर्नओवर था, जो बढ़कर 50 लाख रुपये के करीब पहुंच गया है।

निर्यात की तैयारी : एफपीओ ने कृषि उत्पाद के निर्यात की तैयारी कर ली है। डायरेक्टर जनरल आफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) व एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी (एपीडा) से लाइसेंस मिल चुका है। डीजीएफटी के लाइसेंस पर किसी भी देश में निर्यात किया जा सकता है। जबकि, एपीडा सोर्स बताता है कि किस देश में डिमांड है। बबलू कहते हैं कि जल्द ही निर्यात क्षेत्र में आएंगे। इससे किसानों को और अधिक लाभ होगा।

बाजार में उतारा उत्पाद : किसान समूह ने शक्ति एफपीओ, नाम से बाजार में कृषि उत्पाद उतारा है। आटा, चावल, बेसन, तेल, बाजरा आदि उत्पाद बाजार में हैं। अन्य जिलों में भी सप्लाई होती है। किसान इनकी आनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं।

अनुदान पर मिले कृषि यंत्र : एफपीओ को 40 से 50 प्रतिशत सरकारी अनुदान पर कृषि यंत्र मिले हैं। इनमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, सुपर सीडर, ट्रिलर, मल्टी प्लाऊ, जीरो ड्रिल आदि हैं। कृषि कार्य के लिए किसानों को ये यंत्र निश्शुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

मेटलिब में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी राजकीय लाइब्रेरी प्रयागराज

अमरदीप भट्ट, प्रयागराज

नीदरलैंड की संस्था इफ्ला ने किया है दुनिया के 15 लाइब्रेरियन की टीम का चयन

प्रयागराज की राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी से डा. गोपाल मोहन शुक्ला ने बनाया कीर्तिमान

विश्वस्तरीय उपलब्धियों में प्रयागराज ने अपने खाते में एक और कीर्तिमान बनाया है। यहां की राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी (पुस्तकालय) का चयन पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की सर्वोच्च संस्था इफला यानी इंटरनेशनल फेडरेशन आफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ने ग्लोबल प्रोजेक्ट 'मेटलिब' (मेट्रोपोलिटन सिटी लाइब्रेरी) के लिए किया है। इस संस्था का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है।

इफ्ला ने इस प्रोजेक्ट के लिए दुनियाभर में 15 लाइब्रेरी का चयन किया है, जिसमें भारत से राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी एकमात्र है। यह प्रोजेक्ट नौ अप्रैल से मार्च 2025 तक चलेगा।

राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन/अध्यक्ष डा. गोपाल मोहन शुक्ला ने बताया कि इफला ने उन मेट्रोपोलिटन शहरों की लाइब्रेरी से प्रस्ताव मांगे थे, जहां की आबादी चार लाख या इससे ज्यादा है। बर्चुअल पूछा गया था कि ऐसे मेट्रोपोलिटन शहरों की लाइब्रेरी में पुस्तकों व पत्रिकाओं को सुव्यवस्थित रखने, आधुनिक दौर की जरूरतें पूरा करने में किस वैज्ञानिक तरीके से काम किया जा सकता है। राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ से डा. गोपाल मोहन शुक्ला ने भी प्रस्ताव भेजा था। उनके प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इफ्ला ने विश्व के 15 लाइब्रेरियन की सूची में उन्हें भी शामिल कर लिया।

****

चुनावी चंदा कितना चंगा !

भारत जैसे बहुदलीय लोकतंत्र में चुनावी चंदे की अहम भूमिका है। राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए चंदे की जरूरत होती है। देश की आजादी के बाद कई दशकों तक नेता और राजनीतिक दल आम लोगों से चंदा जुटाते थे। इसके अलावा औद्योगिक घराने भी राजनीतिक दलों को चंदा देते थे। उदारीकरण के बाद कारपोरेट का उभार हुआ और राजनीतिक चंदे का बड़ा हिस्सा निजी कंपनियों से आने लगा। हालांकि, चुनावी चंदे के तौर-तरीकों पर सवाल भी उठते रहे हैं, क्योंकि इसमें पारदर्शिता का अभाव था। पहले नियम था कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम के चंदे का हिसाब नहीं देना है। राजनीतिक दल इस नियम का फायदा उठा कर चंदे के बड़े हिस्से को 20,000 रुपये से कम राशि में दिखा देते थे। इस तरह के आरोप भी लगे कि कारपोरेट राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और सत्ता में आने पर राजनीतिक दल कारपोरेट के हितों को आगे बढ़ाते हैं। इससे बचने के लिए यह विचार भी आया कि राजनीतिक दलों का चुनाव पर होने वाला खर्च सरकार उठाए। ऐसे परिदृश्य में मोदी सरकार 2017 में चुनावी चंदे के लिए चुनावी बांड योजना लेकर आई। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस समय कहा था कि देश 70 साल में राजनीतिक चंदे के लिए कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं बना पाया है। चुनावी बांड योजना इस कमी को पूरा करेगी। हाल में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनावी चंदे की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए?

चंदे की आदर्श व्यवस्था के लिए प्रयास जरूरी

ओपी रावत
पूर्व, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

विश्व के लोकतांत्रिक देशों में चुनावी चंदे की आदर्श व्यवस्था के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमें भी हताश हुए बिना इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, जिससे राजनीतिक दलों की जरूरतें भी पूरी हों और कानूनों के अनुपालन के साथ आम जनता के अधिकार भी सुरक्षित रहें।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर साबित किया है कि वह हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और सुरक्षित रखने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। चुनावी बांड मामले में दिखाई गई सख्ती और निर्णय ने चुनावी चंदे के माध्यम से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (विदेशी स्रोतों से राजनीतिक चंदे की मनाही) और मनी लांड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) के उल्लंघन की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है।

परंतु भारतीय लोकतंत्र की अपनी अलग समस्या है। एक लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख तक मतदाता हो सकते हैं। लोकसभा क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल भी काफी बड़ा होता है। किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को अपनी नीतियों, घोषणा पत्र और कार्यक्रमों की जानकारी इतने बड़े क्षेत्र में और इतने मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए कई माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है और यह सभी माध्यम खर्चीले हैं। तकनीकी विकास से नए-नए तरीके भी उपलब्ध हो रहे हैं, परंतु सभी व्यय साध्य हैं। चुनाव में जीत की संभावना का पता लगाने के लिए राजनीतिक दल बड़ी डाटा कंपनियों से शोध और सर्वे भी कराने लगे हैं। इससे उन्हें जीतने योग्य उम्मीदवार की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे यह भी पता चल जाता है कि मतदाताओं का कौन सा वर्ग किस मुद्दे को लेकर पार्टी से नाराज है। यदि यह मतदाता वर्ग उनकी जीत के लिए जरूरी है तो सरकार में रहते हुए दल अपनी सरकार से ऐसे निर्णय तुरंत करा देते हैं, जो असंतोष दूर कर दें तथा विरोधी पक्ष के लोग उस वर्ग के हित में तुरंत निर्णय लेने का वचन देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) का उदय तथा इंटरनेट मीडिया की बढ़ती पहुंच भी राजनीतिक दलों को अपनी ओर खींचती है और नए चुनावी खर्च का द्वार खोलती है। इन परिस्थितियों में बिना पर्याप्त चुनावी चंदे के चुनाव लड़ना और जीतना असंभव सा है। उम्मीदवार के चुनाव खर्च में अधिकतम सीमा (सीलिंग) है, परंतु राजनीतिक दल के खर्च पर कोई बाध्यकारी सीमा नहीं है। इससे भी चुनावी खर्च सतत आसमान की ओर बढ़ रहा है।

ऐसे समय में चुनावी बांड ने एक बात तो साबित कर दी है कि कारपोरेट से चुनावी चंदा दलों तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी माध्यम खोज लिया गया है। लगभग पांच वर्ष में 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का चंदा सभी दलों को मिला है। परंतु न तो आम मतदाता के अधिकारों का संरक्षण हुआ और न ही देश के कानून का पालन ही सुनिश्चित हो सका। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक और जानकारी देने का आदेश दिया है। स्टेट बैंक से यह जानकारी आने पर और भी बातें स्पष्ट हो सकेंगी। अतः हमें यह सोचना होगा कि नए विकल्प खोजे जाएं या चुनावी बांड योजना में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई त्रुटियों का परिमार्जन सुनिश्चित करते हुए, भविष्य में किसी कानून के उल्लंघन की संभावना को खत्म किया जाए।

इसके लिए संस्थाओं और संस्थागत कर्मियों के आंतरिक चरित्र को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। बैंकर्स का काम जमा जुटाना और कर्ज देकर देकर आय अर्जित करना है। ऐसे लोगों पर यह जिम्मेदारी डालना कि वे केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि खरीदार ने बांड लेते समय न तो विदेशी धन का उपयोग किया है और न ही बांड को काले धन के माध्यम से प्रीमियम पर अन्य व्यक्ति/कारपोरेट को ट्रांसफर किया है, व्यावहारिक नहीं है। विश्व में सभी लोकतंत्र चुनावी चंदे के लिए आदर्श व्यवस्था की खोज में प्रयासरत हैं और सतत प्रयोग हो रहे हैं। हमें भी इस दिशा में हताश हुए बिना प्रयास करना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों की आवश्यकता पूरी होती रहे और मतदाता के अधिकार सुरक्षित रखते हुए देश के सभी कानूनों का कड़ाई से पालन होता रहे। साथ ही चुनाव खर्च पर लगाम लगाने के लिए भी हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए।

आपकी आवाज

राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च क्यों उठाए? क्या चुनावी चंदा देकर देश में आर्थिक भ्रष्टाचार के बढ़ने की संभावना नहीं रहती? जो लोग जिस राजनीतिक दल को चंदा देते हैं क्या उस दल की सरकार बनने पर वो उन लोगों के आर्थिक भ्रष्टाचार या कालेधन के कामों पर पर्दा नहीं डालेगी? हाल ही में राजनीतिक दलों को चंदा देने के जो आंकड़े सामने आए हैं,अगर वो सारी रकम देश में गरीबी दूर करने के लिए खर्च की जाती तो शायद बहुत से लोगों की गरीबी दूर हो जाती। कुछ छोटी-मोटी राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व में आने का कारण न तो लोकसेवा, न देश सेवा है, बल्कि कालेधन को सफेद करना है। देश आजाद होने के बाद लगभग हर पार्टी की सरकार सत्ता मे आई लेकिन किसी ने भी चंदे के धंधे पर लगाम कसने की कोशिश तो क्या इसके लिए कोई इरादा भी नहीं दिखाया।

राजेश कुमार चौहान

राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च सरकार को उठाना चाहिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र चाहिए। चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों के लिए एक निश्चित राशि तय करनी चाहिए। चुनाव के समय निर्वाचन आयोग यह राशि सभी राजनीति दलों को दे। इसके पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के तहत सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रचार प्रसार की एक समान नीति बने। इससे चुनाव में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हो सकेगा। इससे देश में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होगा।

मीना धानिया

सुधारों पर जनता करे पहल

त्रिलोचन शास्त्री
चेयरमैन एडीआर और प्रोफेसर, आइआइएम बेंगलुरु

चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था का मामला चुनाव सुधारों से जुड़ा है। इस पर जरूरी सिफारिशें पहले से उपलब्ध है। लेकिन सरकारें कदम नहीं उठा रही हैं। जरूरत इस बात की है कि चुनाव सुधारों की मांग जनता की ओर से आए। तभी सरकार इस पर ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर होगी।

मीडिया में चुनावी बांड के बारे में खबरें छाई हुई हैं। लेकिन हमें इससे आगे देखने की जरूरत है क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के बारे में लोगों की जागरूकता बहुत कम है। पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि राजनीतिक दलों को चुनावी अभियान चलाने और रूटीन काम के लिए पैसे की जरूरत है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका है। हमें अच्छे, ईमानदार और सक्षम राजनीतिक दलों की जरूरत है, जो सिर्फ सत्ता हासिल करने के बजाए जनसेवा पर फोकस करें।

आइए पहले फंडिंग के मुद्दे पर कुछ बुनियादी सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। पहले, चंदे के तौर पर मिली राशि वैध होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई विदेशी पैसा और काला धन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चंदे की रकम के बदले किसी तरह का लाभ लेने की मंशा नहीं होनी चाहिए, न ही राजनीति दल या सरकारें चंदा देने वालों को बदले में किसी तरह का लाभ पहुंचाएं। चुनावी चंदा देने वाले सरकारों से कई तरह से फायदे लेते हैं। यह सरकारी ठेके हो सकते हैं, खनन, जुआ, अवैध शराब के व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों को नजरअंदाज करना हो सकता है। इसके अलावा बड़ी कंपनियों को टैक्स से जुड़े फायदे, बड़े दानदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियों और कानून में बदलाव, पर्यावरण मंजूरी देना या बड़े सरकारी ठेके देना भी ऐसे तरीकों में शामिल है। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि आम तौर पर ये सभी फायदे आम जनता के हितों के खिलाफ होते हैं। अगर सत्तारूढ़ दल ने चंदा लिया है तो सामान्य तौर पर सरकारें ये सभी फायदे देती हैं। तीसरा सिद्धांत बराबरी के मौके का है। लोकतंत्र में, हर एक व्यक्ति के पास एक वोट है। लेकिन हर एक व्यक्ति राजनीति में नहीं जा सकता है और न ही चुनाव लड़ सकता है। चुनाव में इतनी अधिक रकम की जरूरत होती है कि 99 प्रतिशत नागरिक चुनाव लड़ने का खर्च नहीं उठा सकते।

किस हद तक बराबरी का मौका होना चाहिए या किस हद तक यह संभव है, इस पर बहस होनी चाहिए। अब बात करते हैं काले धन और विदेशी पैसे की। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान 3,450 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए। ये एक रिकार्ड है। यह नोटबंदी के बाद हुआ था। माना गया था कि नोटबंदी काले धन को खत्म कर देगी। जब्त की गई रकम चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले काले धन का अंश मात्र है। 2018 में शुरू किए गए आनलाइन पेमेंट, चुनावी बांड इस काले धन पर रोक नहीं लगा सके। चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल को नई योजनाओं और कानूनों से नहीं रोका जा सकता है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को चुनाव के पहले ही काले धन की पहचान करके जब्त करने की जरूरत है। आम तौर पर एजेंसियों को इसकी जानकारी होती है लेकिन ये कदम नहीं उठाती हैं। चेक और आनलाइन पेमेंट के जरिये विदेश से पैसा आना संभव नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक हो जाएगा और यह अवैध भी है। अगर हवाला के जरिये विदेश से पैसा आता है तो हमें इसे ट्रेस करने और इस पर रोक लगाने के लिए अलग जांच एजेंसी की जरूरत है।

जहां तक एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का सवाल है, तो विश्व के दूसरे लोकतांत्रिक देशों में चुनावी चंदे के लिए बेहतर तरीके अपनाए जाते हैं। पहली बात, इन देशों में पार्टी फंडिंग पूरी तरह से पारदर्शी होती है। मतदाता जानता है कि किस पार्टी या उम्मीदवार को किसने कितना चंदा दिया है। दूसरी बात, इन देशों में कंपनियों या लोगों के लिए चंदा देने की एक अधिकतम सीमा है। आज भारत में 186 लोग हैं, जो फोर्ब्स की अरबपति की सूची में हैं। ऐसे लोग व्यक्तिगत चंदा देकर या अपनी कंपनियों के जरिये उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को प्रभावित कर सकते हैं। एक उद्योगपति ने एक राजनीतिक दल को अपनी दुकान बताया था। ऐसे में एक व्यक्ति और कारपोरेट कितना चंदा दे सकता है, इसकी एक अधिकतम सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा नागरिकों और सरकारी एजेंसियों को हर चुनाव और प्रमुख नीतिगत घोषणाओं के बाद इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसी कंपनी या व्यक्ति को गलत तरीके से फायदा तो नहीं पहुंचाया गया है। चुनावी बांड के आंकड़े बताते हैं कि लाटरी कंपनी ने 1,300 करोड़ से अधिक का चंदा दिया है और कंपनी वर्षों से इनकम टैक्स विभाग की जांच के घेरे में है। पहले इस कंपनी का नाम भी ज्यादा नहीं सुना गया है। ऐसा गोपनीयता की आड़ में ही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता के इस आवरण को हटा दिया है।

बराबरी के मौके के सवाल की बात है तो हमें पब्लिक फंडिंग पर बात करनी होगी। पब्लिक फंडिंग का मतलब है कि सरकार राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च का एक हिस्सा वहन करे। अनुमान है कि भारत में 2019 लोकसभा चुनाव में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में अधिक पैसा खर्च हुआ था। यूरोप के ज्यादातर देशों में पब्लिक फंडिंग होती है। अमेरिका के कई राज्यों में भी ऐसा होता है। लेकिन भारत में ऐसा तभी किया जा सकता है जब पहले के सुधारों को कड़ाई से लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजनीतिक दल चुनाव में काला धन, उद्योगपतियों के पैसे के साथ सरकारी खजाने का पैसा भी खर्च करेंगे। हालांकि कुछ हद तक पब्लिक फंडिंग स्वच्छ छवि वाले और ईमानदार व्यक्तियों को चुनाव लड़ने में सक्षम बना सकती है। इसके अलावा चुनावी खर्च की एक अधिकतम सीमा तय करने की जरूरत है, जो वास्तविकता के करीब हो। वर्तमान में राजनीतिक दलों पर चुनावी खर्च को लेकर कोई बंदिश नहीं है। हालांकि उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा है। इस तरह की अधिकतम सीमा उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को एक हद तक बराबरी का मौका देगी। इस पर कदम उठाने की जरूरत है।

दूसरे लोकतांत्रिक देशों में चंदा कैसे जुटाती हैं पार्टियां

विश्व के दूसरे लोकलांत्रिक देशों में भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाते हैं। आइये जानते हैं कि इन देशों में चुनावी चंदे की व्यवस्था कैसी है और ये व्यवस्था कितनी पारदर्शी है?

जर्मनी में राजनीतिक चंदे की व्यवस्था

जर्मनी में राजनीतिक दलों की आय के तीन प्रमुख स्रोत हैं। स्टेट फंडिंग, पार्टी के सदस्यों से या निर्वाचित प्रतिनिधियों, जैसे सांसदों के वेतन से योगदान और निजी क्षेत्र से या कारपोरेट से मिलने वाला चंदा। स्टेट फंडिंग का आधार पार्टी के जनाधार को बनाना गया है। इसकी गणना आखिरी चुनावों में पार्टी को मिले वोट की संख्या, सदस्यों से मिले योगदान और चंदे के आधार पर की जाती है। इसके पीछे विचार यह है कि एक राजनीतिक दल की जड़ें समाज में जितनी गहरी हैं, उसे स्टेट फाइनेंस की उतनी अधिक जरूरत है।

क्या स्टेट फंडिंग की कोई अधिकतम सीमा है?
एक राजनीतिक दल किसी एक वर्ष में हुई अपनी आय से अधिक स्टेट फंडिंग नहीं ले सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पार्टी की 50 प्रतिशत तक आय स्टेट फंडिंग से हो सकती है। स्टेट फंडिंग की अधिकतम सीमा हर वर्ष तय की जाती है। हाल के वर्षों में यह राशि बहुत तेजी से बढ़ी है। 2010 में स्टेट फंडिंग की कुल राशि 133 मिलियन यूरो थी और 2021 के लिए यह राशि बढ़ कर 200 मिलियन यूरो से अधिक हो गई।

अमेरिका में कौन देता है चुनाव के लिए चंदा

अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है लेकिन यह सबसे महंगा लोकतंत्र भी है। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति या संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास फंड जुटाने वाले, आडिट और लीगल टीम होनी चाहिए, जो पारदर्शिता के मानकों पर खरा उतरने के लिए खर्च की गई रकम का खुलासा करने के जटिल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करा सकें। आपके पास अमीर समर्थकों का नेटवर्क भी होना चाहिए जो आपकी प्रोफाइल बनाने और आपके विपक्षी पर हमला करने के लिए असीमित राशि खर्च कर सकें।

8,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च की गई बिना हिसाब की राशि

कौन दे सकता है चंदा: यह इस बात पर निर्भर करता है कि चंदा देने वाला प्रत्यक्ष योगदान कर रहा है या अप्रत्यक्ष योगदान कर रहा है। उदाहरण के लिए- कारपोरेट उम्मीदवार के चुनाव अभियान के लिए चंदा नहीं दे सकते हैं लेकिन पीएसी को दे सकते हैं।

क्या अमेरिका में राजनीतिक चंदा पारदर्शी है?
इसका जवाब है, हां। कुछ हद तक। अगर आप किसी उम्मीदवार के चुनाव अभियान में सीधे 50 डालर से अधिक रकम प्रत्यक्ष तौर पर देते हैं तो दानदाता की पहचान और दान दी गई रकम का खुलासा फेडरल इलेक्शन कमीशन के समक्ष करना जरूरी है। अगर आप सुपर पीएसी को दान देते हैं तो भी इसकी जानकारी देना जरूरी है। लेकिन यहां भी इस बात की गुंजाइश है, जहां बिना हिसाब-किताब की रकम से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। अमेरिका में गैर लाभकारी संगठन दान देने वाले के बारे में खुलासा किए बिना राशि खर्च कर सकते हैं। अनुमान है कि 2020 के चुनाव में एक अरब डालर यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपये से अधिक बिना हिसाब वाली राशि खर्च की गई।

क्या चंदे के लिए वित्तीय सीमा है?
हां। फेडरल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध गाइडलाइंस के अनुसार, एक व्यक्ति की अभियान समिति के लिए 3,300 डालर, पालिटिकल एक्शन कमेटी (पीएसी) के लिए प्रति वर्ष 5000 डालर, 10,000 डालर पार्टी की राज्य, जिला और स्थानीय समिति के लिए योगदान कर सकता है। एक व्यक्ति पार्टी की राष्ट्रीय समिति के लिए 41,300 डालर और राष्ट्रीय समिति के लिए ही अतिरिक्त 1,23,900 डालर योगदान कर सकता है। सुपर पीएसी पर इस तरह की सीमा लागू नहीं होती है और यह असीमित योगदान ले सकती है।

ब्रिटेन में चुनावी चंदा

पालिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस एंड रेफरेंड्म्स एक्ट 2000 (पीपीईआरए) राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नियम बनाए गए हैं। नियमों के अनुसार 500 पाउंड से अधिक का कोई भी चंदा ब्रिटेन के व्यक्ति या कंपनी से ही होना चाहिए।

500 पाउंड से कम का चंदा दे सकता है विदेश से कोई व्यक्ति राजनीतिक दलों को

500 पाउंड से कम के योगदान का क्या: 500 पाउंड या इससे कम के योगदान को चंदा नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि राजनीतिक दलों के लिए इस तरह के भुगतान का रिकार्ड रखना जरूरी नहीं है। हालांकि चंदे पर नियंत्रण से बचने का प्रयास करना अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे एक से अधिक छोटे छोटे भुगतान के जरिए 500 पाउंड से अधिक चंदा देना।

क्या आप विदेश से दे सकते हैं चंदा: **नहीं।** लेकिन अगर आपका योगदान 500 पाउंड या इससे कम है तो इसे तकनीकी तौर पर चंदा नहीं माना जा सकता। इसका मतलब है कि विदेश से कोई व्यक्ति ब्रिटेन के राजनीतिक दलों को 500 पाउंड से कम चंदा दे सकता है।

राष्ट्रीय फलक

मां पर कविता लिखने वाले उनकी इज्जत भी करें : संतोष आनंद

जासं, संभल: प्रसिद्ध गीतकार संतोष आनंद का कहना है कि मां पर कविता लिखने वाले उनकी इज्जत भी करें। उन्होंने नाम न लेते हुए एक कवि का उदाहरण भी दिया। बोले, एक कवि अपनी रचना सुना रहे थे...बोले मेरे हिस्से में मेरी मां है.....। मैंने उनसे कहा,आपकी मां तो आपके छोटे भाई के साथ रहती हैं। कम से कम कविता में तो सच बोलो। अब वह कवि दुनिया में नहीं हैं।

संतोष आनंद रविवार को कल्कि धाम में होली मिलन समारोह में आए थे। उन्होंने काव्य पाठ करते हुए कई गीत सुनाए। इस बीच उनका दर्द भी छलक उठा। रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण नहीं मिलने पर अफसोस जताया। गायक सोनू निगम पर कटाक्ष करते हुए बोले, जिसने दाऊद के गुणगान में दुबई जाकर गीत गाया। उसे तिलक लगाकर बुला लिया गया। मुझे नहीं बुलाया। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को भाजपा से जुड़ा कार्यक्रम भी बताया। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि खैर मुझे तकलीफ नहीं हुई, सारे मेरे अपने हैं। मैं नफरत नहीं करता हूं, लेकिन जो जायज बात है वह कहने से नहीं चूकता हूं।

मुंबई दंगों के 32 साल बाद महाराष्ट्र सरकार की मुआवजे की कवायद

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मृतक या लापता लोगों के स्वजनों से मांगा ब्योरा
- मुआवजा देने के लिए पीड़ितों के उत्तराधिकारियों की तलाश शुरू

मुंबई, प्रेट्र: वर्ष 1992 में हुए मुंबई के सांप्रदायिक दंगों और 1993 के बम विस्फोटों के तकरीबन 32 साल बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने के लिए कदम उठाए हैं, जो इस हिंसा के दौरान मारे गए या लापता हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर, 2022 के एक आदेश के बाद पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए अपील पत्र जारी करके अगले महीने तक ब्योरा मांगा है।

14 मार्च को सरकार की तरफ से जारी पत्र में दंगों और विस्फोटों के बाद अपनी जान गंवाने वाले या लापता हुए लोगों के स्वजनों से अगले माह तक शहर और उपनगरीय कलेक्टरों के कार्यालयों से संपर्क करने का आग्रह किया गया। यह कदम नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रेरित था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को दिसंबर 1992 में सांप्रदायिक दंगों और मुंबई में मार्च 1993 में बम विस्फोटों के बीच की अवधि के मृतक या लापता व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने का निर्देश दिया गया था। बता दें दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दौरान मुंबई सांप्रदायिक तनाव और दंगों की चपेट में आने से तकरीबन 900 लोगों की मौत हुई थी और 168 से अधिक लोग लापता हो गए थे। 12 मार्च, 1993 को शहर के कई हिस्सों में 13 विस्फोट हुए, जिनमें 257 लोगों की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 1998 में राज्य सरकार ने दंगों और विस्फोटों की घटनाओं में प्रत्येक मृतक या लापता पीड़ितों के परिवारों को दो लाख रुपये का मुआवजा जारी किया।

हाल के पत्र में सरकार ने उन मृत या लापता व्यक्तियों की एक सूची जारी की जिनके कानूनी रिश्तेदारों का सरकारी वेबसाइटों पर पता नहीं चल पाया है। पत्र में कहा गया है कि सूचीबद्ध मृतकों/लापता व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सरकार से वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक दस्तावेज और पहचान प्रमाण के साथ एक महीने के भीतर मुंबई शहर और मुंबई उपनगर कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करें।

ओडिशा एसटीएफ ने दो नकली ईडी अधिकारियों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : ओडिशा पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकारी बताकर लोगों को ठगने वाले दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान तारिणी सेन और ब्रह्मशंकर महापात्र के रूप में हुई है। उनके पास से बैंक पासबुक, नकली परिचय पत्र, 17 एटीएम कार्ड सहित अन्य सामान जब्त किए गए हैं। दोनों के बैंक खाते से अब तक 16 लाख रुपये से अधिक के अवैध लेन-देन की जानकारी मिली है।

बताया गया कि दोनों भाई उन जगहों पर पहुंच जाते थे, जहां राज्य या राज्य के बाहर ईडी के छापे मारे जा रहे होते थे। इसके बाद दोनों आसपास के घरों में रहने वाले अधिकारियों के घर जांच करने पहुंच जाते थे और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर उनसे धन ऐंठते थे। दोनों भाइयों ने ठगी की इस कड़ी में अब तक 300 से अधिक अधिकारियों को फांसने का प्रयास किया था। छतरपुर के उप जिलाधिकारी देवदत्त महंत ने इस आशय की शिकायत क्राइम ब्रांच से की थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई।

पुणे में आइएस के आतंकियों की चार संपत्तियां कुर्क

- एनआइए की कार्रवाई, 11 आतंकियों पर कसा गया शिकंजा
- चारों संपत्तियों का इस्तेमाल आतंकी साजिश में हो रहा था

नई दिल्ली, एएनआइ: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने पुणे में आतंकी संगठन आइएस के माड्यूल के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एनआइए ने पुणे में आइएस के 11 आतंकियों की चार अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। जांच एजेंसी के अनुसार यह कार्रवाई देश में वैश्विक आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए की गई है।

एनआइए ने कहा कि महाराष्ट्र में पुणे के कोंढवा में कुर्क की गई संपत्तियां तीन भगोड़ों सहित 11 आतंकियों से जुड़ी हुई हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई देश में वैश्विक आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए की गई है। इन चारों संपत्तियों का इस्तेमाल आइईडी बनाने, इसके प्रशिक्षण और आतंकवादी कृत्यों की साजिश रचने के लिए किया जा रहा था।

एनआइए इस मामले में पहले ही सभी 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 25 के तहत कुर्क की गई संपत्तियां आवासीय घर और फ्लैट हैं। ये संपत्तियां आरोपित मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, मोहम्मद शाहनवाज आलम, मोहम्मद रिजवान अली, कादिर दस्तगीर पठान, सिमाब काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, अब्दुल्ला फैयाज शेख, तल्हा लियाकत खान, शमिल नाचन और आकिफ नाचन के नाम पर थी।

आइएस माड्यूल के खिलाफ कार्रवाई

यह मामला महाराष्ट्र, गुजरात और भारत के अन्य हिस्सों में विभिन्न स्थानों पर आइईडी फैब्रिकेशन ट्रेनिंग वर्कशाप के माध्यम से आतंकी गतिविधियां फैलाने की आइएस की साजिश से जुड़ा है। एनआइए ने हाल के माह में प्रतिबंधित वैश्विक आतंकी संगठनों के नेटवर्क को नष्ट करने के तहत आइएस माड्यूल पर कार्रवाई की थी। आइएस की साजिश और गतिविधियों की जांच जारी है।

अब बरसात के बाद ही दक्षिण अफ्रीका से आएंगे और चीते

नईदुनिया, मंदसौर : मप्र के मंदसौर जिले के गांधीसागर अभयारण्य में दक्षिण अफ्रीका से चीते अब बरसात के बाद ही आ पाएंगे। वनाधिकारी लोकसभा चुनाव के चलते यह प्रोजेक्ट टाले जाने की बात कह रहे हैं। बता दें कि चीता पुनर्वास परियोजना के तहत प्रथम चरण में नामीबिया से आठ और दूसरे चरण में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, जिन्हें श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। विशेषज्ञों ने कूनो में चीतों की संख्या पर्याप्त हो जाने का तर्क देते हुए तीसरे चरण में लाए जाने वाले चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में बसाने की योजना बनाई है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के भोजन के लिए हिरण-चीतल दूसरे वन क्षेत्रों से लाकर छोड़े जा रहे हैं। अभी तक 289 चीतल-हिरण छोड़े जा चुके हैं। अब गर्मी बढ़ने से हिरण पकड़ने में परेशानी होने लगी है। इसके चलते भी चीतों को लाने की तैयारी वर्षा काल तक टाले जाने की मजबूरी है। यहां 400 हिरण पकड़कर छोड़ना हैं, ताकि वह यहां के वातावरण में रमने लगें और फिर अपना कुनबा बढ़ाएं।

दैनिक जागरण

कल्पना विचार का आधार है

पारदर्शी प्रक्रिया की जरूरत

अंततः चुनाव आयोग ने चुनावी बांड के जरिये दिए जाने वाले चंदे का वह विवरण भी सार्वजनिक कर दिया जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। इस विवरण के अनुसार सबसे अधिक चंदा भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने पाया। यह वही क्रम है जो कुछ दिनों पहले सार्वजनिक किए गए विवरण में दिखा था। द्रमुक और जनता दल (एस) ने तो यह बता दिया कि उसे किस कंपनी अथवा व्यक्ति से कितना चंदा मिला। देखना यह है कि अन्य दल ऐसा करते हैं या नहीं। वे ऐसा न भी करें, तो स्टेट बैंक जैसे ही चुनावी बांडों का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर बताएगा वैसे ही यह सामने आ जाएगा कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। चुनावी बांड के जरिये दिए जाने वाले चंदे का जो विवरण अभी तक सामने आया है, उससे दो चिंताजनक पहलू उजागर हुए हैं। एक तो यह कि जो कंपनियां प्रवर्तन निदेशालय अथवा आयकर विभाग की जांच का सामना कर रही थीं, उन्होंने भी चंदा दिया। दूसरा यह कि कुछ ऐसी कंपनियों ने भी चंदा दिया जो घाटे में चल रही थीं। यह दोनों पहलू संदेह पैदा करते हैं।

इस संदेह का निवारण होना ही चाहिए कि कहीं व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए तो चंदा नहीं दिया गया। पता नहीं इस संदेह का निवारण हो सकेगा या नहीं, लेकिन यह आवश्यक है कि चुनावी चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी हो और जनता को यह जानकारी मिल सके कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। राजनीति बिना पैसे के नहीं चल सकती। चंदे के बिना राजनीतिक दलों का काम चलने वाला नहीं है। चुनावी बांड की व्यवस्था इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि चंदे की प्रक्रिया साफ-सुथरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब आवश्यक यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे वैसे सवाल न उठने पाएं जैसे चुनावी बांडों को लेकर उठे। चुनावी बांडों के जरिये चंदा देने की व्यवस्था को खत्म करने के साथ ही किसी नई पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण किया जाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इसका अंदेशा पैदा हो गया है कि कहीं चंदा देने का वह पुराना तौर-तरीका फिर से न चलन में आ जाए जिसमें किसी को इस बात का कुछ पता ही नहीं चलता था कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। राजनीति को काले धन से परे रखने के हरसंभव जतन किए ही जाने चाहिए। चुनावी चंदे की नई व्यवस्था में यह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी दल अथवा सरकार किसी कारोबारी पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल कर सके। इसी के साथ कारोबारियों को स्वेच्छा से और अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को चंदा देने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था बनाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि अपारदर्शी तरीके से चंदे के लेन-देन से राजनीतिक दलों की तो बदनामी होती ही है, भारतीय लोकतंत्र की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है।

कड़ी कार्रवाई आवश्यक

पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन समस्या अब भी गंभीर है। आए दिन नशे के सेवन से युवाओं की जान जा रही है। नशे के खिलाफ कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं और बिक्री करने वाले लोगों का विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नशीले पदार्थ बेचने वाले ऐसे लोगों पर हमला कर रहे हैं। गुरदासपुर के बटाला में नशा बेचने से रोकने पर युवक की हत्या अत्यंत गंभीर मामला है। तेजधार हथियार लेकर युवकों द्वारा हमला किए जाने से कई सवाल पैदा होना स्वाभाविक है। ऐसा लगता है कि अपराधियों के मन से पुलिस का भय नहीं है। यह तो दुस्साहस ही कहा जाएगा कि दो दिन बाद दूसरी बार हमला हुआ और जान चली गई। पुलिस का डर होता तो शायद हमला नहीं किया जाता। नशे का विरोध करने वालों पर हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले कई जिलों में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। नशे की समस्या खत्म करने के लिए लोगों का आगे आना आवश्यक है। यह अच्छी बात है कि कुछ पंचायतें, सामाजिक संगठन एवं अन्य लोग इस बुराई के खिलाफ आगे आने की हिम्मत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले या बेचने वाले लोगों द्वारा धमकी न दी जाए, उन पर हमला न किया जाए। नशा तस्कर एवं विक्रेता विरोध करने वालों में भय पैदा करना चाहते हैं। हमला करने और धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे दूसरों को सबक मिल सके।

बटाला में नशा बेचने से रोकने पर युवक की हत्या चिंतित करने वाली घटना है। पुलिस विभाग के आलाधिकारियों को इसे गंभीरता से लेना होगा

महासमर का मौजूदा परिदृश्य

राज कुमार सिंह

चुनावी माहौल मतदान तक बदलता रह सकता है, लेकिन आज के परिदृश्य में भाजपा के नेतृत्व वाला राजग सत्ता हासिल करने की होड़ में आगे नजर आता है

अवधेश राजपूत

लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। आगामी 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में मतदान होगा और चार जून को पता चलेगा कि-अबकी बार, किसकी सरकार! चुनाव से पहले सत्ता के दावेदार तो दावे करते ही हैं, किंतु लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। मतदाता अपने विवेक की कसौटी पर दावों को कसते हैं और दावे करने वालों के रिकार्ड को भी। दस साल की सत्ता विरोधी भावना की आशंका के बावजूद भाजपा अपने लिए 370 और अपने गठबंधन राजग के लिए 400 सीटों का लक्ष्य घोषित कर चुकी है, मगर विपक्ष अपना कोई आंकड़ा नहीं बता पा रहा। क्या भाजपाई खेमा आत्मविश्वास की अधिकता और विपक्ष में आत्मविश्वास के अभाव का संकेत दिख रहा है? लोकसभा में दो सीटों से 303 सीटों तक का सफर तय करने वाली और कई प्रदेशों पर शासन करने वाली भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वह हमेशा चुनावी मोड में रहती है।

पिछले साल 28 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस यानी 'इंडिया' नाम से भाजपा विरोधी मोर्चा गठित किया। इसके माध्यम से विपक्षी दल भाजपा को चुनौती देते तो दिखे, लेकिन उस बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए। आइएनडीआइए नामकरण के बाद आत्ममुग्ध विपक्ष परस्पर घात-प्रतिघात की राजनीति में उलझ गया, जबकि भाजपा ने राजग को उसके रजत जयंती वर्ष में न सिर्फ सक्रिय किया, बल्कि अपना कुनबा और बढ़ाया। पिछले साल के अंत में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में आपस में ही लड़ने वाला विपक्ष अभी तक संयोजक और साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय नहीं कर पाया है, जबकि तभी से चुनावी मोड में आई भाजपा चुनावी मुद्दों को धार देते हुए राजग के विस्तार में जुटी है। आइएनडीआइए के सफर की शुरुआत तो 28 दलों से हुई थी, लेकिन उसके दोस्त ही साथ छोड़ते गए। यहां तक उस मोर्चे के सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कांग्रेस के व्यवहार से खफा होकर वापस उसी राजग में लौट गए, जिसके विरुद्ध विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। बार-बार पालाबदल के लिए नीतीश की आलोचना की जा सकती है, लेकिन जयन्त चौधरी के लिए क्या कहेंगे? सपा से दोस्ती में मुखर भाजपा विरोध की राजनीति करने वाले जयन्त चौधरी का रालोद भी राजग में चला गया। चुनाव से पहले ही इस बिखराव की अलग-अलग व्याख्या की जा रही हैं, पर होने वाले नफा-नुकसान को समझने के लिए किसी राकेट साइंस की जरूरत नहीं। यह समझने के लिए भी नहीं कि इस बिखराव और दिशाहीनता के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के नाते कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है। विपक्षी एकता से बने माहौल का राजनीतिक लाभ उठाने में कांग्रेस इतनी आत्मकेंद्रित हो गई कि उसने सहयोगियों के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा हो जाने दिया। शायद इसका कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी रही हो।

चुनावी माहौल मतदान तक बदलता रह सकता है, लेकिन आज के परिदृश्य में भाजपा के नेतृत्व वाला राजग सत्ता हासिल करने की होड़ में आगे नजर आता है। 370 और 400 सीटों का लक्ष्य भले ही कुछ अतिरंजित लगे, लेकिन 2019 में भाजपा ने 300 पार का नारा सच कर दिखाया था। अब भी उसके प्रयास बता रहे हैं कि वह लक्ष्य हासिल करने में जी-जान से जुटी है। 10 साल से सत्तारूढ़ दल तीसरे कार्यकाल के लिए दूर हो गए दोस्तों को भी मनाने में कसर नहीं छोड़ रहा, जबकि इतने ही समय से सत्ता से बेदखल देश का सबसे पुराना दल दीवार पर लिखी चुनावी राजनीतिक जरूरत की इबारत को भी पढ़ने को तैयार नहीं। राहुल गांधी संभावित सहयोगियों को भी भाजपा की 'बी टीम' घोषित कर दूर करते रहे, जबकि नरेन्द्र मोदी-अमित शाह की जोड़ी मुखर विरोधियों में भी दोस्ती की संभावना तलाशती रही। बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की राजग में वापसी तथा उत्तर प्रदेश में जयन्त का पाला बदल इसी सोच का नतीजा है। ओडिशा में बीजद और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से भी पुनः दोस्ती की कवायद जारी है। जबकि नीतीश और जयन्त के पाला बदल के बावजूद कांग्रेस बंगाल में ममता बनर्जी से गठजोड़ को लेकर लचीलापन नहीं दिखा पाई। आम आदमी पार्टी यानी आप से भी कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में तो हुआ, जबकि पंजाब में दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे।

अब जरा दलों और गठबंधनों की मोर्चेबंदी से इतर चुनावी मुद्दों पर भी नजर डालें। निःसंदेह नरेन्द्र मोदी का नाम और चेहरा भाजपा का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड रहा है। संप्रग शासन में घोटाले के आरोपों से उपजी निराशा के बीच हुए 2014 के चुनाव में खुद को उम्मीद की किरण के रूप में पेश कर तीन दशक बाद किसी एक दल के रूप में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिलाने वाले मोदी अगले चुनाव में भी जनता का विश्वास कायम रखने में सफल रहे। भाजपा की 21 सीटें भी बढ़ गईं। दूसरे कार्यकाल में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद-370 की समाप्ति और तीन तलाक पर रोक जैसे परंपरागत वादे पूरे कर बड़ा संदेश देने में सफल रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर भी उत्तराखंड से पहल हो चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में पांचवें नंबर पर पहुंच चुकी है और जल्द ही तीसरे पायदान पर पहुंच सकती है। विश्व में भारत की साख बढ़ी है। इसके बावजूद 'अच्छे दिनों' और विदेश से काला धन वापस लाने जैसे अधूरे वादों के अलावा विपक्ष के तरकश में महंगाई, बेरोजगारी और लगातार पेपर लीक जैसे मुद्दों के भी तीर हैं। देखना होगा कि अपनी संदिग्ध विश्वसनीयता के बावजूद विपक्ष इन मुद्दों को कितनी दूर तक ले जा पाता है। यह भी कि फिर मतदाता किस पर भरोसा करेंगे, विपक्ष के मुद्दों पर या मोदी की गारंटी पर। कुछ औद्योगिक घरानों से निकटता के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने मोदी की साख पर प्रहार भी शुरू किए। हाल तक तो उसका चुनावी असर नहीं दिखा, पर चुनावी बांड्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाद सामने आ रही सच्चाई का लोकसभा चुनाव पर कोई असर होगा या नहीं, यह अभी नहीं कहा जा सकता।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

सेक्युलरिज्म की भ्रामक अवधारणा

प्रणय कुमार

'धर्म एवं संविधान' तथा 'धर्म एवं सत्य' में परस्पर विरोध न होकर वास्तव में सहयोग का एक भाव ही निहित है

धर्म सूत्रों के मर्म को भी समझना आवश्यक। फाइल

पिछले दिनों पुणे में एक अदालत के भवन की आधारशिला रखते हुए 'भूमि-पूजन' समारोह के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय एस. ओका ने कहा कि न्यायालय-परिसर में आयोजित किसी भी कार्यक्रम में पूजा-अर्चना या दीप-प्रज्वलन जैसे अनुष्ठान बंद कर देने चाहिए। उनके मतानुसार न्यायालय के किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व संविधान की प्रस्तावना की प्रति के समक्ष सिर झुकाकर पंथनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने भी कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के ध्येय-वाक्य 'यतो धर्मस्ततो जयः' (जहां धर्म है, वहां जय है) को बदल देना चाहिए, क्योंकि सत्य ही संविधान है, जबकि धर्म सदा सत्य नहीं होता। उन्होंने यहां तक प्रश्न उठाया कि जब अन्य सभी उच्च न्यायालयों और राष्ट्रीय संस्थानों में आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य भिन्न क्यों है?

सामान्यतः ऐसे तर्कों के मूल में या तो रिलीजन, मजहब एवं संप्रदाय आदि को धर्म का पर्याय मानने की भूल है या सेक्युलरिज्म की भ्रामक एवं मिथ्या अवधारणा है। 'सेक्युलरिज्म' मूलतः भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे आपातकाल के दौरान 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया था, जब पूरा विपक्ष जेल में था। संविधान की मूल प्रति में शताब्दियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा एवं इतिहास को रेखांकित करने के लिए 22 चित्र थे, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, श्रीकृष्ण जैसे सर्वकालिक महानायकों से लेकर हनुमान, बुद्ध, महावीर, राजा भरत, राजा विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोबिंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, यज्ञ में संलग्न वैदिक ऋषि आदि प्रमुख हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि संविधान सभा के सदस्य 'सेक्युलरिज्म' के आज के झंडाबरदारों की तुलना में अधिक 'सेक्युलर' तथा नीति एवं नीयत को लेकर अधिक स्पष्ट एवं निष्पक्ष थे। क्या यह सत्य नहीं कि भारत अपनी मूल प्रकृति एवं स्वभाव से ही पंथनिरपेक्ष है? वस्तुतः 'सेक्युलरिज्म' एक ऐसी अवधारणा है, जिसे यूरोप से भारत में आयातित किया गया है। इस अवधारणा का जन्म यूरोप में मध्य युग में हुआ था, जब चर्च और राज्य सत्ता अपने-अपने प्रभाव एवं कार्य-क्षेत्र के लिए आपस में टकराए थे। वहां की परिस्थिति विशेष के लिए वह एक उचित समाधान रहा होगा, परंतु हमारे यहां कभी भी मजहबी राज्य नहीं था, न ही राज्य-सत्ता एवं धर्मसत्ता के मध्य कभी कोई टकराव ही देखने को मिला, इसलिए उस संदर्भ में सेक्युलरिज्म की बात ही अर्थहीन है।

हमारे देश में धर्माचार्यों के शासन की नहीं, बल्कि अनुशासन की परंपरा अवश्य रही है। धर्म को रिलीजन अथवा मजहब के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म समग्र जीवन-पद्धति से भी विशालतर अवधारणा है। यह एक ब्रह्मांडीय विचार है। यह वैविध्य में एकत्व देखने की अंतर्दृष्टि है। धर्म शब्द के मूल में 'धृ' धातु है, जिसका संबंध धारण करने से है। धर्म वस्तु और व्यक्ति में सदा रहने वाली सहज वृत्ति, प्रकृति अथवा गुण का द्योतक है। धर्म कर्तव्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। धर्म उन व्यवस्थाओं अथवा नियमों के समुच्चय का नाम है, जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं मानव जीवन के विभिन्न अंगों को धारण किए रहता है। वहीं मजहब एवं रिलीजन का संबंध कुछ निश्चित आस्थाओं-मान्यताओं से होता है। जब तक कोई व्यक्ति उनको मानता है, वह उस 'रिलीजन' या 'मजहब' का सदस्य बना रहता है। ज्यों ही वह उन आस्थाओं-मान्यताओं को छोड़ता है, वह उनसे बहिष्कृत हो जाता है। धर्म केवल आस्थाओं पर आधारित नहीं होता। किसी धार्मिक आस्था में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति भी धार्मिक अर्थात सद्गुणी हो सकता है। 'सेक्युलर' का अनुवाद 'धर्मनिरपेक्ष' किए जाने के कारण भी बहुत से भ्रम पैदा हुए। इसका अभिप्राय धर्म से उदासीन होना नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि राजकीय समारोहों के उद्घाटन के अवसर पर दीप-प्रज्वलन की परिपाटी या नए जहाज के जलावतरण की मंगलमय बेला में नारियल तोड़कर प्रसन्नता प्रकट करना अथवा नवनिर्माण से पूर्व भूमि-पूजन कर धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना किसी उपासना पद्धति का भाग न होकर भारतीय संस्कृति और परंपरा का अंग है।

'तमसो मा ज्योतिर्गमय' अंधकार से प्रकाश की ओर-यह मानव की प्रगति यात्रा का दिशानिर्देश है। चिरकाल से मनुष्य नन्हा सा दीप जलाकर अंधकार की सत्ता को चुनौती देता आया है। हम आलोकधर्मी संस्कृति के वाहक हैं। अंधकार किसी भी समूह, समाज अथवा समुदाय का अभीष्ट नहीं हो सकता, न ही होना चाहिए। धर्म जहां परिणामोन्मुखी एवं निर्देशात्मक होता है, वहीं सत्य वस्तुनिष्ठ होता है। यदि सत्य इस प्रश्न का उत्तर देता है कि 'क्या है' तो धर्म इस प्रश्न का उत्तर देता है कि 'क्या होना चाहिए।' धर्म संविधान में निहित न्याय, निष्पक्षता और समानता के अंतर्निहित मूल्यों को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वैधानिक निर्णय न केवल विधिसम्मत हों, अपितु नैतिक कसौटी पर भी खरे उतरने वाले हों। संविधान जहां देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है, वहीं धर्म नैतिक दिशा-निर्देश प्रदान कर इसके अनुप्रयोग को बढ़ाता है। यह कानूनी व्याख्या एवं निर्णय लेने में सहायक एवं मार्गदर्शक भूमिका निभाता है। धर्म को विधिक प्रक्रिया, तर्क एवं व्याख्या में सम्मिलित कर न्यायाधीश नैतिक दुविधाओं को संबोधित एवं जटिल मुद्दों को हल कर सकते हैं। 'धर्म एवं संविधान' तथा 'धर्म एवं सत्य' में परस्पर विरोध या टकराव न होकर सहयोग एवं पूरकता का भाव निहित है।

(लेखक शिक्षाविद् एवं सामाजिक संस्था 'शिक्षा-सोपान' के संस्थापक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

फलदाता

श्रीमद्भगवद्गीता में जब अर्जुन द्वारा किए गए कर्म और उन कर्मों के फल-प्राप्ति की स्थिति पर जिज्ञासा व्यक्त की गई तो वहां इस जिज्ञासा का समाधान देते हुए श्रीकृष्ण द्वारा यह कहा गया कि कर्म करना ही मनुष्य के हाथों में है। उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल कब, कहां, किस रूप में मिलेगा? इसका निर्धारण करने का अधिकार कर्म-संपादक को नहीं है। कर्म-संपादक का अधिकार केवल इतना ही है कि वह शास्त्र और लोक-मर्यादा का पालन करते हुए केवल अपने लिए निर्धारित कर्म ही करे।

श्रीरामचरितमानस में इस विषय पर जो सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार सभी स्वकृत ही भोगते हैं। और तब यह जिज्ञासा होती है कि किसका क्या कर्म है और उसका फल किस रूप में उसे मिलेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका समाधान करते हुए विद्वान महाभारत में श्रीकृष्ण और कंस की उस वार्ता का संदर्भ देते हैं जब वह कंस के सिंहासन के पास पहुंच कर उसके बालों को पकड़कर उसे सिंहासन के नीचे फेंकने को तैयार हुए तो कंस ने कहा, कृष्ण! यह क्या कर रहे हो? मैंने तो किसी का कोई अपराध किया नहीं है। जो किया वह राज्य-व्यवस्था थी। फिर ऐसे में तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो?

कंस की बात सुनकर श्रीकृष्ण ने कहा, कंस! मैं न किसी को मारता हूं और न किसी को जीवित करता हूं। मैं तो किसी जीव के साथ उतना ही विधान करता हूं, जितना उसने अपने जीवन में दूसरे जीव के साथ किया होता है। तुम याद करो, जब तुम अपनी बहन और मेरी मां देवकी को विवाह के बाद विदा कर रहे थे और तब अपनी मृत्यु की आकाशवाणी सुनकर तुमने बिना विचार किए उन्हें बाल खींचकर रथ के नीचे फेंक दिया था। कंस! मैं भी तो यही कर रहा हूं, क्योंकि जो जैसा करता है, उसके उतने फल का निर्धारण मात्र ही मैं करता हूं और उसे कृत कर्म का फल देता हूं।

डा. गदाधर त्रिपाठी

एक संजीवनी की तरह है 'फिर'

डा. महेश परिमल

फिर एक ऐसा शब्द है, जो हमें जिंदगी में हमेशा नई राह दिखाता है। हताश मन में उमंग भर देता है

हम सभी का सामना कभी न कभी 'फिर' से पड़ता है। इस एक शब्द में कई चीजें समाहित हैं। इसमें नई जान फूंकने की शक्ति है। यह एक ऐसा शब्द है, जो हमें जिंदगी में हमेशा नई राह दिखाता है। हताश मन में उमंग भर देता है। एक हताश मन यदि एक बार यह सोच ले कि जिंदगी अब 'फिर' से जीनी है तो उसके सोच की लहरें कहां से कहां तक पहुंच जाती हैं। सचमुच टूटी हुई पतवार को जोड़ने की क्षमता रखता है यह शब्द। अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला है यह शब्द। अपनी गलतियों को न दोहराने के संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला है यह शब्द। जीवन के खालीपन को भरता है यह शब्द 'फिर'। परीक्षा में कम नंबर आने के बाद बच्चा जब कहता है कि अगले साल फिर कोशिश करूंगा। बच्चा इस 'फिर' को अपना साथी बनाकर जुट जाता है अपनी मंजिल को पाने के लिए।

हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे, जो पहले प्रयास में सकारात्मक परिणाम नहीं देते, पर दूसरे प्रयास में चमत्कारिक परिणाम अवश्य देते हैं। किसी काम को बार-बार करने पर व्यक्ति उस काम में प्रवीण हो जाता है। ठीक उसी तरह एक बार काम में असफलता प्राप्त करने के बाद उसे यदि फिर से किया जा रहा है तो समझो कि अब उस काम को करने में पहले वाली गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। वह काम व्यवस्थित तरीके से पूर्ण होगा। काम को करना और किसी काम को फिर से करने में थोड़ा-सा अंतर है। फिर से करने का मतलब ही है पूरी सावधानी के साथ उस काम को अंजाम देना। फिल्मी संसार भी इससे अछूता नहीं है। फिर वही दिल लाया हूं, फिर तेरी कहानी याद आई, बहारें फिर भी आएंगी, दिल ने फिर याद किया, यह रात फिर न आएगी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर हेरा-फेरी, फिर मिलेंगे आदि इसके उदाहरण हैं। कहा जा सकता है कि कामयाब लोगों के लिए 'फिर' शब्द एक संजीवनी की तरह है।

अल्बर्ट आइंस्टीन और थामस अल्वा एडीसन के उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर ये अपने प्रयोग को पहली बार करने के बाद हार मान लेते तो इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता। किसी काम को बार-बार करने की प्रवृत्ति ने उन्हें महान बनाया। 'फिर' वह अहसास है कि इस बार कामयाबी हमारे ही हाथ होगी। 'हम होंगे कामयाब' का आशय ही यही है कि हमने फिर से कोशिश की। पहली कोशिश ने हमें सीख दी तो दूसरी कोशिश ने सफलता। इसलिए जिंदगी में 'फिर' से कभी नाता न तोड़ें। गोस्वामी तुलसीदास ने इसे 'पुनि-पुनि' बताकर कई बार अपनी चौपाइयों में प्रयुक्त किया है। इसलिए 'फिर' शब्द हमारे सामने आता है तो इसे सहजता से लें, इसके पीछे के संकल्प को देखें, इसकी सकारात्मकता को पहचानें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जल बिना जीवन नहीं

'बेंगलुरु के जल संकट का सबक' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में पंकज चतुर्वेदी ने ठीक कहा है कि बेंगलुरु में जल संकट अन्य शहरों को इस तरह की समस्या से बचने के लिए तुरंत चेतने का संदेश दे रहा है। निश्चित रूप से पानी की बूंद-बूंद का सदुपयोग हो और प्राकृतिक स्रोतों को सहेजने के साथ वर्षा की बूंदें भूमि के गर्भ तक पहुंचें, इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही हम जल संकट का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं, अन्यथा खासकर गर्मियों के समय गहराता जल संकट सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। समय रहते जल की बचत के साथ उसके सदुपयोग की भावना आम जनमानस में विकसित करनी होगी। हमारे पूर्वजों ने साफ पानी से भरे लबालब जोहड़ एवं तालाब देखे, नदियां और झरने देखे। जबकि आज जोहड़, तालाब और नदियां प्रदूषित होकर लुप्त हो रही हैं और भूजल दोहन से धरती का गर्भ भी सूख रहा है। ऐसे में, हम सबको चेतना होगा। जल की बचत के साथ वर्षा जल संचयन के लिए भी प्रयासरत रहना होगा। जल बिना जीवन नहीं। आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन की सबसे बड़ी जरूरत को ही हम व्यर्थ बहा देंगे तो यह जल संकट उनके लिए बड़ी चुनौती बनेगा। पशु-पक्षी तो जमीन के अंदर से पानी निकालकर नहीं पी सकते। न जाने कितने ही जानवर प्यास से मरते होंगे। इसलिए हमें जल स्रोतों के प्राकृतिक संसाधनों को भी सहेजना चाहिए, ताकि प्यास से कोई जीव अपनी देह न त्यागे।

हरीश कुमार शर्मा, डोहर खुर्द, हरियाणा

मेलबाक्स

सीएए पर सवाल क्यों?

जो लोग सीएए के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनसे सवाल है कि अगर भारत अपने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस कानून के तहत भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है। यह एक प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में 24 प्रतिशत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी आदि थे। आज पाकिस्तान में यह आंकड़ा दो प्रतिशत है। ज्यादातर शरणार्थी हो गए या जबरन मतांतरण का शिकार हो गए। ये लोग अधिकांश अनुसूचित जाति के हैं और उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। उन्हें सीएए के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग खुल रहा है। यह कानून उन्हें नागरिकता प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जो पिछले कुछ वर्षों से यहां रह रहे हैं। सीएए का विरोध करने वालों को ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम् और मानवता को सर्वोपरि रखने वाली सनातन संस्कृति को विश्व के आधुनिक पटल पर पुनर्जीवित करने का प्रयास है। जिन लोगों के अंदर आज के समय में भारतीय सनातन संस्कृति की चेतना है, उसी को सीएए जागृत कर रहा है।

अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

चुनावी हवा

लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। उत्तर प्रदेश में सात फेज में चुनाव कराएंगे जाएंगे। कहावत भी है कि दिल्ली की राजनीति उत्तर प्रदेश से होकर जाती होती है। लोकसभा की 80 सीटों वाले प्रदेश में हर कोई उम्मीद जताए बैठा है। राजनीतिक दल जानते हैं कि वे कितने गहरे पानी मे खड़े हैं। विकास की बुलंदियों पर जिस दल और जिन नेता ने उत्तर प्रदेश को पहुंचाया है लोग उसे ही वोट देंगे। परिणाम तो चार जून को आएगा, लेकिन दलों में चिंता अभी से लगी हुई है। भाजपा और सपा सक्रिय हैं। बसपा अभी प्रचार प्रसार से दूर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस निम्न स्तर पर है। कांग्रेस की वोट की भूख नेताओं को अनाप शनाप बोलने के लिए मजबूर कर रही है। मोदी ने उत्तर प्रदेश में अनेक रैलियां की हैं। मोदी उन क्षेत्रों का भी दौरा कर चुके हैं जिसमें पिछली बार जनता का समर्थन नहीं मिला था। देखना यह है कि आगामी लोकसभा में किसका पलड़ा भारी रहता है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

479 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में मदरसा शिक्षा के लिए। साथ ही, योगी सरकार यूपी में 7,442 मदरसों का आधुनिकीकरण कर रही है और इन मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी लागू किया गया है।

आजकल

मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

मदरसों को आम तौर पर मजहबी शिक्षा के केंद्र के रूप में देखा जाता है, जहां मुस्लिम मत से संबंधित शिक्षा दी जाती है। मदरसों में हो रही विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग की जांच के दौरान उत्तर प्रदेश में आठ हजार से अधिक मदरसे अवैध पाए गए हैं। ऐसे में मदरसों के बारे में अन्य समुदायों में बनी नकारात्मक धारणा को तोड़ने के लिए उनका आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है

लालजी जायसवाल
लोकनीति विश्लेषक

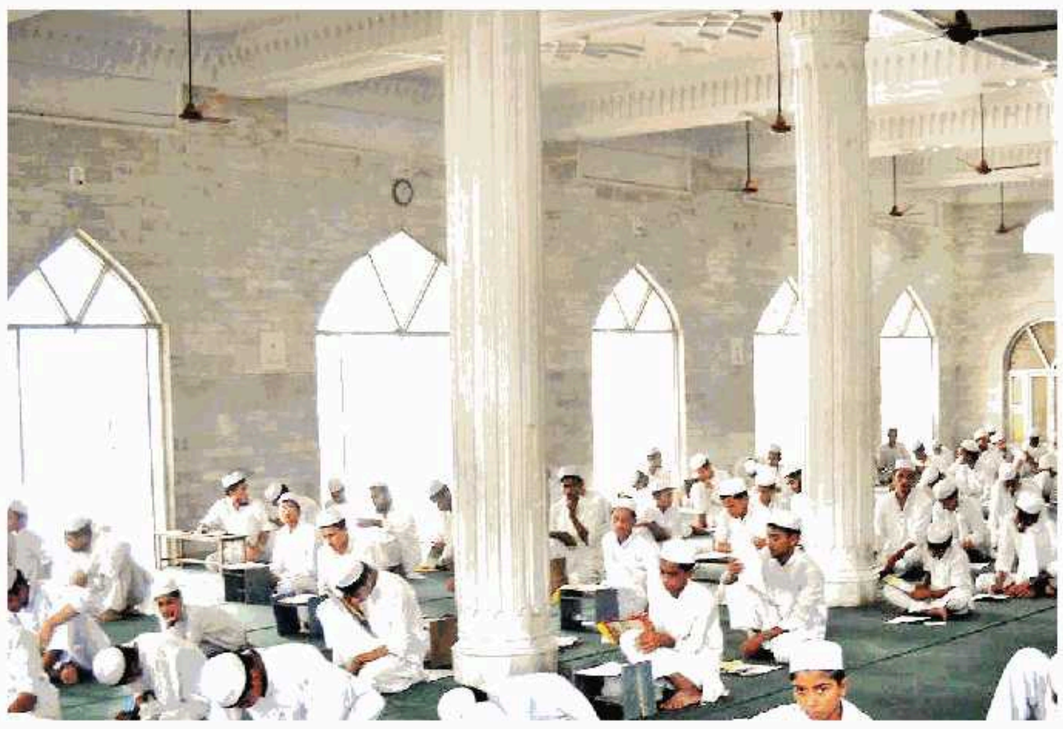

हाल ही में एसआइटी की जांच में यह सामने आया है उत्तर प्रदेश में अनेक मदरसों के संचालन के लिए वैध अनुमति नहीं ली गई थी। प्रतीकात्मक

उत्तर प्रदेश में संचालित लगभग 16 हजार मदरसों की जांच अभी चल रही है। इनमें लगभग साढ़े पांच हजार मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि लगभग 10 हजार मदरसे ऐसे हैं, जिन्हें तीन से पांच वर्ष की अस्थायी मान्यता प्राप्त थी। अधिकांश ऐसे हैं, जिनकी मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा मान्यता ही नहीं कराई गई। चिंता की बात है कि इनमें न तो खेल के मैदान हैं और न ही अन्य मानक पूरे किए गए हैं। इस तरह लगभग 90 प्रतिशत मदरसों के संचालक अपनी आय-व्यय का ब्योरा नहीं दे सके हैं। कुछेक संचालकों का यह तर्क भी है कि मदरसे चंदे की रकम से बनाए गए हैं, परंतु उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। एसआइटी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 80 मदरसों को लगभग 100 करोड़ रुपये की विदेश से फंडिंग हुई है। ये पैसा सीधे इन मदरसों का प्रबंधन करने वाली सोसायटी और गैर-सरकारी संगठनों के बैंक खातों में जमा किया गया था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धन का गुप्त आगमन नैतिकता और धार्मिक सहिष्णुता को बिखराने में भूमिका निभा सकता है।

गौरतलब है कि मदरसों का आधुनिकीकरण हमेशा से चर्चा में रहा है। मदरसों के पाठ्यक्रमों का गहन अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि वहां पढ़ाए जाने वाले फिक्ह अर्थात इस्लामिक विधि की शैली, भाषा तथा उदाहरण प्राचीन कालीन हो चुके हैं। ये पाठ्यक्रम तर्क व चर्चा का माहौल बनाने के बजाय द्वेष व विरोध का भाव अधिक पैदा कर रहे हैं। इनसे जानकारी परक तर्कशक्ति के बजाय ऊब पैदा होने लगती है। इसमें अधिकांश टीकाओं की टीकाएं पढ़ाई जा रही हैं। निश्चित ही यह दिलचस्पी जगाने का आदर्श तरीका नहीं है। अलबत्ता दक्षिण भारत के कुछ राज्यों विशेषकर केरल और बंगाल में स्थिति कुछ अलग है, जहां अंग्रेजी, साइंस एवं गणित जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। पिछले 10-15 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों ने मदरसों के आधुनिकीकरण पर बड़े-बड़े बजट बनाने और इन पैसों को मदरसों तक पहुंचाने का दावा किया है। उल्लेखनीय है कि इस आधुनिकीकरण में मुख्यतः अंग्रेजी, विज्ञान और कंप्यूटर की पढ़ाई शामिल है। अगर बात बिहार की करें तो यहां मुश्किल से 15 प्रतिशत मदरसों में ही कंप्यूटर पहुंच सका है। वहां लगभग 85 प्रतिशत मदरसे आधुनिकीकरण के इंतजार में अभी भी हैं।

धन का स्रोत : यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मदरसों को सरकारी सहायता नहीं मिलती है। कुछ मदरसे पूरी तरह से दान और शुल्क पर निर्भर करते हैं। मदरसों के लिए धन का स्रोत एक विवादास्पद मुद्दा है। कुछ लोग मानते हैं कि मदरसों को सरकारी सहायता नहीं मिलनी चाहिए, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि मदरसों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह ही सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। भारतीय मदरसों की एक और बहुत बड़ी समस्या वित्तीय व्यवस्था है। लगभग सारे मदरसे आमजन के सहयोग से चलते हैं। इसलिए मदरसों का पंजीकरण कराकर उन्हें सरकारी सहायता देकर सशक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार से सरकार का उन पर नियंत्रण भी बना रहेगा।

आधुनिकीकरण पर दिया जाए जोर : सच्चर कमेटी के सदस्य रहे रिटायर्ड आइआरएस अधिकारी जफर महमूद के अनुसार, मदरसों के आधुनिकीकरण की बात तो 1996 से ही चल रही है। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इंद्रकुमार गुजराल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक की सरकारें आईं और गईं। लेकिन कोई भी सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। पिछले पांच वर्षों में सरकार ने मदरसों का आधुनिकीकरण करने का काम किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मदरसों में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पाठ्यक्रम को भी जोड़ने पर काम हो रहा है। भारत सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मदरसों/ अल्पसंख्यकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अंब्रेला स्कीम लागू किया है जो मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना और अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास से मिलकर बनी है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2021-22 में मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार भी मदरसों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देती आ रही है। साथ ही योगी सरकार ने फर्जी मदरसों को रोकने के लिए वर्ष 2017 में मदरसा पोर्टल भी बनाया था जिसके तहत 19,125 मदरसों में से 16,531 मदरसे पोर्टल से जुड़े हुए हैं। योगी सरकार वर्तमान में 7442 मदरसों का आधुनिकीकरण कर रही है और इन मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी लागू किया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विविधताओं का देश है और यहां के नागरिकों की कई पहचान हो सकती है, किंतु उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी राष्ट्रीयता-भारतीयता से है। जब इसी पहचान की अवहेलना होगी तो कई विसंगतियों का पैदा होना स्वाभाविक है। इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए कि क्या सभी के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था बनाई जा सकता है? बहरहाल, आवश्यकता इस बात की होनी चाहिए कि सभी बच्चे साधारण विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करें, जिससे उनकी राष्ट्रीयता समान हो सके। बच्चों को उसी स्कूल में आधुनिक विषयों के साथ-साथ सभी मतों की नैतिक शिक्षा हेतु अलग से व्यवस्था की जाए, ताकि वे अन्य मजहबों और उनके मान-बिंदुओं का आदर कर सकें। साथ ही दूसरों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सीख सकें।

आज मुस्लिम समुदाय की जो स्थिति है, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार हैं? मुस्लिम शासनकाल में अरबी-फारसी को भले ही महत्व दिया गया हो, किंतु आधुनिक युग के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में केवल मजहबी ज्ञान से मुस्लिम समाज, शेष समाज के साथ-साथ चलने की कैसे कल्पना कर सकता है? पिछले कुछ वर्षों में मदरसों पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकियों की नर्सरी बनने के आरोप लगे हैं। वहां मुस्लिम युवाओं की ब्रेनवाशिंग होती है, ऐसी बातें सुरक्षा एजेंसियों ने भी कहीं है। ऐसे में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। साथ ही उसे देश की मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना होगा, ताकि वर्तमान प्रणाली के अनुरूप उसे आधुनिकीकरण के दायरे में लाया जा सके।

उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण

देखा जाए तो मदरसों का पाठ्यक्रम बहुत पुराना है। मदरसा शिक्षा का वर्तमान पाठ्यक्रम में काल अर्थात समय का अभाव पाया जाता है, जो कुरान की शिक्षा के विरुद्ध है। कुरान इंसानों से चिंतन, खोज और तर्क करने का आग्रह करता है, जबकि मदरसों का अपने विद्यार्थियों से कहना होता है कि वे केवल कुरान याद करें और कोई प्रश्न न पूछें। सवाल पूछने वाले को ऐसा माना जाता है कि उसने परंपरा तोड़ी है तथा इस पर वहां सजा का प्रविधान है। साथ में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि मदरसा में शिक्षकों के लिए भी विशेष योग्यता का निर्धारण किया जाए। ऐसे शिक्षक ही मदरसों में रखे जाएं जो धर्म से ऊपर उठकर विज्ञान और तकनीक की पर्याप्त समझ रखते हों, क्योंकि शिक्षण संस्थानों की सफलता पूरी तरह से शिक्षकों पर निर्भर करती है। शिक्षकों को विषयों को पढ़ाने के लिए उच्च शिक्षित और योग्य होना चाहिए। शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की शिक्षण कर्मचारियों को उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। लिहाजा यदि शिक्षक पर्याप्त रूप से योग्य नहीं होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा।

मदरसे अपने दीनी तालीम देने के उद्देश्य में तो कामयाब हैं, क्योंकि इस्लाम जीने का सलीका सिखाता है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौकरी चाहिए और नौकरी केवल आधुनिक शिक्षा से मिलेगी। इस दिशा में मदरसे पीछे हैं। ऐसे में अगर मोदी सरकार मदरसों और उसके शिक्षकों को माडर्न बनाने का प्रयास करती है, तो यह एक बेहतर कदम है। क्या मजहबी शिक्षा देने तक सीमित मदरसों में आधुनिक विषयों को शामिल करके वहां के छात्रों के चिंतन में बदलाव लाना संभव है? यदि मदरसों में अंग्रेजी, विज्ञान आदि आधुनिक विषयों को शामिल करने से कट्टर इस्लामी मानसिकता वाकई बदल सकती तो निश्चय ही अलीगढ़ मुस्लिम विवि भारत को खंडित करने के प्रपंच में भूमिका नहीं निभाता। मदरसा शिक्षा प्रणाली की अन्य खामियों में बड़ी खामी यह है कि यहां के छात्रों का संपर्क मुस्लिम बच्चों-अध्यापकों के साथ ही होता है। प्रारंभिक परवरिश में ही बाहरी दुनिया से कटाव उन्हें अन्य समुदाय के विचार व जीवन दर्शन से अपरिचित रखता है। यदि मुस्लिम बच्चे केवल अपने समुदाय के बच्चों और मौलवी के ही संपर्क में रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका दृष्टिकोण, वेशभूषा, भाषा, देश के इतिहास के बारे में उनकी समझ और सपने भी शेष समाज से भिन्न होंगे। यही दूरियां अक्सर कई गलतफहमियों को जन्म देने का कारण बनती हैं।

(लालजी जायसवाल)

खरी-खरी

आस्तीन के एक सांप का साक्षात्कार

अलंकार रस्तोगी

मैं इस बात को लेकर अचरज में था कि सामान्य तौर पर सांप तो बिलों में रहा करते हैं, आखिरकार ये किस प्रजाति के सांपों को सूझी कि अच्छे-खासे इंडीपेंडेंट बंगले टाइप्ड बिल को छोड़कर वन बीएचके वाले आस्तीन जैसे अपार्टमेंट में रहने में इन्हें मजा आने लगा। कौन सा वहां पर स्विमिंग पूल होता है या जिम और क्लब की मेंबरशिप मिली होती है?

मैं इसी उत्सुकतावश ऐसे ही किसी आस्तीन के सांप की तलाश में निकल पड़ा। मैंने जैसे ही एक आस्तीन वाले बंदे से झटक कर हैंडशेक किया, वैसे ही उसमें से एक सांप नीचे टपक गया और मुझे देखकर फन फैलाकर बिल्कुल दाउद इब्राहिम की तरह घूरने लगा, मानो वह मुझे उसको डिस्टर्ब करने के लिए तुरंत डस लेगा। इससे पहले कि वह मेरे दुस्साहस के लिए मुझे 'आन द स्पाट' सजा दे पाता, मैंने उसे अपना परिचय और मंसूबे बता दिए।

अब वह सांप किसी सेलिब्रिटी की तरह भाव खाते हुए बोला, 'बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने तो सुना था कि व्यंग्यकार स्वयं बहुत जहरीला प्राणी होता है, भला उसको मेरा इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत आन पड़ी?

मैं उस सांप से पर्याप्त और सुरक्षित दूरी बनाते हुए बोला, 'सांप भाई, मेरी जिज्ञासा है कि लंबे, गहरे और आलीशान बिल को छोड़ इस आस्तीन में ऐसी क्या खूबी है जो आप इसमें रहना पसंद करते हैं?'

जो जहर सांप ने मेरे लिए अपने मुंह में भरा हुआ था, उसे पास की नाली में जाकर उगलते हुए बोला, 'यार तुम व्यंग्यकार लोग भी न दूर की नहीं सोचते हो। तभी महज एक कालम के लिए कलम घिस रहे हो। इतना भी नहीं जानते कि अब बेईमानी की चाशनी में मतलब की जलेबी भिगोई जाती है। अब सरकारें प्रजातंत्र से नहीं, बल्कि मेरे जैसे आस्तीन के सांपों को रिसोर्ट में दूध पिलाने से बनती हैं। मैं आस्तीन में स्वयं नहीं पलता, बल्कि मुझे तो यहां संरक्षण दिया जाता है। अब मुझे आस्तीन का सांप नहीं, तरक्की पसंदों का बाप कहना ज्यादा सही होगा।

पोस्ट

शेयर बाजार का यही दस्तूर है कि एक गलती आपको लाखों रुपये की चपत लगवा सकती है, लेकिन एक सीखा गया सही सबक आपके लिए करोड़ों भी बना सकता है।

अभिजीत चोकसी@stockifi_Invest

चुनावी बांड को लेकर चल रही बहस का सार यही है कि पूरी कवायद इसी बात की है उसके पास मुझसे ज्यादा चंदा कैसे? मेरा चंदा साफ और तुम्हारा चंदा रंगदारी।

अनुराग@VnsAnuTi

चुनावी बांड में जिस लाटरी किंग के नाम की सबसे अधिक चर्चा है, उनसे सबसे अधिक चंदा द्रमुक को मिला। द्रमुक आइएनडीआइए का एक प्रमुख घटक है।

अरविंद गुप्ता@buzzindelhi

राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। कौन कब किससे अलग हो जाए और किसका हो जाए, यह तात्कालिक परिस्थितियों, जरूरतों और सहूलियतों पर निर्भर करता है। ज्यादा भावुकता बस कार्यकर्ताओं में होती है। नेता भावुक नहीं होते। कभी-कभी भावुक होने का दिखावा जरूर करते हैं।

अरविंद चोटिया@arvindchotia

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या आम चुनाव की प्रक्रिया ज्यादा लंबी है?

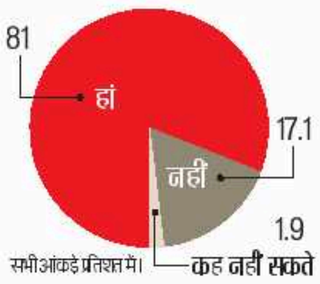

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या इतने चुनावों और परीक्षाओं के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश बची है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चंदा वाइट में मिले तो उनको ऐतराज,
मतलब, चलना चाहिए काले धन का राज।
काले धन का राज सिरे से गलत इरादा,
धन लें दल के नाम और रक्खें घर आधा!
करना है हर काम उन्हें गंदा ही गंदा,
फिर क्यों हो स्वीकार उन्हें वाइट में चंदा!!

- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश डायरी

चुनावी बयार में जागती 'अंतरात्मा' की आवाजें

हरिशंकर मिश्र
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

राजनीति में दलीय निष्ठाओं की खास बात यह है कि वे मौके पर तार-तार होती हैं और उस धारा की ओर बढ़ती हैं जो वेगवान हो। यूपी में चुनाव की आहट शुरू होते ही निष्ठा बदलने का जो मौसम शुरू हुआ, वह अब अपने चरम पर है और राजनीति के शातिर ऐसे मोहरों की घेरेबंदी में जुटे हुए हैं जो उनके लिए बाजी जीत सकें। इसके लिए सभी दलों की अपनी रणनीति है और अपने दांवपेच। यह अलग बात है कि भाजपा ने इसमें बाजी मारी है और इसलिए कि उसकी चुनावी धारा अधिक तेज है और वहां संभावनाएं भी दिख रही हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है जिसकी निगाहें बसपा के बलशाली उम्मीदवारों पर हैं तो कांग्रेस की उम्मीदें अन्य दलों से छांटे गए प्रत्याशियों पर टिकी हैं। हाथी कमजोर हो चला है तो उसकी पूरी कोशिश इसी बात पर है कि येन-केन प्रकारेण बिखराव रोका जाए।

'अंतरात्मा की आवाज' पर होने वाला निष्ठा परिवर्तन बहुधा मजबूत पक्ष की ओर होता है, इसलिए अंबेडकरनगर के बसपा सांसद रितेश पांडेय ने जब भाजपा का दामन थामा तो किसी को आश्चर्य न हुआ। पहले से ही ऐसी अफवाहें चल रही थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय ने जब भगवा थामा तो यह थोड़ा चौंकानेवाला था। मनोज पांडेय विपरीत परिस्थितियों में भी ऊंचाहार से विधायक बने थे और सपा का मुख्य ब्राह्मण चेहरा थे। भाजपा में आने का उनका आकर्षण रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ दावेदारी हो सकती है, बशर्ते कि पार्टी उन्हें लड़ाना चाहे। भाजपा में आने वालों की भीड़ है और पार्टी ने भी अपने दरवाजे खोल रखे हैं। यहां तक कि मायावती सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्र उर्फ अंटू भी बीते शुक्रवार को उसके दरवाजे पर नजर आए। यह अलग बात है कि उन्हें सदस्यता ग्रहण करने से पहले ही लौटना पड़ा। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के रिश्तेदार अंटू कहते हैं कि उन्हें दिल्ली में ज्वाइन कराया जाएगा, लेकिन पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है। सत्ता में रहते हुए उन पर एनएचआरएम घोटाले के दाग हैं और शायद उनके लिए भगवा थामना इतना आसान न हो। हालांकि इसी कार्यक्रम में बसपा सरकार में राज्य मंत्री रह चुके बांदा के अच्छेलाल निषाद और महोबा के सिद्ध गोपाल साहू को पार्टी ने अपनी फौज में शामिल किया।

दूसरे दलों के लोगों को पार्टी में शामिल करना भाजपा की रणनीति का हिस्सा है और इससे वह दौड़ में सबसे आगे का संदेश देना चाहती है, जो मिशन-80 के तहत प्रदेश की सभी सीटों को जीतने के लक्ष्य में निहित है। कोई दो राय नहीं कि इससे जनाधार बढ़ेगा और दूसरे दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से पार्टी ने प्रदेश, क्षेत्र और जिला स्तर पर ज्वाइनिंग कमेटियां गठित की हैं। प्रदेश स्तरीय कमेटी की कमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हवाले है जिसने अपने तरकश में अब तक कई तीर बढ़ाए हैं। एक बड़ा तीर तो हाल ही में कानपुर के अजय कपूर के रूप में जुड़ा है जिन्हें दिल्ली में ज्वाइन कराया गया। तीन बार के विधायक कपूर कांग्रेस के निष्ठावान नेताओं में रहे हैं। अभियान के तहत भाजपा दूसरे दलों के लोगों को बड़ी संख्या में शामिल करने में सफल रही है।

राजनीतिक स्वार्थ के आगे दलीय निष्ठा और नैतिकता के कोई मायने नहीं और इसका लाभ समाजवादी पार्टी को भी मिला है। आजमगढ़ में वह बसपा के बड़े नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपनी ओर घसीटने में सफल रही और इस सौदेबाजी के इनाम में जमाली के लिए पार्टी ने विधान परिषद के दरवाजे खोल दिए। यहां तक कि सपा ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी से भी परहेज नहीं किया जो घोषित माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं। बीती ताहि बिसार दे कि तर्ज पर अफजाल ने 2016 की उस घटना को भुला दिया जब अखिलेश के विरोध के चलते ही उनकी पार्टी कौमी एकता दल का सपा में विलय नहीं हो सका था। अखिलेश ने भी अफजाल के उस बयान को भुला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सपा को सबक सिखाएंगे। हालांकि अफजाल और गुड्डू जमाली के सपा में आने की एक वजह यह भी है कि बसपा में उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है।

कांग्रेस भले ही अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, लेकिन निष्ठा बदल के इस खेल में उसे भी कुछ हासिल हुआ है। लखीमपुर खीरी के बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले रवि प्रकाश वर्मा और उनकी पुत्री पूर्वी वर्मा सपा से नाता तोड़कर पहले ही हाथ पकड़ चुके थे। सहारनपुर के चर्चित नेता इमरान मसूद भी उसके लिए राहत की बात हैं और सपा से गठबंधन के बाद उससे कुछ और लोग जुड़ सकते हैं।

छत्तीसगढ़ डायरी

आम चुनाव में गारंटी वाला दांव

सतीशचंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के मौसम का अर्थ है गर्मी और बहुत गर्मी। अभी ही तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। सात मई को रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित सात संसदीय क्षेत्रों में मतदान के साथ प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। तब राजनीति के साथ-साथ मौसम का तापमान भी चरम पर रहेगा। उससे पहले बस्तर में 19 अप्रैल और कांकेर, राजनांदगांव एवं महासमुंद में 26 अप्रैल को मतदान होने के बाद चार जून के परिणाम का ही इंतजार रहेगा। इन्हीं दिनों की तैयारी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने तीन महीने के कार्यकाल में गारंटियों को पूरा करने में पुरजोर तरीके से लगे रहे। संसदीय चुनाव में वोट के लिए जनता के बीच जाने के पहले पूरी ताकत से किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। घोषणाओं के साथ उनके अनुपालन का संतुलन प्रदेश के 11 संसदीय क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा सकता है। यद्यपि प्रदेशवासियों को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन की राज्य सरकार की योजना भी जमीनी स्तर पर प्रभाव दिखा रही है तो जनता मतांतरण के विरुद्ध कठोर कानून की भी आस लगाए है। पिछले एक सप्ताह में 500 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों ने मंत्रियों की हड़बड़ाहट पर प्रश्न भी खड़े किए हैं, परंतु हार और भ्रष्टाचार के आरोपों में उलझा विपक्ष फिलहाल चुनौती खड़ा करने से बचता ही नजर आ रहा है।

मोदी की गारंटी का ही नतीजा रहा कि प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10 मार्च को एक हजार रुपये प्रति महीने की दर से महतारी वंदन योजना की राशि पहुंच गई। उसके बाद 12 मार्च को लगभग 25 लाख धान उत्पादक किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान के वादे के अनुसार कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि का भुगतान कर दिया गया। साथ ही प्रदेश के लगभग चार लाख नियमित कर्मचारियों को चार प्रतिशत की दर से वृद्धि के साथ 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की घोषणा कर दी गई है। इसका लाभ लगभग सवा लाख पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। ग्राम पंचायत सचिवों को वर्ष 2023 की 55 दिनों की हड़ताल के रोके गए वेतन का भुगतान प्रदेश के गांव-गांव तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। इतने कम समय में अप्रत्याशित रूप से गारंटी पूरा करने के प्रयासों का परिणाम जमीनी स्तर के विकास कार्यों पर अवश्य पड़ा है। अधिकांश कार्यालयों में फाइलें अटक गई हैं, परंतु हवा का रुख चुनावी है और सभी बातें गौण पड़ गई हैं।

प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों के लिए तीन महिलाओं सहित 11 उम्मीदवारों की पहले ही घोषणा कर भाजपा ने शुरुआती बढ़त बना ली है। विभिन्न स्तरों पर अभियान भी आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की सूची आठ से आगे नहीं बढ़ पा रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम महादेव सट्टा एप से जुड़े मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो की चार मार्च को दर्ज प्राथमिकी में आ जाने से मुश्किलें बढ़ने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। विधानसभा चुनाव के समय से ही शराब, कोयला, कस्टम मिलिंग और जिला खनिज फाउंडेशन में भ्रष्टाचार कांग्रेस और पार्टी के नेताओं के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। ईडी द्वारा कोर्ट में पेश चार्जशीट में दुर्ग के पाटन से विधायक भूपेश बघेल पर सट्टा एप के मालिक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से 508 करोड़ रुपये वसूली का आरोप लगाया गया है। महादेव एप के अधिकांश आरोपितों का दुर्ग से ही रिश्ता है।

संसदीय चुनाव में दुर्ग के नेताओं को विभिन्न क्षेत्रों से दी गई उम्मीदवारी को देखते हुए समझा जा सकता है कि प्रदेश की औद्योगिक व आर्थिक राजधानी का राजनीति में कितना प्रभाव है। भाजपा ने यदि दुर्ग से सांसद विजय बघेल को दोबारा मैदान में उतारा है तो यहां से सांसद रह चुकीं सरोज पांडेय को कोरबा से टिकट मिला है। दुर्ग से ही सांसद रहे एवं पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू इस बार महासमुंद से चुनाव मैदान में हैं तो भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज के बस्तर क्षेत्र सहित कांकेर, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर से अभी तक उम्मीदवार भी नहीं तय हो पाए हैं।

बालोद में एक किसान को कृषक उन्नति योजना के तहत राशि का प्रमाण पत्र देते विष्णुदेव साय। नईदुनिया

यद्यपि चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रदेश में तबादला अभियान का चरम पर पहुंच जाना अवश्य चर्चा का विषय बन चुका है। प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, वन, जेल और सिंचाई महकमे में जिस तरह से अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों की ताबड़तोड़ सूचियां जारी हुईं, उससे कुछ संदेह भी उत्पन्न हुए। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के 200 से अधिक तबादलों को हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से वापस लिया गया है। अब तक सभी का ध्यान चुनाव पर केंद्रित है। परिणाम बताएगा कि मतदाताओं ने मुद्दों पर मतदान किया या उन पर भावनाओं का ज्वार हावी हो गया।

****

तेल रहित चावल भूसी के निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ाया

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को चार और महीने के लिए बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब इसके निर्यात पर जुलाई 2024 तक प्रतिबंध जारी रहेगा जो मार्च 2024 में खत्म हो रहा था। पशुचारा महंगा होने से दूध की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रतिबंध की समयसीमा बढ़ाई है। (एएनआइ)

हमारी योजना यह है कि कोल इंडिया और एनएलसी इंडिया नए बिजली संयंत्र कोयला खदानों के पास लगाएं। इससे परिवहन लागत में कमी आएगी और कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी।

— अमृत लाल मीणा, कोयला सचिव

एक नजर में

नए संयंत्रों पर 750 करोड़ का निवेश करेगी मदर डेयरी

नई दिल्ली : ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए मदर डेयरी कुल 750 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने कहा कि 650 करोड़ रुपये नए दूध और फल व सब्जी प्रोसेसिंग संयंत्रों की स्थापना पर निवेश किए जाएंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये मौजूदा संयंत्रों की क्षमता विस्तार पर निवेश किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नया दूध संयंत्र नागपुर और फल प्रोसेसिंग संयंत्र कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। मदर डेयरी के पास इस समय कुल नौ प्रोसेसिंग संयंत्र हैं जिनकी क्षमता 50 लाख लीटर प्रतिदिन है। (प्रेट्र)

41 हजार करोड़ रुपये घटा फ्लिपकार्ट का मूल्यांकन

नई दिल्ली : ई-कामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के मूल्यांकन में दो वर्षों यानी जनवरी 2022 से जनवरी 2024 के दौरान पांच अरब डालर करीब 41 हजार करोड़ रुपये की कमी आई है। अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वालमार्ट की ओर से इक्विटी संरचना में बदलाव के बाद फ्लिपकार्ट का मूल्यांकन जनवरी 2024 में 35 अरब डालर रह गया है जो जनवरी 2022 में 40 अरब डालर था। फ्लिपकार्ट ने मूल्यांकन में कमी के लिए फोनपे को अलग कर दूसरी कंपनी बनाने को जिम्मेदारी ठहराया है। वालमार्ट ने वित्त वर्ष 2023-24 में 3 .5 अरब डालर में फ्लिपकार्ट में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई थी। (प्रेट्र)

भारत में उत्पादन पर निवेश बढ़ाएगी डेकाथलान

पेरिस : फ्रांस की स्पोर्ट्स रिटेल कंपनी डेकाथलान भारत में अपनी उत्पादन क्षमता विस्तार पर निवेश बढ़ाएगी। कंपनी के सीईओ बारबरा मार्टिन कोपोला ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। हमें भारतीय बाजार में अपनी उच्च वृद्धि दर जारी रहने की उम्मीद है। कोपोला ने कहा कि भारत कंपनी के लिए महत्वपूर्ण मैन्यूफैक्चरिंग केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। कंपनी भारत से अपने उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा निर्यात करती है। कोपोला ने कहा कि वह भारत में खेल संस्कृति के विकास से वास्तव में प्रभावित हैं। (प्रेट्र)

भारत की मौजूदा आर्थिक तेजी 2003-07 जैसी

2003-07 में आठ प्रतिशत से अधिक थी आर्थिक वृद्धि दर

नई दिल्ली, प्रेट्र : वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मार्गन स्टेनली ने कहा है कि निवेश के दम पर आगे बढ़ रही भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार वित्त वर्ष 2003-07 जैसी लग रही है। उस समय वृद्धि दर औसतन आठ प्रतिशत से अधिक थी।

- मार्गन स्टेनली ने निवेश के आधार पर पेश की रिपोर्ट
- जीडीपी के मुकाबले निवेश 27 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया था

मार्गन स्टेनली ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि एक दशक तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले निवेश में लगातार गिरावट के बाद अब भारत में पूंजीगत व्यय वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। रिपोर्ट में स्टेनली के अर्थशास्त्रियों ने कहा, 'हमें लगता है कि पूंजीगत व्यय चक्र के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और इसलिए वर्तमान तेजी 2003-07 के समान है।' अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वर्तमान तेजी खपत की तुलना में निवेश बढ़ने के चलते है। शुरुआत में इसे सार्वजनिक पूंजीगत व्यय से समर्थन मिला, लेकिन अब निजी पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हो रही है। इसी तरह खपत को पहले शहरी उपभोक्ताओं ने सहारा दिया और बाद में ग्रामीण मांग भी बढ़ी। वैश्विक निर्यात में बाजार हिस्सेदारी बढ़ने और व्यापक आर्थिक स्थिरता से भी अर्थव्यवस्था को समर्थन मिला है। हमारा मानना है कि मौजूदा तेजी जीडीपी के मुकाबले निवेश बढ़ने के चलते है। इसी तरह के वृद्धि चक्र में 2003-07 के दौरान जीडीपी के मुकाबले निवेश 27 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया था।

जीडीपी के मुकाबले निवेश 2011 तक अपने उच्चस्तर पर था। बाद में 2011 से 2021 तक गिरावट रही। हालांकि, उसके बाद स्थिति बदलने लगी और अब जीडीपी के मुकाबले निवेश 34 प्रतिशत तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2026-27 तक इसके 36 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2003-07 के दौरान पूंजीगत व्यय में उछाल के कारण उत्पादकता, रोजगार सृजन और आय वृद्धि में तेजी आई। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को भी रोजगार मिला। जीडीपी में बचत भी 2003 की 28 प्रतिशत से बढ़कर 2008 में 39 प्रतिशत हो गई थी।

1.2 लाख करोड़ का निवेश करेगा अदाणी समूह

नई दिल्ली, प्रेट्र : अदाणी समूह अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के दौरान 1.2 लाख करोड़ रुपये (करीब 14 अरब डालर) का निवेश करने की योजना बना रहा है। यह निवेश पोर्ट से लेकर ऊर्जा, एयरपोर्ट, सीमेंट और मीडिया कारोबार में किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि समूह ने कारोबार बढ़ाने के लिए अगले सात से दस वर्षों में अपनी 100 अरब डालर की निवेश योजना को दोगुना कर दिया है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के लिए प्रस्तावित पूंजीगत खर्च चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में किए जाने वाले अनुमानित खर्च से 40 प्रतिशत ज्यादा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि समूह चालू वित्त वर्ष में 10 अरब डालर का निवेश कर सकता है।

स्विट्जरलैंड की कई कंपनियां भारत में निवेश की इच्छुक

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्विट्जरलैंड की आर्थिक मामलों की मंत्री हेलेन बडगिलर ने कहा है कि उनके देश की कई कंपनियां भारत में निवेश करने की इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड की एचईएसएस ग्रीन मोबिलिटी 2025 तक भारत में करीब तीन हजार इलेक्ट्रिक बसों की मैन्यूफैक्चरिंग करने चाहती है। इसके लिए अगले छह से आठ वर्षों में 11 करोड़ डालर का निवेश किया जाएगा। इसी तरह, चाकलेट निर्माता बैरी कैलेबाउट समूह 2024 के अंत तक अपना तीसरा मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र शुरू करने के लिए तैयार है। प्रौद्योगिकी समूह बुहलर अगले दो से तीन साल में 2.3 करोड़ डालर का निवेश करेगा। व्यापारिक समझौते के तहत आइसलैंड, नार्वे, लीशटेंस्टाइन और स्विट्जरलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डालर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकें बैंक, ग्राहकों को दें महत्व

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकने के लिए कहा है। साथ ही खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी का कहना है कि वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बैंक और जीवन बीमा कंपनियां ग्राहकों से पालिसी खरीदने के लिए धोखाधड़ी वाले और अनैतिक तरीके अपना रही हैं।

जोशी ने कहा कि इन मामलों को देखते हुए बैंकों को संवेदनशील बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों से खाताधारकों के हितों को सबसे अधिक महत्व देने को कहा गया है। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में 75 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों को जीवन बीमा पालिसी बेची गई हैं। सामान्यतया बैंक अपनी सहायक बीमा कंपनियों के उत्पाद बेचने की कोशिश करते हैं। अगर ग्राहक इसका विरोध करते हैं, तो शाखा अधिकारी ऊपर से दबाव की बात कहते हैं। जब ग्राहक किसी प्रकार का कर्ज लेने या सावधि जमा में निवेश करने जाते हैं, तो उन्हें बीमा उत्पाद बेचने की कोशिश की जाती है। जोशी ने बताया कि बैंकों को अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। सरकारी की ओर से जारी नियमों का पालन नहीं करने पर यह निर्देश दिया गया है।

विवेक जोशी

वित्तीय सेवा विभाग ने धोखाधड़ी और अनैतिक तरीके से पालिसी बेचने की शिकायतों के बाद बैंकों को दिया निर्देश

वित्त वर्ष 2022-23 में डीजल की खपत 12 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान डीजल की खपत में वार्षिक आधार पर 12.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी ऊर्जा सांख्यिकी भारत-2024 रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में कुल ईंधन खपत में डीजल की हिस्सेदारी 38.52 प्रतिशत रही है।

- पिछले वित्त वर्ष में डीजल की कुल खपत 8.59 करोड़ टन रही
- 2021-22 के दौरान बिजली की खपत 12.96 लाख गीगावाट रही

रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 के दौरान डीजल की कुल खपत 8.59 करोड़ टन रही है जो 2021-22 में 7.66 करोड़ टन रही थी। इसी तरह, 2022-23 के दौरान पेट्रोल की खपत में 13.38 प्रतिशत और पेट्रोलियम कोक की खपत में 28.68 प्रतिशत की वृद्धि रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राकृतिक गैस की खपत समय के साथ उतार-चढ़ाव रहा है। 2022-23 के दौरान ऊर्जा के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस की खपत 7.7 प्रतिशत घटकर 36,383 अरब घनमीटर (बीसीएम) रह गई। यह 2021-22 में 39,414 अरब घनमीटर थी। इसी तरह, गैर-ऊर्जा उद्देश्य के लिए प्राकृतिक गैस की खपत 1.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 2021-22 के 22,077 बीसीएम से बढ़कर 2022-23 में 22,319 बीसीएम हो गई। प्राकृतिक गैस की अधिकतम खपत उर्वरक उद्योग में 32.35 प्रतिशत की रही। इसके बाद सड़क परिवहन सहित शहर गैस वितरण नेटवर्क (20.06 प्रतिशत) का स्थान रहा।

बिजली की खपत 2012-13 के 8,24,301 गीगावाट प्रति घंटा से बढ़कर 2021-22 के दौरान 12,96,300 गीगावाट प्रति घंटा हो गई। केरोसिन या मिट्टी के तेल की खपत में 2013-14 और 2022-23 के बीच साल-दर-साल आधार पर 26 की भारी गिरावट आई है।

मिशन पाम आयल के तहत पहला प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू

रोइंग, एएनआइ: मिशन पाम आयल के तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला पाम आयल प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया है। देश की बड़ी आयल पाम कंपनियों में से एक 3एफ आयल पाम ने इसकी स्थापना की है। यह संयंत्र अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में रोइंग में स्थापित किया गया है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

यह एक अत्याधुनिक संयंत्र है। इसमें पाम आयल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग दोनों की सुविधा उपलब्ध है। यह एक शून्य अपशिष्ट संयंत्र है। इसके लिए यहां अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्र भी बनाया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश का भी पहला पाम आयल संयंत्र है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ मार्च को वर्चुअली संयंत्र का उद्घाटन करते हुए इसे परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक बताया था। 3एफ आयल पाम के सीईओ संजय गोयनका का कहना है कि खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को देखते हुए पाम आयल देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।

मार्च में 40 हजार करोड़ का एफपीआइ निवेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : मार्च में एक बार फिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआइ) घरेलू इक्विटी और डेट बाजारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। डिपाजिटरी के डाटा के अनुसार, एफपीआइ 15 मार्च तक इक्विटी बाजारों में 40,710 करोड़ रुपये और डेट बाजारों में 10,383 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक एफपीआइ इक्विटी में 16,505 करोड़ और डेट में 52,639 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं।

जानकारों का कहना है कि जनवरी में बड़ी बिकवाली करने वाले विदेशी निवेशक फरवरी में शुद्ध खरीदार रहे, लेकिन निवेश की मात्रा कम रही थी। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार का कहना है कि मार्च में एफपीआइ ने बड़े पैमाने पर खरीदारी की है। हालांकि, इसमें थोक सौदों की संख्या ज्यादा रही है। विजयकुमार का कहना है कि यह एफपीआइ गतिविधियों का वास्तविक संकेत नहीं हैं, लेकिन यह रुख आगे भी जारी रह सकता है।

- बाजार विशेषज्ञ बोले- इस महीने थोक सौदों के जरिये ज्यादा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
- कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक डेट बाजारों में 52,639 करोड़ डाले

पांच कंपनियों का पूंजीकरण 2.23 लाख करोड़ घटा

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीते सप्ताह शेयर बाजारों में रही गिरावट के चलते बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 में से पांच कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 2.23 लाख करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई। डाटा के अनुसार, बीते सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूंजीकरण 81,763 .35 करोड़ रुपये घटकर 19,19,595.15 करोड़ रुपये रह गया है। इसी प्रकार, एलआइसी के पूंजीकरण में 63,629.48 करोड़ रुपये की कमी आई है। इसके अलावा एसबीआइ के पूंजीकरण में 50,111.7 करोड़, एचयूएल में 21,792.46 करोड़ और आइसीआइसीआइ बैंक में 6,363.11 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई है।

विजयकुमार का कहना है कि अब एफपीआइ अमेरिकी बांड यील्ड के अनुसार रणनीति बदल रहे हैं। यदि महंगाई में वृद्धि से अमेरिकी बांड पर यील्ड बढ़ता है तो एफपीआइ भारतीय बाजारों से निक्सी कर सकते हैं। इक्विटी बाजारों में मार्च में मिड और स्मालकैप में कमजोरी दिखी है, जबकि लार्जकैप में लचीलापन बना हुआ है। इस कारण एफपीआइ ने लार्जकैप से बिकवाली घटा दी है और बैंकिंग, दूरसंचार व आटोमोबाइल्स में सीमित खरीदारी कर रहे हैं।

स्टार्टअप महाकुंभ में तीन हजार उद्यमी होंगे शामिल

जासं, नई दिल्ली : भारत मंडपम में सोमवार से शुरू हो रहे स्टार्टअप महाकुंभ में सफलता की कहानियां देखने को मिलेंगी। दो हजार स्टार्टअप इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें 10 थीम पवेलियन, एक हजार से अधिक निवेशक, 300 इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर, तीन हजार सम्मेलन प्रतिनिधि, 20 से अधिक देश के प्रतिनिधिमंडल, सभी भारतीय राज्यों के तीन हजार भावी उद्यमी, 50 से अधिक यूनिकार्न और 50,000 से अधिक व्यावसायिक आगंतुक शामिल होंगे।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार से शुरू हो रहे तीन दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम एसोचैम, नैसकाम, बूटस्ट्रैप इनक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन, टीआइई और इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आइवीसीए) के सहयोगात्मक प्रयासों से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय फलक

फ्लिपकार्ट ने मनमाने तरीके से रद किया आइफोन का आर्डर, अब चुकाना होगा हर्जाना

मुंबई, प्रेट्र : आइफोन का आर्डर मनमाने तरीके से रद करना फ्लिपकार्ट को महंगा पड़ा है। एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट को अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी पाया है। आयोग ने आदेश दिया कि फ्लिपकार्ट उस ग्राहक को 10,000 रुपये का भुगतान करे जिसके आइफोन के आर्डर को रद किया गया था।

- उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट को अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी पाया
- ग्राहक को हुए मानसिक उत्पीड़न के लिए करना होगा 10 हजार रुपये भुगतान

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग मुंबई ने पिछले महीने पारित आदेश में कहा, अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए जानबूझकर आर्डर को रद किया गया था। विस्तृत आदेश रविवार को उपलब्ध कराया गया। आयोग ने कहा कि हालांकि ग्राहक को रिफंड मिल गया था, लेकिन आर्डर को मनमाने तरीके से रद करने के कारण ग्राहक को हुई मानसिक पीड़ा के लिए उसे मुआवजा मिलना चाहिए।

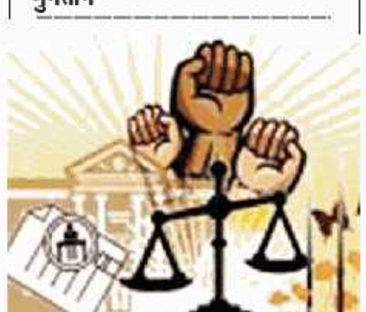

प्रतीकात्मक

दादर निवासी शिकायतकर्ता के अनुसार उसने 10 जुलाई 2022 को फ्लिपकार्ट से आइफोन आर्डर किया और क्रेडिट कार्ड से 39,628 रुपये का भुगतान किया। फोन को 12 जुलाई को पहुंचाया जाना था, लेकिन छह दिन बाद ई-कामर्स कंपनी से आर्डर रद किए जाने का एसएमएस मिला। संपर्क करने पर कंपनी ने बताया कि डिलीवरी ब्वाय ने फोन पहुंचाने के कई प्रयास किए थे लेकिन शिकायतकर्ता अनुपलब्ध था इसलिए आर्डर रद कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि आर्डर रद होने से उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ।

फ्लिपकार्ट ने अपने लिखित जवाब में कहा कि शिकायतकर्ता ने उसे उत्पाद का विक्रेता माना। जबकि वह केवल मध्यस्थ के रूप में आनलाइन प्लेटफार्म के रूप में काम करती है। प्लेटफार्म पर सभी उत्पाद थर्ड पार्टी विक्रेताओं द्वारा बेचे और आपूर्ति किए जाते हैं। इस मामले में विक्रेता इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। शिकायतकर्ता और विक्रेता के बीच हुए पूरे लेनदेन में फ्लिपकार्ट की कोई भूमिका नहीं थी।

फ्लिपकार्ट ने दावा किया कि उसने विक्रेता को शिकायतकर्ता की शिकायत के बारे में सूचित किया था। विक्रेता ने कहा कि डिलीवरी ब्वाय ने पते पर फोन पहुंचाने के कई प्रयास किए थे लेकिन शिकायतकर्ता अनुपलब्ध था इसलिए आर्डर रद कर दिया गया था। पैसा रिफंड कर दिया गया है।

हालांकि आयोग ने कहा कि ई-कामर्स कंपनी द्वारा आर्डर को एकतरफा तरीके से रद कर दिया गया था। फ्लिपकार्ट ने अपने या विक्रेता द्वारा फोन पहुंचाने के कई प्रयासों के बारे में किए गए दावे को लेकर कोई साक्ष्य नहीं दिए। आयोग ने कहा कि फ्लिपकार्ट ने स्वीकारा है कि आर्डर रद कर दिया गया था और शिकायतकर्ता को नया आर्डर देने के लिए कहा गया था। आरोप है कि आइफोन की लागत लगभग 7,000 रुपये बढ़ गई थी और इसलिए आर्डर रद कर दिया गया था और नया आर्डर देने के लिए कहा गया था।

आयोग ने बताया कि फ्लिपकार्ट ने अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था, जो अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के बराबर है। आयोग ने फ्लिपकार्ट को शिकायतकर्ता को हुए मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया।

होशियारपुर में गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ में कांस्टेबल बलिदान

जासं, होशियारपुर : पंजाब के होशियारपुर जिले के मनसूरपुर में छापेमारी करने गई सीआइए स्टाफ की टीम की गैंगस्टर सुखविंदर राणा के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गैंगस्टर ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से सिपाही अमृतपाल सिंह बलिदान हो गए। वारदात के बाद आरोपित फरार है।

एसएसपी सुरिंदर लांबा ने बताया कि मनसूरपुर निवासी गैंगस्टर सुखविंदर राणा के पास अवैध हथियार होने की सूचना पर सीआइए स्टाफ ने छापेमारी की थी। इस दौरान राणा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एक गोली अमृतपाल सिंह के सीने में जा लगी। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत मुकेरियां के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। डीएसपी विपिन कुमार ने बताया कि सुखविंदर पर नशा तस्करी, हत्या, हत्या के प्रयास व लूट समेत आठ संगीन मामले दर्ज हैं। 16 जनवरी, 2023 को अवैध असलहा रखने के आरोप में जालंधर के थाना करतारपुर मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद वह जमानत पर बाहर आया था।

बिहार में पुलिस अधिकारी बनकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने साइबर फ्राड करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते हैं। इसके बाद तमाम तरह के आरोप लगाकर उनसे वसूली करते हैं। पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अरशद समेत छह धोखेबाजों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चार लैपटाप, विभिन्न बैंकों की 27 पासबुक, चार आधार कार्ड, 17 डेबिट कार्ड, पांच पैन कार्ड, 13 अकाउंट ओपनिंग किट, चार सिम कार्ड, सात मोबाइल सेट और कई बैंकों से संबंधित कागजात जब्त किए गए हैं।

एसएसपी राकेश कुमार ने रविवार को बताया कि गिरोह के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। जांच में पता चला कि इन लोगों ने हवाला का पैसा तीन देशों में भेजा है। इस तरह से एक माह के अंदर करोड़ों की राशि का फ्राड करने की बात सामने आई है। जांच की जा रही है।

- पाकिस्तान से जुड़े हैं तार, मास्टरमाइंड समेत छह लोग गिरफ्तार, तीन देशों में भेजे गए पैसे

साइबर फ्राड मामले में गिरफ्तार छह आरोपितों के साथ प्रेसवार्ता करते दाए से पहले एसएसपी राकेश कुमार व साथ में साइबर डीएसपी। जागरण

इस तरह से करते थे ठगी : बताया गया कि साइबर फ्राड गिरोह के बदमाश जिले के विभिन्न इलाकों के लोगों के पास किसी थाने के पुलिस अधिकारी बनकर फोन करते थे। इसके बाद परिवार के किसी सदस्य को दुष्कर्म या अन्य केस में गिरफ्तार करने की बात कहकर पैसे की मांग करते थे। झांसे में आकर लोग इनके बताए खातों में पैसे भेज देते थे और ठगी के शिकार बन जाते थे। हाल में इस तरह की करीब आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं। 13 मार्च को साइबर थाने में राकेश कुमार नामक व्यक्ति ने इससे संबंधित घटना की प्राथमिकी कराई थी। उनसे 75 हजार रुपये की ठगी इसी तरह से दुष्कर्म केस में बेटे को गिरफ्तार करने की बात बोलकर की गई थी। इसके बाद एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित के नेतृत्व में साइबर थानाध्यक्ष सह डीएसपी सीमा देवी के साथ विशेष टीम का गठन किया गया था। तकनीकी बिंदुओं के तहत जांच के बाद पूरे मामले से पर्दा उठ पाया।

वन भूमि पर कब्जा में राजस्थान कांग्रेस कमेटी के महासचिव गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमीन पठान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पठान पर कोटा में वन भूमि पर कब्जा कर के फार्म हाउस बनाने का आरोप है।

वन विभाग की टीम शनिवार को फार्म हाउस से कब्जा हटाने पहुंची तो पठान और उनके साथियों ने अभद्र व्यवहार किया। टीम के साथ धक्कामुक्की भी की। इस पर पुलिस ने रविवार को पठान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पठान को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पठान ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर पिछले साल भाजपा छोड़ी थी। वह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। पुलिस ने पठान और उनकी पत्नी रजिया के खिलाफ शनिवार को अनंतपुरा थाने में मामला दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि राज्य की पूर्ववर्ती सरकार में अवैध कब्जे के कई मामले सामने आए थे।

छत्तीसगढ़ में आठ लाख का इनामी नक्सली ढेर

काकनार के जंगल में मुठभेड़ के बाद बरामद नक्सली सामग्री

नईदुनिया, कांकेर

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में शनिवार को एक मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने आठ लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया। मृत नक्सली की पहचान मनकेर के रूप में हुई है। मुठभेड़ स्थल से बीजीएल (देशी लांचर), 12 बोर की रायफल, बाकीटाकी, नक्सली साहित्य, दवाईयां व भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की है।

कांकेर के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला ने बताया कि ककानार जंगल में बीएसएफ और डीआरजी की टीम नक्सल विरोधी अभियान में निकली थी। उसी समय जंगल में सुरक्षाबलों का नक्सलियों की मिलिट्री नंबर पांच से सामना हो गया। मुठभेड़ में मनकेर मारा गया। उधर, दंतेवाड़ा जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों ने रविवार को दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया।

****

कैसे आया भूपेश बघेल का नाम

प्रथम पृष्ठ से आगे

ईडी द्वारा कोर्ट में पेश चार्जशीट में दुर्ग जिला के पाटन से विधायक भूपेश बघेल पर सट्टा एप के मालिक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से 508 करोड़ रुपये वसूली का आरोप लगाया गया था। ईडी ने विधानसभा चुनाव से पहले सट्टेबाजी सिंडीकेट के कूरियर ब्वाय व ड्राइवर असीम दास को 4.92 करोड़ रुपये की नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय उसने प्रभावशाली राजनेता बघेल तक राशि पहुंचाने का बयान दिया था। इसके साथ ही एप का प्रमोटर बताने वाले शुभम सोनी का वीडियो जारी हुआ था। जिसमें उसने बघेल को 500 करोड़ रुपये देने का दावा किया था। नईदुनिया उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। जिसके बाद शुभम सोनी के खिलाफ भी ईडी की जांच शुरू हुई है। वह अभी जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है।

अमृतसर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खुलवाया जाएगा : संधू

जासं, अमृतसर

अमृतसर संसदीय सीट से भाजपा के संभावित उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि जल्द ही अमृतसर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खुलवाया जाएगा।

अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू ने रविवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर से भेंट की। संधू ने कहा, अमेरिका सरकार द्वारा भारत में दो और नए वाणिज्य दूतावास खोले जाने हैं। इनमें से एक अमृतसर में खोलने के लिए विदेश मंत्री ने भरोसा दिया है। इससे सीमांत क्षेत्र के लोगों को वीजा लेने, व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने और दोनों देशों के लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने में सुविधा मिलेगी। संधू के मुताबिक, उन्होंने विदेश मंत्री के साथ अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कार्गो सेवाएं शुरू करने व देश-विदेश से हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी चर्चा की। कहा, अमृतसर से अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय और खाड़ी देशों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाने की असीमित संभावनाएं हैं। कार्गो सुविधाओं से व्यापारियों और किसानों को विदेशी बाजारों तक फल और सब्जियां पहुंचाने में सुविधा होगी। आय में भी वृद्धि होगी।

नई दिल्ली में रविवार को विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान बातचीत करते तरणजीत सिंह संधू। सौ. भाजपा

न्यूज गैलरी

श्रीलंकाई नौसेना ने 21 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

कोलंबो : श्रीलंकाई नौसेना ने अपने देश की समुद्री सीमा में मछली पकड़ रहे 21 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। मछुआरों को शनिवार को जाफना के पास से गिरफ्तार करने के बाद कांकेसनथुरै बंदरगाह ले जाया गया। नौसेना ने उनकी दो नौका भी जब्त कर ली। इस वर्ष अभी तक 146 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भारत-श्रीलंका के बीच लंबे समय से मछुआरों का मुद्दा बना हुआ है। श्रीलंकाई नौसेना पाल्क स्ट्रैट में कई बार भारतीय मछुआरों पर फायरिंग भी कर चुकी है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित यह पतली समुद्री पट्टी मछली के लिहाज से संपन्न क्षेत्र है और दोनों देशों के मछुआरे यहां मछली पकड़ने पहुंचते हैं। (प्रेट्र)

अफगानिस्तान में टैंकर से टकराई बस, 21 की मौत

काबुल : अफगानिस्तान के हेलमंड में हेरात-कंधार हाईवे पर रविवार सुबह एक बस और टैंकर के बीच हुई टक्कर में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 38 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 11 की स्थिति नाजुक है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, बस ने एक मोटरबाइक को टक्कर मार दी और उसके बाद तेल से भरे टैंकर से जा भिड़ी। इसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। त्रासदपूर्ण हादसे में 16 बस यात्री, दो मोटरबाइक सवार और तीन टैंकर सवारों की मौत हो गई। घायलों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। (एएनआइ)

पुतिन जीते, 2030 तक बने रहेंगे राष्ट्रपति

राष्ट्रपति चुनाव : कमजोर मुकाबले के चलते पांचवीं बार जीत हुई आसान

स्टालिन को पीछे छोड़ सबसे प्रभावी नेता बनने की राह पर

मास्को, रायटर : रूस में तीन दिनों की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई मतगणना में कुल पड़े मतों में 87.97 प्रतिशत मत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिले हैं। इस प्रकार से पुतिन ने चुनाव जीत लिया है और वह 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि रूस में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, इसलिए यह परिणाम अप्रत्याशित नहीं है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया रविवार को पूर्ण हुई। कुल 11.42 करोड़ मतदाताओं में से 72.84 प्रतिशत लोगों ने तीन दिनों में मतदान किया।

पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में रूस की सत्ता में 1999 से ही बने हुए हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते बोरिस येल्तसिन ने उन्हें जब सत्ता की बागडोर सौंपी थी तब रूस कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा था। कहा जाता है कि एक समय पुतिन रूस को अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो गए थे पर जब उन्हें लगा कि नाटो में रूस को अपेक्षित सम्मान नहीं मिलेगा तब पुतिन अपने देश को उसका पुराना गौरव लौटाने के कार्य में जुट गए। महज दस वर्षों में उन्होंने रूस की तस्वीर बदल दी और सैन्य शक्ति में अमेरिका को चुनौती देने लगे। अब वह जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए रूस के 200 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले नेता बनने की राह पर हैं।

रूस में 2024 का चुनाव तब हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध का तीसरा वर्ष शुरू हो चुका है। इस चुनाव से पूर्व पुतिन रूस की जनता को अस्तित्व का खतरा बताते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके सामने यूक्रेन पर हमले के अलावा अन्य विकल्प नहीं था। इस बीच पुतिन रूस की जनता में अपना विश्वास बरकरार रखने में सफल रहे हैं। इस चुनाव में उन्हें कड़े मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ा है, बहुत कम समर्थन वाले तीन प्रत्याशी- निकोलाइ खारितोनोव, लियोनिद स्लत्स्की और व्लादिस्लाव डावन्कोव उनके सामने हैं। जबकि यूक्रेन ने इस मौके का इस्तेमाल रूस पर हमला करने के लिए किया। चुनाव के दौरान यूक्रेनी सेना ने सीमा पर गोलाबारी की तो रूसी रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले हुए। पुतिन ने कहा है कि चुनाव बाधित करने की इन कोशिशों के लिए यूक्रेन को दंडित किया जाएगा। शुक्रवार और शनिवार को कई स्थानों पर पुतिन के विरोध में प्रदर्शन हुए थे और मतपत्रों को खराब करने की कोशिश हुई थी। रविवार को भी कुछ स्थानों पर पुतिन विरोधी नारेबाजी की सूचना है।

भारी मतदान ने जताया कि जनता में लोकप्रियता बरकरार

व्लादिमीर पुतिन। फाइल

रूस के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रविवार को मतदान के अंतिम दिन मास्को में वोटिंग करते मतदाता। रायटर

नून अंगेस्ट पुतिन का मतदाताओं पर खास असर नहीं दिखा

रूस के कुल 11.42 करोड़ मतदाताओं में से 63 प्रतिशत ने शुक्रवार और शनिवार को मतदान किया था। रविवार को दिवंगत एलेक्सी नवलनी की पत्नी और उनके समर्थकों ने नून अंगेस्ट पुतिन का नारा लगाते हुए विरोध में मतदान का आह्वान किया था लेकिन मुकाबले में मजबूत प्रत्याशी न होने के कारण इस आह्वान से पुतिन को खास नुकसान नहीं हुआ। रविवार को दोपहर में मतदान केंद्रों पर युवाओं की भीड़ देखी गई थी। मतदाताओं की ऐसी ही लाइनें भारत, आस्ट्रेलिया, जापान, आर्मेनिया, कजाखस्तान, जार्जिया और अन्य देशों में स्थित रूसी दूतावासों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर भी देखी गईं। कुल 80 लाख लोगों ने आनलाइन वोट डाला।

रूस के चुनाव में भारत में भी मतदान

रूस के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रविवार को भारत में कई स्थानों पर वोट डाले गए। चेन्नई में साइंस एंड कल्चर सेंटर के रसियन केंद्र में बने पोलिंग स्टेशन पर मत डालती रूसी महिला। एएफपी

ट्रंप की चेतावनी, वह राष्ट्रपति नहीं चुने गए तो देश में होगा खून-खराबा

बाइडन के प्रचार अभियान ने कहा, यानी वह फिर कैपिटल हिंसा को दोहराना चाहते हैं

ओहियो राज्य में चुनाव अभियान रैली के दौरान आक्रामक मुद्रा में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एपी

वाशिंगटन, एएनआइ: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अभियान में नेताओं की बयानबाजी से गरमाहट बढ़ने लगी है। रिपब्लिकन नेता पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि चुनाव में यदि वह राष्ट्रपति नहीं चुने गए तो देश में 'खून-खराबा' होगा। इस पर डेमोक्रेट नेता राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रचार अभियान की ओर से कहा गया है कि इसका मतलब ट्रंप फिर से कैपिटल हिंसा को दोहराना चाहते हैं। अमेरिका में इस वर्ष नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं।

ओहियो के डेटन में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उक्त टिप्पणी कर अपने प्रतिद्वंद्वियों को मुद्दा बनाने का मौका दे दिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि टंप वास्तव में क्या कहना चाह रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति आटोमोबाइल उद्योग के बारे में शिकायत कर रहे थे। भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि वह दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो चीन, अमेरिका में आयातित कोई भी वाहन नहीं बेच पाएगा। कहा, दोबारा राष्ट्रपति चुना गया तो वह अपने पहले दिन जेल में बंद अपने समर्थकों को माफी देंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के पराजित होने के बाद उनके समर्थकों ने छह जनवरी, 2021 को संसद (कैपिटल हिल) पर हमला कर दिया था। इस मामले में मामले में उनके कई समर्थक जेल में बंद हैं।

वहीं, राष्ट्रपति बाइडन के प्रचार प्रवक्ता जेम्स सिंगर ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान की कड़ी निंदा की। कहा, वह (ट्रंप) एक और '6 जनवरी' चाहते हैं लेकिन अमेरिकी लोग उन्हें इस नवंबर में एक और चुनावी हार देने जा रहे हैं। लोग उनके उग्रवाद, हिंसा से प्यार और बदला लेने की उनकी प्यास को अस्वीकार करते हैं। उल्लेखनीय है कि बाइडन और ट्रंप के समर्थक भी एक दूसरे के नेता पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वह खुद को बड़ा राष्ट्रवादी साबित करने में लगे हुए हैं।

पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव होते तो धांधली नहीं होती : इमरान खान

इस्लामाबाद, एएनआइ : भारत में एकतरफ समूचा विपक्ष ईवीएम का जमकर विरोध कर रहा है और इससे मतदान रुकवाने के लिए दर्जनों बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि अगर उनके देश में चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों से हुए होते तो चुनाव में धांधली नहीं होती। चुनावी हेराफेरी के मामले को एक घंटे में ही सुलझा लिया जाता।

अल-कादिर ट्रस्ट केस में उनकी बेगम बुशरा बीबी और सहयोगियों के खिलाफ सुनवाई के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआइ) के संस्थापक इमरान ने अदियाला जेल में पत्रकारों से आम चुनावों में धांधली पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग, कुछ राजनीतिक दलों और सत्ता में बैठे लोगों ने ईवीएम से वोटिंग कराने की योजना को ही तबाह कर दिया।

इमरान खान ने आम चुनाव में जनता के मतों को चुराने वाले कथित अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह का उच्च स्तरीय मुकदमा चलाने की जरूरत बताई है। उन्होंने अपने इस बयान को इंटरनेट मीडिया पर भी पोस्ट किया है। पाकिस्तानी अखबार डान की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान ने दावा किया कि उनकी पार्टी को तीन करोड़ से अधिक वोट मिले थे, जबकि बाकी 17 पार्टियों को भी कुल मिलाकर इतने ही वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के समक्ष उन्होंने चुनाव में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था और गैर सरकारी संगठनों ने भी चुनावी प्रक्रिया में खामियों को इंगित किया था। लेकिन सबसे पहले तो पीटीआइ से उसका चुनाव चिन्ह बैट ही छीन लिया गया। फिर पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ साजिश करते हुए उसे आरक्षित सीटें भी नहीं दीं। पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि उनके मतों को चुराना संविधान के अनुच्छेद छह के अनुसार देशद्रोह है।

पूर्व पीएम बोले- मत चुराने वाले अफसरों पर देशद्रोह का केस हो

खान का दावा- अकेले उनकी पार्टी को तीन करोड़ वोट मिले थे

पाकिस्तान ने आइएमएफ से कहा, सीपीईसी को अतिरिक्त कोष नहीं

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को आश्वस्त किया है कि वह समझौते की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। कहा, चीनी बिजली संयंत्रों का 493 अरब पाकिस्तानी रुपये का बकाया निपटाने को अतिरिक्त बजट आवंटित करने की उसकी कोई योजना नहीं है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचारपत्र की रिपोर्ट के अनुसार, आइएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष में चीनी बिजली संयंत्रों के लिए बजट से इतर 48 अरब रुपये के अतिरिक्त आवंटन पर पाकिस्तान सरकार के फैसले के बारे में पूछताछ की। ज्ञात हो, जनवरी के अंत तक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) की बिजली परियोजनाओं का बकाया बढ़कर 493 अरब पाकिस्तानी रुपये (1.8 अरब डालर) हो गया। यह रकम गत वर्ष जून की तुलना में 214 अरब रुपये ज्यादा है।

अब चीनी सेना ने अरुणाचल को बताया चीन का अभिन्न भाग

बीजिंग, प्रेट्र: अरुणाचल प्रदेश के संबंध में अब चीन की सेना के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उसने अरुणाचल प्रदेश को चीन का परंपरागत (अभिन्न) हिस्सा बताया है। चीनी सेना की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्ति को नकारे जाने के बाद आई है। मोदी इसी महीने चीन की सीमा तक जाने वाली सेला टनल के उद्घाटन के लिए अरुणाचल प्रदेश गए थे।

चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग शियाओगांग ने कहा, शिजांग (तिब्बत का चीनी नाम) का दक्षिणी भाग चीन का परंपरागत हिस्सा है। बीजिंग अरुणाचल प्रदेश का नाम देकर उस भूभाग पर किए जा रहे कार्यों का कड़ा विरोध करता है। प्रवक्ता ने यह बात सेला टनल और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के नजदीक भारत द्वारा

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद दूसरी बार चीन की प्रतिक्रिया

चीन के वेवुनियाद दावे को भारत ने हमेशा किया है खारिज

आधारभूत ढांचा विकसित किए जाने के बारे में कही है। ज्ञात हो, अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का चीन ने मंदारिन भाषा में नामकरण भी कर रखा है। भारत हमेशा से चीन के दावे को खारिज करता रहा है। कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी नौ मार्च को अरुणाचल प्रदेश गए थे और वहां पर उन्होंने 825 करोड़ रुपये की लागत से बनी सेला टनल का उद्घाटन किया था। रणनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण इस टनल के जरिये पूरे वर्ष भर एलएसी तक आवागमन जारी रहेगा। यह सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी कृत्रिम सुरंग है।

वेल्स के पहले अश्वेत फर्स्ट मिनिस्टर बनेंगे वान गेथिंग

लंदन, एपी: वान गेथिंग वेल्स अर्ध-स्वायत्त सरकार के पहले अश्वेत फर्स्ट मिनिस्टर होंगे। वह शनिवार को वेल्स लेबर पार्टी के नेता चुने गए। इस पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने शिक्षा मंत्री जेरेमी माइल्स को हराया। 50 वर्षीय गेथिंग मार्क ड्रेकफोर्ड के स्थान पर यह पद संभालेंगे। ड्रेकफोर्ड ने पिछले साल के अंत में घोषणा की थी कि वह पद छोड़ देंगे। वेल्स के श्वेत पिता और जांबिया की अश्वेत मां की संतान वान गेथिंग वेल्स के पांचवें फर्स्ट मिनिस्टर बनेंगे। अगले सप्ताह वेल्श की विधायिका सेनेड उनके चुनाव की पुष्टि करेगी जहां लेबर पार्टी के सबसे अधिक सदस्य हैं। यूनाइटेड किंगडम के चार क्षेत्रों में वेल्स, इंग्लैंड, स्काटलैंड और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। रक्षा, विदेश और अन्य राष्ट्रीय मामले ब्रिटिश सरकार के तहत आते हैं।

पर्यटन और निवेश के लिए यह दशक भारत का है : करकरिया

वाशिंगटन, प्रेट्र: दुनिया की सबसे बड़ी बीजा आउटसोर्सिंग कंपनी वीएफएस ग्लोबल के सीईओ जुबिन करकरिया ने कहा है कि भारत में तेजी से सामाजिक व आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। इससे व्यापार, पर्यटन व संस्कृति के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि यह दशक भारत का है। भारत की जीवंत व विविध अर्थव्यवस्था, बड़ी युवा आबादी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत निवेशकों व आगंतुकों को आकर्षित करती है।

जुबिन करकरिया ने एक साक्षात्कार में बताया कि वीएफएस ग्लोबल आने वाले पर्यटकों व बाहर जाने वाले यात्रियों दोनों के लिए भारत की संभावनाओं के बारे में बहुत आशावादी हैं। वीएफएस ग्लोबल वीजा व पासपोर्ट आउटसोर्सिंग का एक नया उद्योग बनाने के लिए जाना जाता है। यह अपनी स्थापना के 22 वर्षों में 149 देशों में 3,353 आवेदन केंद्रों के साथ काम कर रहा है। अब तक इसने 27.8 करोड़ आवेदन व 13.0 करोड़ बायोमेट्रिक्स नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। आज वीएफएस ग्लोबल 67 सरकारों का विश्वसनीय भागीदार है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और 27 शेंगेन देशों में से 24 शामिल हैं। करकरिया ने कहा कि मैंने भारत में वीएफएस ग्लोबल की परिकल्पना की और उसे लांच किया, जो अपने क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत-निर्मित पहली यूनिकार्न है।

वीएफएस ग्लोबल के सीईओ ने कहा, भारत में तेजी से हो रहा बदलाव

देश में व्यापार, पर्यटन और संस्कृति के लिए नए अवसर पैदा होंगे

मालदीव संसदीय चुनाव के लिए भारत में भी होगी वोटिंग

माले, प्रेट्र: मालदीव में 21 अप्रैल को होने वाले संसदीय चुनावों के लिए भारत के दक्षिणी राज्य केरल में भी मतदान होगा। द्वीप देश के चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए तिरुवनंतपुरम में भी पोलिंग स्टेशनों व मतपेटियों की व्यवस्था करने की घोषणा की है। आयोग ने कहा, मालदीव के 11 हजार नागरिकों के दूसरे देशों में पोलिंग स्टेशन के लिए पुनः पंजीकरण करने के बाद भारत के अलावा और दो अन्य देशों श्रीलंका व मलेशिया की राजधानियों में भी संसदीय चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे।

अखबार द सन ने मालदीव चुनाव आयोग के महासचिव हसन जकारिया के हवाले से बताया कि मतदान के लिए भारत के अलावा जिन देशों में मतपेटियां रखीं जाएंगी वे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो व मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर हैं। उन्होंने कहा, पुनः पंजीकरण विंडो अन्य देशों में रह रहे नागरिकों के लिए खोला गया था, पर तीन देशों के मतदाताओं ने पर्याप्त वारंट वाली मतपेटियों को फिर से पंजीकृत किया था'

आयोग ने कहा, इस बार ब्रिटेन, यूएई और थाईलैंड में मतदान की व्यवस्था नहीं होगी। शनिवार को समाप्त हुई पुनः पंजीकरण विंडो के दौरान अन्य विदेशी देशों के पर्याप्त मतदाताओं ने अपना पंजीकरण नहीं कराया। 93 सीटों के लिए मालदीव के संसदीय चुनाव में 389 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें से ज्यादातर प्रत्याशी (90) भारत समर्थक मुख्य विपक्षी दल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) से हैं। जबकि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन समर्थक हैं जो सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

21 अप्रैल को केरल के तिरुअनंतपुरम में भी डाले जाएंगे वोट

भारत के अलावा कोलंबो व क्वालालंपुर में भी होंगे वैलेट वाक्स

भारतीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की समीक्षा

माले, एएनआइ : भारत और मालदीव के उच्चस्तरीय कोर समूह की तीसरी बैठक माले में आयोजित हुई। दोनों पक्षों ने भारतीय विमानन के निरंतर संचालन के लिए भारतीय तकनीकी कर्मियों की चल रही प्रतिनियुक्ति की समीक्षा की। इस बीच, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा, द्वीप देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बाहरी पक्षों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा, बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मालदीव के लोगों को मानवीय व मेडवैक सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए भारतीय तकनीकी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की समीक्षा की।" चर्चा द्विपक्षीय व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने और भारत-मालदीव के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के प्रयासों पर केंद्रित थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अपनी चर्चा जारी रखी।

भारत, सेशेल्स सोमवार से करेंगे 10 दिवसीय युद्धाभ्यास

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय सेना हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रमकता के खिलाफ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सेशेल्स के एक सैन्य अड्डे पर द्वीपीय राष्ट्र के सैनिकों के साथ 10 दिवसीय व्यापक युद्धाभ्यास करेगी। भारतीय सेना ने रविवार को कहा कि यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच कौशल, अनुभव और अनुरूप अभ्यासों के आदान-प्रदान के अलावा द्विपक्षीय सैन्य संबंधों का निर्माण भी करेगा और उन्हें प्रोत्साहन देगा। यह अभ्यास सहयोगात्मक साझेदारी को भी बढ़ावा देगा और दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद करेगा।

सेशेल्स हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 115 द्वीपों का एक रणनीतिक रूप से स्थित द्वीपसमूह है और भारत के साथ रक्षा सहयोग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारतीय सेना की 45 कर्मियों वाली एक टुकड़ी 'लामितिये 2024' अभ्यास में भाग लेने के लिये रविवार को सेशेल्स रवाना हुई। संयुक्त अभ्यास 18 से 27 मार्च तक सेशेल्स में आयोजित किया जाएगा। क्रियोल भाषा में 'लामितिये' का अर्थ 'दोस्ती' है। सेशेल्स डिफेंस फोर्सेज (एसडीएफ) के भी इतने ही सैन्यकर्मी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। सेना ने कहा कि 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास, युद्ध चर्चा, व्याख्यान और प्रदर्शन शामिल होंगे।

'लामितिये 2024' द्विपक्षीय सैन्य संबंधों का निर्माण और प्रोत्साहन देगा

भारतीय सेना की 45 कर्मियों वाली टुकड़ी रविवार को सेशेल्स रवाना

बिना पासपोर्ट टोरंटो पहुंची की पीआइए की एयर होस्टेस

करांची, प्रेट्र: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआइए) के साथ कार्यरत एक एयर होस्टेस बिना अपने पासपोर्ट के इस्लामाबाद से टोरंटो पहुंच गई। कनाडा के अधिकारियों ने उस पर 200 कनाडाई डालर का जुर्माना लगाया है। जिओ न्यूज ने अपने समाचार में कहा है कि यह घटना 15 मार्च को हुई। पीआइए एयर होस्टेस विमान पीके-781 पर ड्यूटी के लिए जाते समय अपना पासपोर्ट ले जाना भूल गई। यह विमान टोरंटो जाने वाला था। समाचार में कहा गया है, 'पीआइए की एक एयर होस्टेस ने इस्लामाबाद से टोरंटो तक बिना पासपोर्ट यात्रा की। विमान लैंड होने के बाद लापरवाही का पता चला और कनाडा के अधिकारियों ने उस पर 200 कनाडाई डालर (लगभग 42000 पाकिस्तानी रुपये) का जुर्माना लगाया।'

पीआइए के प्रवक्ता ने कर्मचारी की पहचान गोपनीय रखते हुए कहा कि वह कराची हवाई अड्डे पर ही अपना पासपोर्ट भूल गई। प्रवक्ता ने कनाडा में एयर होस्टेस के राजनीतिक शरण मांगने संबंधी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वह पीके-782 से पाकिस्तान लौट रही है। हाल के सप्ताह के दौरान पीआइए के 10 से ज्यादा कर्मी कनाडा पहुंचने के बाद लापता हो चुके हैं।

नेतन्याहू ने कहा, गाजा में जारी रहेगा सैन्य अभियान

यरुशलम, रायटर : युद्ध रोकने के अंतरराष्ट्रीय दबाव को नकारते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा। नेतन्याहू का यह बयान बंधकों की रिहाई के लिए हमास की स्थायी युद्धविराम की मांग के बीच आया है। जबकि गाजा में राहत कार्य में लगी एजेंसियों ने निकट भविष्य में वहां पर बड़ी संख्या में लोगों के भूख से मरने की आशंका जताई है।

मंत्रिमंडल की बैठक में नेतन्याहू ने कहा, इजरायली सेना कुछ दिनों में रफाह के भीतर जाएगी और वहां कार्रवाई करेगी। अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के रफाह में कार्रवाई न करने के अनुरोध के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। उन्होंने कहा, विश्व क्या सात अक्टूबर, 2023 के हमास के हमले को भूल गया? वह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला था। क्या इजरायल को हमास के दानवों से अपनी सुरक्षा का अधिकार नहीं है? नेतन्याहू ने कहा, रफाह से नागरिकों को निकालकर वहां छिपे आतंकियों को पकड़ा जाएगा लेकिन इस मसले पर सहयोगी देश दुराग्रहपूर्ण रवैया प्रदर्शित कर रहे हैं। विदित हो कि रफाह मिस्र सीमा पर स्थित गाजा का छोटा सा शहर है जहां पर इस समय करीब 14 लाख बेघर लोग शरण लिए हुए हैं। गाजा के कई इलाकों में खाद्य सामग्री की कमी है। वहां पर अमेरिका और जार्डन के विमान खाद्य सामग्री गिरा रहे हैं। 200 टन राहत सामग्री लेकर यूरोप से एक जहाज भी गाजा पहुंच चुका है। जार्डन पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज ने कहा है कि इजरायली सेना अगर रफाह में कार्रवाई करती है तो वह स्थिति क्षेत्रीय शांति के लिए बेहद खतरनाक होगी। शुल्ज इजरायल की यात्रा भी करेंगे।

गाजा में युद्ध रोकने के अंतरराष्ट्रीय अनुरोध को इजरायली पीएम ने नकारा

पूछा, क्या हमास के दानवों से आत्मरक्षा का अधिकार नहीं

बेंजामिन नेतन्याहू। फाइल

अफगानिस्तान में छिपे बैठे हैं छह हजार टीटीपी आतंकी : पाकिस्तान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि राजदूत आसिफ दुर्रानी ने कहा है कि प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में टीटीपी के लगभग 5000 से 6000 छिपे बैठे हैं। दुर्रानी ने कहा कि आतंकियों के परिवारों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 70,000 पहुंच जाएगी। दुर्रानी ने इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक शांति अध्ययन के लिए पाकिस्तान संस्थान (पीआइपीएस) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शनिवार को अपने संबोधन में उक्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित टीटीपी के साथ पाकिस्तान की शांति वार्ता पूर्व में इसलिए विफल रही क्योंकि आतंकी समूह न तो समर्पण और न ही पाकिस्तान के संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करने के लिए तैयार था। विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि कोई और उनका खर्च उठा रहा है। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार इतनी बड़ी संख्या में लोगों के प्रतिदिन का खर्च वहन करने में समर्थ नहीं है। काबुल में अंतरिम सरकार से पाकिस्तान कह चुका है कि उसे टीटीपी से समर्पण कराना और समूह को हथियार विहीन बनाकर उसके अगुआ को हिरासत में लेना होगा।

****

रूस पर यूक्रेन का मिसाइल हमला

रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना के मिसाइल हमले में रूस के शहर बेलगोरोड में आवासीय इमारत में आग लग गई। इस हमले में सड़क पर खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। रायटर

अश्विन के सामने कई चुनौतियां आई हैं। उन्होंने किसी भी चुनौती को अपनी प्रगति में रोड़ा बनने का मौका नहीं दिया। वह देश के लिए एक असाधारण मैच विजेता रहा है, उसकी निरंतरता शानदार है।
— अनिल कुंबले, पूर्व स्पिनर, भारत

विश्व कप में फिट होने के लिए इंजेक्शन लगाए : पांड्या

मुंबई, प्रेट्र : हार्दिक पांड्या ने पिछले साल विश्व कप के मैचों के लिए फिटनेस हासिल करने के लिए कई इंजेक्शन लेने और अपने टखने से खून के थक्के हटाने जैसे मुश्किल उपायों का सहारा लिया, लेकिन इससे चोट और बढ़ गई और उन्हें विश्व कप से बाहर होना पड़ा। हार्दिक ने कहा कि मैंने अपनी एड़ी पर तीन अलग-अलग जगहों पर इंजेक्शन लगवाए और सूजन के कारण मुझे अपने टखने से खून निकलवाना पड़ा।

हर गेंदबाज को उसकी भाषा में जवाब दे सकते हैं यशस्वी : ज्वाला

इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में प्लेयर आफ द सीरीज चुने गए यशस्वी जायसवाल के बचपन के कोच ज्वाला सिंह का कहना है कि उनका शिष्य मानसिक मजबूती में कई खिलाड़ियों से अलग है। अगर यशस्वी आइपीएल में बल्ले से रन बनाता है तो उन्हें टी-20 विश्व कप में रोहित के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। ज्वाला सिंह से **अभिषेक त्रिपाठी** ने विशेष बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश :-

साक्षात्कार

● इंग्लैंड के विरुद्ध यशस्वी की बल्लेबाजी को कैसे आंकते हैं?

-यशस्वी ने जो क्षमता विकसित की है और जो उसकी मानसिकता है कि उसे गेंदबाज पर दबाव बनाना है। जब मैच नहीं होते थे तो हमने कई शाट्स पर काम किया। कट शाट, पुल शाट, ओवर द कवल, ओवर द बालर हेड, फ्लिक पर छक्का मारना। आजकल के क्रिकेट में डोमिनेटिंग अप्रोच बहुत जरूरी है। ये जो बैजबाल हम बोल रहे हैं, उसने इसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। वह आधुनिक युग का बल्लेबाज है, जो हर तरह के गेंदबाज को उसकी भाषा में जवाब दे सकता है। चाहे आप उसे बैजबाल या कोई और नाम दें।

● जब बात मानसिक मजबूती की होती है तो क्या लगता है कि अब यशस्वी कितना तैयार है?

-एक स्तर के बाद क्रिकेट मानसिक खेल ही है। अगर आप रणजी खेल रहे हो, भारत के लिए खेल रहे हो तो आप कई मुश्किलों को पार करके यहां पहुंचे होंगे। अहम यह है कि जब आप इतने बड़े स्तर पर खेलते हो तो मानसिक मजबूती अचानक से नहीं आती है। जहां तक यशस्वी की यात्रा रही है तो मुंबई के लिए खेलना ही बहुत मुश्किल है। मुंबई का क्रिकेट का जो ढांचा है तो आपको बचपन से ही कड़ी प्रतियोगिताएं खेलने को मिलती हैं। यशस्वी करीब नौ साल तक मेरे साथ रहा है। हम चर्चा करते थे तो मैं उसे बताता था कि ये तरीका है जिससे तू विश्वस्तरीय खिलाड़ी बन सकता है और ये तरीका है जिससे तू असफल हो सकता है। ये तेरे ऊपर है कि तुझे क्या बनना है। मैं उसे समझाता था कि सफलता और असफलता के बीच हमें अपने काम को बेहतर कैसे करना चाहिए। इसी वजह से वह मानसिक रूप से बाकी खिलाड़ियों से अलग दिखता है।

● आपके पास कई बच्चे आते होंगे कि हमारे पास घर नहीं है। हमें अपने पास रख लीजिए। आपने यशस्वी में क्या देखा जो उन्हें चुना?

-बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं 1995 में गोरखपुर से मुंबई गया। आचरेकर सर के साथ रहकर क्रिकेट सीखना मेरा सपना था। मैं आचरेकर सर से मिला, उनसे सीखा। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे चोट लग गई, तब मुझे लगा कि अब एक खिलाड़ी के तौर पर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। 2000 में मेरे पिता का देहांत हो गया। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बहुत सारे सांप होते हैं, लेकिन अजगर एक ही होता है। मुझे उनकी बात से निराशा हुई और तब मैंने निर्णय किया कि मैं एक खिलाड़ी जरूर तैयार करूंगा जो भारत के लिए खेले। यशस्वी को मैंने 2013 में आजाद मैदान पर नेट्स में खेलते हुए पहली बार देखा। तब वह बहुत छोटा था, तब लोगों ने मुझे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया। तब मैंने उसे अपने घर पर बुलाया। जब वह मेरे घर आया तो उसने बताया कि सर मुझे कोई खेलने नहीं दे रहा है। मैं एक साल से यहां-वहां घूम रहा हूं, लेकिन मुझे कोई मैच नहीं मिलता। कुछ लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं। उस समये जैसी स्थिति यशस्वी की थी, वैसी ही मेरी थी जब मैं मुंबई आया था। उसे देखकर मुझे पिता से किया वादा याद आया। मुझे लगा कि यही वो लड़का है, जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। ये भी यूपी से आया है और मैं भी। मुझे भी लोग बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं होगा। उसे भी यही बोलते हैं। कुछ दिन बाद उसके पिता उसे लेने आए थे, जब वो मुझ से मिले तो बोले कि आज से आप ही इसके माई-बाप हो। आपको जो करना है करो, बस इसको क्रिकेटर बना दो। तब मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे ये अवसर दिया कि यशस्वी से मैं वो करवाऊं, जो खुद नहीं कर पाया। आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है।

● आपका अगला सपना क्या है?

-कई कोच हैं, जिनका कोई शिष्य भारत के लिए खेलता है तो वह आराम से बैठ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपना करियर खत्म करते करते भारत खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का कोच बनूं। कई बेहतर क्रिकेटर तैयार करूं ताकि जब मैं अपना करियर खत्म करूं तो आने वाली नई पीढ़ी को लगे कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। मेरे कई शिष्य अभी मुंबई की जूनियर टीम में खेल रहे हैं, जल्दी वे भी ऊपर आ जाएंगे।

● इंग्लैंड सीरीज के बाद क्या आपकी यशस्वी से बात हुई?

-मेरी फोन पर उससे कम ही बात होती है। कभी उसे लगता कि उसका प्रदर्शन गिर रहा है तो वह मुझे फोन करता है। मैं उन्हें संदेश देता हूं। हाल फिलहाल में मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैं जब मुंबई जाऊंगा तो उसका आइपीएल शुरू हो जाएगा। देखते हैं कि कब उससे मिलने का अवसर मिलता है।

● आइपीएल के बाद टी-20 विश्व कप आने वाला है। आपको लगता है कि यशस्वी को रोहित के साथ ओपनर के रूप में टीम में जगह मिलनी चाहिए?

-काफी कुछ आइपीएल पर भी निर्भर करेगा। अगर उसका फार्म आइपीएल में भी अच्छा रहता है तो उसे जरूर टी-20 विश्व कप में मौका मिलना चाहिए। आइपीएल को दो महीने हैं, 14 लीग मैच हैं। इन मैचों में वह कैसा प्रदर्शन करता है, फिटनेस कैसी रहती है। ये इस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन आज की बात करूं तो विश्व कप में रोहित और यशस्वी ओपन कर सकते हैं।

● यशस्वी के गोल गप्पे की कहानी की बहुत बात होती है। क्या आपको लगता है कि अब इसे पीछे छोड़ देना चाहिए?

-2013 के पहले वह आजाद मैदान के पास रहता था। वहां बहुत सारे खाने के स्टाल है। जब वह खेलता नहीं था तो वहां जाकर खड़ा हो जाता था। यही सच्चाई है, वह कभी फ्रूट की दुकान पर तो कभी गोल गप्पे की स्टाल पर मदद कर देता था। जब वह मेरे पास आया तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बाद में जब मीडिया में इस तरह की बातें आईं तो मैंने उससे पूछा तो बोला कि ये सब मुझे भी अच्छा नहीं लगता। 2018 में जब वह अंडर-19 टीम में चुना गया तो कुछ टीवी चैनल वाले मेरे पास आए और कहा कि हमें गोल गप्पे वाला क्लिपिंग चाहिए। उन्होंने काफी अनुरोध किया तो मैं उसे आजाद मैदान के पास एक ठैली पर लेकर गया तो मैंने उससे कहा कि एक-दो गोलगप्पे खिला दे। लेकिन कुछ न्यूज चैनल वालों ने उसका वीडियो बना लिया। अब ये होता है कि जब भी यशस्वी कुछ अच्छा करता है तो मीडिया ये वीडियो और फोटो दिखाते हैं और स्टोरी आती है कि वह सुबह वह पिता के साथ गोल गप्पे बेचता था और शाम को प्रैक्टिस करता था। ये बिल्कुल गलत है। जबकि उसके पिताजी केवल पांच बार ही मुंबई आए।

- यशस्वी को भारत का अगला सुपरस्टार के रूप में देखा जा रहा है। आपको एक कोच के रूप में कैसा लगता है?

-देखिये, जब हम किसी खिलाड़ी के लिए बोलते हैं कि ये अगला सचिन या अगला विराट है तो ये उस खिलाड़ी का मौजूदा प्रदर्शन देखकर कहा जाता है। आप एक सीरीज में सुपरस्टार होते हो तो अगली में स्ट्रगल करते हो। उसका अगला सुपरस्टार बनना इस बात पर निर्भर है कि वह हर घंटे, हर दिन, हर महीने या हर साल पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से प्रदर्शन करे। जिस प्रक्रिया से गुजरकर वह यहां तक आया है, अगर उसे आगे भी जारी रखेगा तो सफल होगा। अगले 10 वर्षों में उसके सामने जो चुनौतियां आएंगी, जो उसे पार करना होगा।

एक नजर में

अलकराज ने सिनर का विजय अभियान थामा

इंडियन वेल्स : कार्लोस अलकराज ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके जैनिक सिनर के पिछले 19 मैच से चल रहे विजय अभियान पर रोक लगाई तथा बीएनपी परिबास ओपन इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। अलकराज ने वर्षा से प्रभावित इस मैच में सिनर को 1-6, 6-3, 6-2 से हराया। फाइनल में अलकराज का मुकाबला रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा। मेदवेदेव ने टामी पाल को 1-6, 7-6, 6-2 से पराजित किया। (एपी)

विक्रमादित्य, गुरु प्रकाश में होगा खिताबी मुकाबला

मुंबई : विक्रमादित्य कुलकर्णी और गुरु प्रकाश ने रविवार को यहां इंडियन चेस स्कूल की ओर से आयोजित ढाई लाख रुपये की पुरस्कार राशि की ग्रांप्रि शतरंज सीरीज की खिताबी भिड़ंत में जगह बनाई। विक्रमादित्य ने संजीव मिश्रा पर जीत प्राप्त की जबकि गुरु प्रकाश ने अरविंद अय्यर को पराजित किया। दोनों खिलाड़ियों के छह में से 5.5 अंक हैं। (प्रेट्र)

जान पैरी ने जीता खिताब

ताइइ : खंड के कोटा खंडेला-सराय सीमा स्थित क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट्स क्लब में चल रही दिल्ली चैलेंजर गोल्फ प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। इसमें इंग्लैंड के जान पैरी विजेता रहे। विजेता गोल्फर को 48 हजार डालर (39.78 लाख रुपये) के चेक सहित ट्राफी देकर सम्मानित किया गया। दिल्ली चैलेंजर्स प्रतियोगिता का शुभारंभ 14 मार्च को हुआ था। इसमें 28 देशों के करीब 156 गोल्फरों ने हिस्सा लिया। (संस)

डी पोल बने गोलकीपिंग कोच

नई दिल्ली : भारत ने पेरिस ओलिंपिक में पुरुष हाकी टीम की सहायता के लिए नीदरलैंड्स के गोलकीपिंग विशेषज्ञ डेनिस वान डी पोल को फिर से अपने सहयोगी स्टाफ में शामिल किया है। वान डी पोल इससे पहले भी भारतीय टीम के साथ 2019 में काम कर चुके हैं। भारतीय टीम अभी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में भाग ले रही है। वान गोलकीपर पीआर श्रीजेश, कृष्णा पाठक और सूरज करकेरा के साथ मिलकर काम करेंगे। (प्रेट्र)

लड़कियों ने खत्म किया आरसीबी का इंतजार

डब्ल्यूपीएल के फाइनल में दिल्ली को आठ विकेट से हराया, 16 वर्ष में आरसीबी ने जीती कोई ट्राफी

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

आइपीएल के 16 वर्षों के इतिहास में जो काम राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, डेनियल विटोरी, विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस कप्तान के रूप में नहीं कर पाए, वो काम स्मृति मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के दूसरे सत्र में ही कर दिखाया। मंधाना ने अपनी कप्तानी में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को चैंपियन बनाकर दिखा दिया। आरसीबी ने रविवार को डब्ल्यूपीएल फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट से हराकर ट्राफी अपने नाम की। आरसीबी की टीम 2008 में बनी थी, लेकिन ट्राफी उससे दूर थी। अब 16 साल बाद उसने पहली ट्राफी जीतकर ये खिताबी सूखा भी खत्म कर दिया। ट्राफी जीतने के बाद महिला टीम ने आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से वीडियो काल पर बात की और इस बल्लेबाज ने भी महिला टीम के लिए एक्स पर लिखा, सुपरबुमेन।

वहीं दिल्ली कैपिटल्स के कुछ भी नहीं बदला। मेग लैनिंग की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिछले साल भी अंक तालिका में शीर्ष पर रहकर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन मुंबई इंडियंस के हाथों उसे हार मिली। इस बार भी टीम आठ में से छह मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर रहकर फाइनल में पहुंची थी और इस बार उसे आरसीबी से हार झेलनी पड़ी।

ताश के पत्तों की तरह ढही दिल्ली की बल्लेबाजी : आरसीबी की स्पिन तिकड़ी ने दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी को घुटनों पर ला दिया। एक समय 64 रन पर कोई विकेट न गंवाने वाली दिल्ली की टीम ने अपने 10 विकेट केवल 43 रन पर गंवा दिए और टीम केवल 113 रन पर आलआउट हो गई। दिल्ली का ये टूर्नामेंट में अब तक का सबसे कम स्कोर है। कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने टास जीतकर जब बल्लेबाजी चुनी तो उनका निर्णय बिल्कुल सही लग रहा था। पहले बल्लेबाजी करो और बड़ा स्कोर बनाकर दूसरी टीम को दबाब में लाओ। पहले ओवर में लैनिंग (23) को जीवनदान मिला, जब वह रनआउट होने से चूक गईं। लेकिन इसके बाद लैनिंग और शेफाली वर्मा (44) ने तूफानी बल्लेबाजी की और मैदान के चारों और आकर्षक शाट लगाए। दोनों ने पावरप्ले खत्म होने तक 61 रन जोड़ दिए थे और टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी।

मोलिन्युक्स ने बदला मैच : गेंदबाजों की लगातार हो रही पिटाई के बाद आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने स्पिनर सोफी मोलिन्युक्स को गेंद सौंपी और उनका ये दांव सफल रहा। मोलिन्युक्स ने एक ही ओवर में शेफाली, जेमिमा रौड्रिग्ज और एलिस कैप्सी को आउट कर मैच का रुख बदल दिया। शैफाली जहां छक्का मारने के प्रयास में सीमारेखा के पास कैच आउट हुईं, तो जेमिमा और कैप्सी खराब शाट खेलकर अपना विकेट दे गईं। दोनों खाता भी नहीं खोल पाईं। एक ही ओवर में तीन विकेट गिरने के बाद दिल्ली के खेमे में खलबली मच गई। श्रेयंका पाटिल ने 10वें ओवर में कप्तान लैनिंग को आउट कर दिल्ली की रही सही उम्मीदों को भी झकझोर दिया। बाकी बल्लेबाजों ने लापरवाही से अपने विकेट गंवाए। श्रेयंका ने दिल्ली के निचले क्रम को ध्वस्त किया तो आशा ने मारिजाने कैप और जेस जोनासन के बिकेट लिए। दिल्ली के नौ बिकेट इन तीनों गेंदबाजों ने लिए, जबकि राधा यादव रन आउट हुईं। दिल्ली ने अपने अंतिम सात विकेट केवल 23 रन के भीतर गंवाए। श्रेयंका ने चार, मोलिन्युक्स ने तीन और शोभना ने दो विकेट लिए। वहीं मोलिन्युक्स ने शानदार थ्रो पर एक रनआउट भी किया।

पैरी का कमाल : आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम को रन बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। मंधाना (31), एलिस पैरी (35) और सोफी डिवाइन (32) ने टीम को जीत दिलाकर इतिहास रच दिया।

दिल्ली कोहराने के बाद डब्ल्यूपीएल ट्राफी के साथ आरसीबी टीम के खिलाड़ी ● एक्स

6 करोड़ रुपये मिले विजेता टीम आरसीबी को

3 करोड़ रुपये उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स को मिले

आरेंज कैप (सर्वाधिक रन)

बल्लेबाज	टीम	रन
एलिस पैरी	आरसीबी	347
मेग लैनिंग	दिल्ली	331
शेफाली वर्मा	दिल्ली	309

पर्पल कैप (सर्वाधिक विकेट)

गेंदबाज	टीम	विकेट
श्रेयंका पाटिल	आरसीबी	13
आशा शोभना	आरसीबी	12
मोलिन्युक्स	आरसीबी	12

फेयर प्ले अवार्ड : आरसीबी
एमर्जिंग प्लेयर : श्रेयंका (आरसीबी)

खचाखच भरा अरुण जेटली स्टेडियम

डब्ल्यूपीएल फाइनल के लिए दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम रविवार को खचाखच भरा था। करीब 35 हजार की क्षमता वाले स्टेडियम में 28,781 दर्शक मौजूद रहे। इसके लिए डीडीसीए और उसके अध्यक्ष रोहन जेटली ने काफी मेहनत की थी। दर्शकों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए थे।

मैच जीतने के बाद विराट से वीडियो काल पर बात करतीं स्मृति मंधाना ● एक्स

आरसीबी की जीत का दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक जश्न

नई दिल्ली, जेएनएन : आरसीबी महिला टीम ने जैसे डब्ल्यूपीएल खिताब जीता, 16 वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे प्रशंसक दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक जश्न में डूब गए। प्रशंसकों का उत्साह इतना अधिक था कि वे हजारों की संख्या में सड़क पर उतर आए। आरसीबी का झंडा और पटाखे लेकर प्रशंसकों ने सड़कों पर खूब जश्न मनाया।

बेंगलुरु में जश्न मनाते आरसीबी टीम के प्रशंसक ● प्रेट्र

आइपीएल खेलने के लिए विराट कोहली भारत लौटे

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपने बेटे अकाय के जन्म के बाद रविवार को भारत लौट आए और आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के लिए अपनी फ्रेंचाइजी रायल चैलेंजर्स बैंगलुरु के ट्रेनिंग शिविर में जुड़ने को तैयार हैं। कोहली ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला लेते हुए भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज से हटने का निर्णय लिया था। बाद में बताया गया कि यह ब्रेक इसलिए लिया गया ताकि यह स्टार बल्लेबाज ब्रिटेन में अपने बेटे के जन्म के समय अपनी पत्नी के साथ रह सके।

आइपीएल प्रसारक ने ट्वीट किया, 'विराट कोहली लौट आए हैं। 'रेड किंग' भारत में 22 मार्च को सीएसके के विरुद्ध अपना आइपीएल अभियान शुरू करने के लिए तैयार हैं।' इसमें लिखा था, 'किंग के लिए चीयर करने और 'किंगली बीट्स' पर थिरकने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स का नया एंथम 'कोहली कालिंग' सभी मंच पर रिलीज हो गया है। इस आइपीएल में कोहली के संबंध में सभी चीजों के लिए स्टार स्पोर्ट्स पर ट्यून करें।' कोहली रविवार को मुंबई पहुंचे और उनके जल्द ट्रेनिंग शिविर से जुड़ने की आशा है।

विराट कोहली ● एक्स

मिंज आइपीएल से बाहर

जासं, रांची : झारखंड के रोबिन मिंज आइपीएल से बाहर हो गए हैं। मिंज इस महीने सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। गुजरात टाइटंस ने रोबिन को 3.60 करोड़ में खरीदा था। गुजरात के कोच आशीष नेहरा ने बताया कि रोबिन पूरी तरह से फिट नहीं है, जिसके कारण वह नहीं खेल पाएंगे। रोबिन के लिए यह बहुत बड़ा झटका है।

पाकिस्तान के कोच नहीं बनेंगे वाटसन और सैमी

कराची, प्रेट्र : शेन वाटसन और डेरेन सैमी ने पाकिस्तान का मुख्य कोच बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, जिससे पीसीबी की विदेशी कोच की तलाश अब भी पूरी नहीं हुई। सैमी ने बताया कि वह पहले से ही वेस्टइंडीज बोर्ड के साथ सीमित ओवरों की टीम के मुख्य कोच के रूप में अनुबंधित हैं। वहीं, वाटसन उनके प्रस्तावित पैकेज की जानकारी पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर आने से नाराज हो गए और पीसीबी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद शनिवार को स्वदेश लौट गए।

नसीम बोले, टीम में असुरक्षा का माहौल रहता है : तेज गेंदबाज नसीम शाह ने कहा कि पाकिस्तान की टीम में असुरक्षा का माहौल है। खिलाड़ी आराम नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी जगह कोई और ले लेगा।

गुलवीर ने तोड़ा 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकार्ड

नई दिल्ली, प्रेट्र : एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता एथलीट गुलवीर सिंह ने कैलिफोर्निया के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में द टेन प्रतियोगिता में पुरुषों की 10000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ते हुए अपनी हीट में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने शनिवार को अपनी स्पर्धा में 27 मिनट, 41.81 सेकेंड का समय लेकर सुरेंद्र सिंह के 2008 में बनाए गए 28 मिनट, 02.89 सेकेंड के रिकार्ड को तोड़ा।

गुलवीर का यह प्रयास हालांकि पेरिस ओलिंपिक के क्वालिफिकेशन के लिए पर्याप्त नहीं था। पेरिस ओलिंपिक का क्वालिफिकेशन समय 27 मिनट है और इस तरह से यह भारतीय एथलीट 41 सेकेंड के अंतर से चूक गया।

राष्ट्रीय फलक

छोटी उम्र में बड़ी उड़ान

जागरण संवाददाता, बैजनाथ

मिजोरम के रहने वाले और भारत के सबसे युवा पैराग्लाइडिंग पायलट 11 वर्षीय सेमुएल ने बिलिंग पहुंचकर अकेले उड़ान भरी और दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन पैराग्लाइडिंग टेक आफ साइट से कीर्तिमान स्थापित किया। बच्चे ने 15 मिनट तक हवा में सफर किया।

सेमुएल यहां पैराग्लाइडिंग भी सीख रहा है। जैसे ही साइट पर सफल लैंडिंग की तो समूचा क्षेत्र तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठाया। मां ने बेटे को गले से लगा लिया। शायद यह भारत में पहला मौका होगा जब इतनी कम उम्र के बच्चे ने भारत की सबसे बेहतरीन पैराग्लाइडिंग टेक आफ साइट से अकेले उड़ान भरी हो। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने बच्चे को सफलता के लिए बधाई दी है और इंटरनेट मीडिया पर फोटो जारी की हैं। सेमुएल बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के माध्यम से ही पैराग्लाइडिंग की बारीकियां सीख रहा है।

बीड़ में टेक आफ साइट पर सफल लैंडिंग के बाद 11 वर्षीय सेमुएल। जागरण

पैरा तीरंदाज शीतल देवी चुनाव के लिए दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित

नई दिल्ली, एएनआइ : पैरा तीरंदाज व अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। चुनाव आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के सहयोग से भारतीय बधिर क्रिकेट संघ (आइडीसीए) टीम और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) टीम के बीच प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन किया। इस दौरान यह घोषणा की गई। इस पर शीतल देवी ने कहा, उनकी उम्र 17 साल है। अगली बार वह भी मतदाता बन कर चुनाव पर्व में भाग लेंगी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी आइकन बनाए जाने पर चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया।

शीतल देवी फाइल

शीतल ने कहा, सभी मतदाता चुनाव के इस पर्व में भाग लें और देश का गर्व बने। इस कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता टीम को बधाई दी। प्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्रिकेटर निखिल चोपड़ा को भी डीडीसीए और आइडीसीए के अधिकारियों के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह क्रिकेट मैच सीईसी राजीव कुमार द्वारा भारतीय बधिर क्रिकेट टीम के प्रति की गई प्रतिबद्धता का उदाहरण है, जब उन्होंने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की पूर्व संध्या पर संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित टी20 चैंपियंस ट्राफी जीतकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया।

सिद्धू मूसेवाला के घर गूंजी किलकारी

दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर में खुशी का माहौल है। उनकी मां चरण कौर ने 58 वर्ष की उम्र में बेटे को जन्म दिया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने नवजात शिशु के साथ अपनी तस्वीर साझा की है और इंटरनेट मीडिया पर लिखा है, 'शुभदीप (सिद्धू मूसेवाला का वास्तवित नाम) को चाहने वाले करोड़ों लोगों के आशीर्वाद ने शुभ के छोटे भाई को हमारी गोद में डाल दिया है। वाहे गुरु के आशीर्वाद से परिवार स्वस्थ है। उल्लेखनीय है कि चरण कौर ने बेटे को जन्म देने के लिए आईवीएफ तकनीक का उपयोग किया है। प्रेट्र

दैनिक जागरण
सप्तरंग
साहित्य और संगीत का
सोमवार, 18 मार्च, 2024

मौसम लगता नया-नया

नवगीत

यश मालवीय
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

सजी होलिका
नुक्कड़ पर, चौराहों पर
उड़ने लगा अबीर, पुरानी राहों पर।

बीतराग जाने कितने दिन,
याद आए
हरसोले हम रहे सुर्खरू,
शाद आए
चाहे जितने पहरे लगे निगाहों पर।

सतरंगा हो गया
धूप का दर्पण भी,
सकुचाया लगता
सर्वस्व समर्पण भी,
एक सिर टिका
खुली-खिली सी बांहों पर।

रंगों ने दस्तखत कर दिए
रंगों पर,
लगा बरसने फागुन
मस्त-मलंगों पर,
हुए निछावर,
हम अपनी ही चाहों पर।

बड़े सवेरे,
मुर्गा टेर लगा गया,
कोई सपना घर की देहरी
लांघ गया,
कान फिर लगे
सच्चाई अफवाहों पर।

खुशबू का घेरा,
कुछ थोड़ा घेर गया
जाड़ा उतरा,
मौसम लगता नया-नया
फूल खिल गए,
भूली-बिसरी आहों पर।

artiyash23@gmail.com

भाषा विमर्श

डा. बुद्धिनाथ मिश्र
देहरादून, उत्तराखंड

वसंत की पुष्पिता भाषा हिंदी

वसंत ऋतु प्रकृति की भाषा सुनने का अवसर देती है, जिसे गीता में भगवान श्रीकृष्ण 'पुष्पिता वाणी' कहते हैं। यह विभिन्न गोत्र के शब्दों के फूल खिलने और रंग व सुगंध बिखेरने की ऋतु है। जानते हैं वसंत ऋतु के शब्द-पुष्पों की सुरभित भाषा क्या है...

हमारी भाषा भी हमारी चेतना की इकाई है। वह जड़ पदार्थ नहीं, सजीव प्राणी की तरह जन्मती है, दुख-सुख झेलती है और सम्मानित-अपमानित होती है। हिंदी दुनिया की सबसे जीवंत, सबसे प्राणवंत भाषा है, इसलिए नदियों की कलकल ध्वनि, चिड़ियों की चहचहाहट, वर्षा की फुहार, वसंत से लेकर टेसू तक के रंग और पराग के सौरभ, ये सब अपने शब्दों में समेटती हुई चलती है। सावन की कजरी से लेकर फागुन के फाग तक हिंदी की विरासत है। बोली और भाषा का अंतर हमारे लिए नहीं है। कोयल की कूक उसकी बोली भी है और भाषा भी। स्वरों के आरोह-अवरोह से वह अपनी भाषा में प्रेयसी कोयली को बुला लेता है। पशु-पक्षियों की भाषा से रामायण के पात्र सुपरिचित थे, हम ही भूल गए। अन्यथा, जान पाते कि हिंदी में वृक्ष-लताएं, फूल-पत्ते, नदी-पहाड़, खेतों की फसलें और चांद-तारे कैसे बोलते-बतियाते हैं। वसंत ऋतु के चार मास प्रकृति की उसी भाषा को सुनने के मास हैं, जिसे गीता में भगवान श्रीकृष्ण 'पुष्पिता वाणी' कहते हैं। हर मौसम अलग-अलग गोत्र के शब्दों के फूल खिलकर रंग और सुगंध बिखेरने का मौसम है। वसंत कुछ अधिक ही रसिक और संवेदनशील है।

बरसात में सामान्यतः साधु-संतों के चार मास के व्रत के रूप में प्रसिद्ध चातुर्मास के अलावा एक दूसरा चातुर्मास भी है-वासंती, जिसमें 'मदन महोत्सव' मनाने की सुदीर्घ परंपरा रही है। चातुर्मास होता है चार मास। चतुर यानी चार संख्या। भारतीय परिवेश में ऋतुएं दो-दो मास पर बदल जाती हैं। इसलिए हमारे यहां छह ऋतुएं होती हैं-पावस (सावन-भादो), शरद (आश्विन-कार्तिक), हेमंत (अगहन-पूस), शिशिर (माघ-फागुन), वसंत (चैत-बैसाख) और ग्रीष्म (जेठ-आषाढ़)। वसंत प्रेम और सौंदर्य की उपासना की ऋतु है। पूरी प्रकृति फूलों-मंजरियों से लद जाती है, इसलिए इसका एक नाम 'पुष्प-समय' भी है। प्रेम, सौंदर्य और यौवन की ऋतु वसंत को ऋतुराज (ऋतुओं का राजा) माना गया। उपहारस्वरूप उसके हिस्से में शिशिर ऋतु के दो मास भी डाल दिए गए। आज फागुन को कोई शिशिर का मास नहीं मानेगा। यह वसंत का प्रमुख मास बन गया है, जिसके अंतिम दिन रंगपर्व मनाया जाता है। फाग के गीत मिलन के गीत होते हैं :

सदा आनंद रहे ओहि द्वारे।
मोहन खेले होरी हो।

यह होली की शाम तक गाया जाता है। उसके बाद चैती यानी विरह वेदना के गीत शुरू हो जाते हैं :

सांसों के गजरे कुम्हलाए।
आए न आए।

वसंत के देवता कामदेव हैं, जो प्रेम-शृंगार के देवता हैं। पुरुष सौंदर्य में कामदेव और स्त्री सौंदर्य में उनकी पत्नी रति आदर्श प्रतिमान हैं। तुलसीदास जी श्रीराम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह बैठते हैं-कोटिक काम लजावनहारी। श्रीराम के सौंदर्य के समक्ष करोड़ों कामदेव निस्तेज हो जाते हैं। कामदेव का मदन नाम मन में अतिशय हर्ष भरने के कारण पड़ा। वे चेतना (मत्) को मथते हैं, अतः मन्मथ हुए। वे उत्कंठा पैदा करते हैं, इसलिए, स्मर हैं। योगेश्वर शिव ने तप भंग करने पर इन्हें अपने तृतीय नेत्र की ज्वाला में भस्म कर दिया था, जिससे ये अनंग (अन्+अंग = देहरहित) हो गए। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने इन्हें प्रत्येक प्राणी के चित्त में बसने का वरदान दे दिया, ताकि सृष्टि चलती रहे। मन में यदि काम भावना न रहे तो कोई जीव सृजन के लिए उद्यत ही न हो। प्राणियों के मन में उत्पन्न होने से ये 'मनोज' (मन+ज, जात = उत्पन्न) कहलाये। मनसिज का भी यही अर्थ है- मनसि = मन में, ज = उत्पन्न। इसी अर्थ में इन्हें 'विश्वकेतु' भी कहा गया कि इनका झंडा (केतु) संपूर्ण विश्व में फहराता है।

'मीनकेतन' (झंडे पर मछली का निशान) मकरध्वज (ध्वज पर घड़ियाल का निशान) आदि नाम भी कामदेव के ही हैं। काम भावना अतिशय बलशाली होती है, जिससे एक नाम 'प्रद्युम्न' पड़ा। द्युम्न का अर्थ बल होता है। प्रद्युम्न यानी प्रकृष्ट (उत्कृष्ट) बलशाली। वैसे पौराणिक कथा यह है कि शंबर राक्षस के वध के लिए श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में ये पैदा हुए, जिससे उनका एक नाम सम्बरारि भी पड़ा। कामदेव के 'पुष्पधन्वा' यानी फूलों का धनुष वाला भी कहा जाए, किंतु शास्त्रों में उनका धनुष इक्षुदंड (गन्ने) का है, जिस पर डोरी भ्रमरों की पंक्ति की है। कामदेव के बाण पांच फूलों के हैं, जिससे उनका नाम 'पंचशर' है। ये पांच फूल हैं- अरविंद (कमल), अशोक, आम, नव मल्लिका (चमेली) और नीलोत्पल (नीला कमल)। इन पांचों बाणों के कार्य क्रमशः हैं-उन्मादन,तापन, शोषण, स्तम्भन और सम्मोहन। कामदेव का वाहन शुक (तोता) है।

buddhinathji@gmail.com

वर्ग पहेली-2577

बाएं से दाएं

1 पूर्वानुमान द्वारा गणना करना (4) I 3 कमी होना, दाने-दाने को मोहताज होना (2,3) I 6 रत्नों का समूह, समुद्र (4) I 8 पांव के नीचे की तली (3) I 9 रुष्ट, दुखी, अप्रसन्न (3) I 10 कान में धीरे से कही हुई बात (4) I 12 चुनौती (4) I 15 वर यात्रा (3) I 17 गति, चाल, वेग (3) I 18 दया करने वाला (4) I 19 अपने को तुच्छ समझने का भाव (3,2) I 20 पाल में बांधने का रस्सा (4) I

ऊपर से नीचे

1 मुख्य आधार या सहारा (3,2) I 2 कृत्रिम जलमार्ग (3) I 4 लिखित आज्ञा पत्र (4) I 5 जो जायज न हो, अनुचित (4) I 7 कली, बिना खिला हुआ फूल (3) I 8 जिले का प्रशासनिक उपखंड (4) I 11 जिस पर कशीदे काढ़े गए हों (4) I 13 चाल-चलन, ढंग (3) I 14 संतोषी, सहने वाला (5) I 15 एक प्रकार की मिठाई (4) I 16 द्रव्यता, चंचलता (4) I 18 दबा-कुचला हुआ, पिछड़ा, विदीर्ण (3) I

© Bird Features & Writing Agency

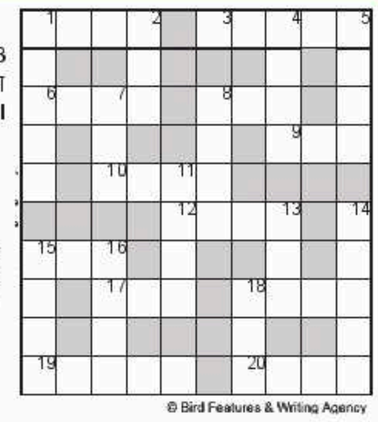

कल का हल

स	न	क				स	रा	ह	ना
रा		र	क	म		ब			खु
स				ग	ज	ब		ना	श
र	तौ	धी		ज				लि	
		र				खो	मो	श	
	स	ज	ग				ह		
	त्सं				स		क	च	रा
जं	ग		तं	ग	ड़ा				ह
ह			ड़		ना	ची	ज		ज
र	क्त	चा	प				रा	गि	नी

जागरण सुडोकू-2577

		5		2		4		8
2	1				3			5
		7	4		5		1	
8			3			5		7
	4	3			6		9	
9				7				4
4				3		1	8	
		9		1			4	
1			7		2			3

कल का हल

1	9	5	4	8	2	6	7	3
8	4	6	9	3	7	1	2	5
7	3	2	6	1	5	8	4	9
3	8	4	7	9	6	5	1	2
2	6	7	8	5	1	3	9	4
9	5	1	3	2	4	7	8	6
6	2	8	5	7	9	4	3	1
5	7	9	1	4	3	2	6	8
4	1	3	2	6	8	9	5	7

आज का भविष्यफल- 18 मार्च, 2024 सोमवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष नवमी।
आज का राहुकाल : प्रातः 07 बजकर 30 मिनट से 09 बजे तक।
आज का दिशाशूल : पूर्व।

कल 19 मार्च, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : उत्तर
कल का पर्व एवं त्योहार : श्री हरि जयंती
विक्रम संवत 2080 शके 1945
उत्तरायण, वसंत ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की दशमी तत्पश्चात एकादशी पुनर्वसु नक्षत्र 20 घंटे 10 मिनट तक, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र शोभन योग 16 घंटे 37 मिनट तक तत्पश्चात अतिगंड योग मिथुन में चंद्रमा 13 घंटे 37 मिनट तक तत्पश्चात कर्क में।

मेष : पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
वृष : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।
मिथुन : व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। सामाजिकता में रुचि बढ़ेगी।
कर्क : समस्या का समाधान होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
सिंह : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
कन्या : शैक्षिक प्रयास सार्थक होगा। व्यावसायिक सफलता मलेगी।
तुला : जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। अधिकारी का सहयोग मिलेगा।
वृश्चिक : समस्या का समाधान होगा। पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा।
धनु : पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी लेकिन मन खिन्न रहेगा।
मकर : दांपत्य जीवन सुखमय होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।
कुंभ : मन खिन्न रहेगा। तनाव मिल सकता है। जोखिम न उठाएं।
मीन : संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी।

संगीतायन

दिनेश पाठक
ग्वालियर, मध्य प्रदेश

शहनाई को दिलाया शास्त्रीय संगीत में मान

शास्त्रीय संगीत में स्वतंत्र वाद्य के रूप में शहनाई की मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की गूंज फिल्म संगीत में भी सिर चढ़कर बोली। इस वाद्य को लोकप्रियता उनके कारण ही मिली...

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां (21 मार्च, 1916-21 अगस्त, 2006)

पिछली सदी के छठे दशक में संगीत नगरी ग्वालियर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का शहनाई वादन होना था। आते ही हाथ-मुंह धोकर कपड़े बदले और साथियों के साथ मंच पर पहुंच गए। शहनाई वादन देर रात तक चलता रहा। दूसरे दिन सुबह वापसी थी। रात को मंच से उतरे तो मेजबान ने भोजन करने का अनुरोध किया, लेकिन खां साहब ने कहा, 'तानसेन की नगरी में उनकी समाधि पर बिना अकीदत पेश किए कैसे खाना खा सकता हूं।' रात दो बजे खां साहब तानसेन की समाधि पर पहुंचे, मत्था टेका और वहां शहनाई वादन करके उन्हें संगीतमय श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान के बड़े भाई सरोद वादक उस्ताद मुबारक अली खां यह घटना सुनाया करते थे।

बिस्मिल्लाह खां से पहले भी कई शहनाई वादक हुए, लेकिन खां साहब ने शहनाई को प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। आम तौर पर शहनाई वादक कजरी, ठुमरी, चैती और दादरा जैसे उप शास्त्रीय एवं सुगम संगीत बजाते रहे थे, लेकिन बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई पर शास्त्रीय राग बजाना भी शुरू किया, इस वाद्य को शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मंचों पर स्थान दिलाया। 1937 में कलकत्ता (अब कोलकाता) में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में उन्होंने पहली बार शहनाई को बड़े मंच पर स्थापित किया। उसके बाद सात दशकों तक वे दुनिया भर के शास्त्रीय संगीत के मंचों पर शहनाई का जादू जगाते रहे।

खां साहब को शहनाई विरासत में मिली थी। उनके पूर्वज बिहार की भोजपुर रियासत के दरबारी शहनाई वादक थे। छह साल की उम्र में बालक बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के पास बनारस आ गए, जो विश्वनाथ मंदिर में शहनाई वादक थे। मामा ने बालक को शहनाई की विधिवत शिक्षा दी। गंगा घाटों और मंदिरों में नन्हे बिस्मिल्लाह ने रियाज के दौरान भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति को भी आत्मसात किया।

प्रमुख सम्मान व अलंकरण

वर्ष 2001 में भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत होने से पूर्व बिस्मिल्ला खां साहब को वर्ष 1956 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्मभूषण, 1980 में पद्मविभूषण और मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान सहित देश-विदेश की कई संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं।

वर्ष 1959 में बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का जादू फिल्मी दुनिया तक पहुंचा। 'गूंज उठी शहनाई' फिल्म के साथ उनकी शहनाई ने लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए। कदाचित भारतीय फिल्म इतिहास में यह एकमात्र वाद्य रहा, जिसके नाम पर फिल्म का नाम रखा गया था। बिस्मिल्लाह खां ने अपने समय के मूर्धन्य गायक-गायिकाओं के साथ जुगलबंदी की, जिनमें उस्ताद फैयाज खां, अब्दुल करीम खां साहब, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई जैसे कलाकार थे। उन्होंने उस्ताद विलायत खान, उस्ताद अमजद अली खां, वीजी जोग, एन.राजम, एल. सुब्रमण्यम और गिरिजा देवी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ भी जुगलबंदी की। पत्नी के निधन के बाद वह शहनाई को ही अपनी बेगम कहते थे। 21 अगस्त, 2006 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी इस बेगम को उनके साथ ही दफनाया गया।

dpathak2005@gmail.com

रमजान में ज्यादा समय इबादत और दुआ में लगाएं रोजेदार

रमजान उल मुबारक बा बरकत महीना है। रोजा इस्लाम की बुनियादी अरकान में से है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किए गए हैं, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ। रमजान उल मुबारक को तीन अशरो में बांटा गया है। पहले अशरे को अशरा रहमत कहा जाता है, पहले अशरे से ही हर नेकी का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजेदारों की दुआ पर आमीन कहते हैं रोजेदार तमाम दुनियादारी छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिर होकर खूब इबादत कर अपने तमाम गुनाहों से निजात और तौबा करते हैं। इन दुआओं की बरकतों से रब्बुल इज्जत आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाता है। आपको खूब खुशी, तरक्की अता फरमाता है। रमजान उल मुबारक का दूसरा अशरा, जिसको अशरा ए मगफिरत भी कहा जाता है। इन दिनों में अल्लाह अपने बंदों की इबादत व मोहब्बत वा इखलास को देखकर उनके गुनाहों की बख्शीश फरमाएगा। लिहाजा हम को होशियार रहकर ज्यादातर समय इबादत में लगाना होगा और यह दुआ पढ़नी होगी। ए अल्लाह मेरे गुनाहों की मगफिरत फरमाएं ए जहानों के पालनहार।

मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली,
काजी शहर लखनऊ

रमजान का तीसरा अशरा रहमतों का महीना है। तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का है। इस अशरे में खुदा की इबादत करने वालों को जहन्नुम की आग से मुक्ति मिलती है, वैसे तो रमजान का पूरा महीना ही रहमतों का महीना है। लेकिन सबसे अहम है तीसरा अशरा। क्योंकि इसी अशरे की ताक रातों में यानी 21, 23, 25, 27, शब ए कद्र हो सकती है और शब ए कद्र की इबादत का सवाब 1,000 साल की इबादतो के बराबर होता है। 27 रमजान की रात को कुरआन शरीफ नाजिल हुआ। इसलिए इन रातों की अहमियत काफी बढ़ जाती है।

साड़ी दौड़ : भारत में साड़ी को स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है और लगभग पांच हजार वर्ष से अस्तित्व में है। अपनी प्राचीनता के साथ साड़ी आज के दौर के फैशन ट्रेंड में भी है। साड़ी के महत्व को रेखांकित करने के लिए रविवार को हैदराबाद में साड़ी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक साड़ियों में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। एपी

केदारपुरी में हिमखंड टूटा, श्रमिकों के अस्थायी घर टूटे

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग

उत्तराखंड के केदारपुरी में पुराने घोड़ा पड़ाव के पास हिमखंड टूटने से वहां पुनर्निर्माण कार्य करने वाले स्टाफ व श्रमिकों के लिए बने अस्थायी घर टूट गए। साथ ही अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। उधर, केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य जारी है। रामबाड़ा से भैरव गदेरे के बीच पांच किमी हिस्से से बर्फ हटाई जा चुकी है। फिलहाल पैदल मार्ग से एक से डेढ़ मीटर चौड़ाई तक ही बर्फ हटाई जा रही है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की लोनिवि शाखा के अधिशासी अभियंता विनय झिंक्वाण ने बताया कि शनिवार को हेलीपैड के ठीक सामने वाली पहाड़ी पर पैदल मार्ग के पास एक भारी हिमखंड टूटकर गिरा। इससे वहां बने अस्थायी घर ध्वस्त हो गए। इन घरों का निर्माण वहां पुनर्निर्माण कार्य करने वाले स्टाफ और श्रमिकों के लिए किया गया था।

वहीं, केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य गत चार मार्च से चल रहा है। इस कार्य में डीडीएमए लोनिवि के 50 श्रमिक लगे हुए हैं। झिंक्वाण ने बताया कि वर्तमान में केदारपुरी समेत पैदल मार्ग पर तीन से चार फीट बर्फ जमी है।

केदारनाथ धाम में पुराने घोड़ा पड़ाव के पास पहाड़ी से ग्लेशियर टूटने से भवनों को पहुंचा नुकसान। जागरण

बांडीपोरा में हिमस्खलन के कारण फंसे यात्रियों को किया एयरलिफ्ट

राज्य ब्यूरो, जम्मू : उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले में बांडीपोरा से गुरेज जाने वाली सड़क रविवार दोपहर हिमस्खलन के कारण बंद हो गई है और कई लोग फंस गए। प्रशासन ने फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर बांडीपोरा पहुंचाया। वहीं, बंद सड़क को खोलने में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) जुटा हुआ है। बांडीपोरा जिले में रविवार को कई बार हिमस्खलन हुआ। इससे जिले के गुरेज सेक्टर के बर्फ से घिरे कंजालवाल क्षेत्र में 120 यात्री फंस गए। जिला प्रशासन ने इन यात्रियों को निकालने के लिए विशेष हवाई उड़ानों की व्यवस्था की। 60 यात्रियों को बांडीपोरा से कंजालवान और 60 को कंजालवान से बांडीपोरा पहुंचाया गया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में कई बार हिमस्खलन होने से सड़कों पर बर्फ जम गई है। इससे वाहनों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन का कहना है कि हिमस्खलन में किसी भी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है।

51 लाख रुपये के नोटों से बुद्धेश्वर बाबा का शृंगार

नईदुनिया, बड़नगर (उज्जैन) : मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बुद्धेश्वर धाम पर श्री बुद्धेश्वर महादेव बाबा का रविवार को 51 लाख रुपये के नोटों से शृंगार किया गया। बुद्धेश्वर धाम पर महाशिवरात्रि से मेले का आयोजन भी चल रहा है। बुद्धेश्वर मित्र मंडल के प्रमुख अशोक पहलवान ने बताया कि तीन दिन पूर्व से 51 लाख रुपये के नोटों से बाबा का शृंगार का कार्य चल रहा था, जो रविवार को पूर्ण हुआ। मेले के समापन 23 मार्च तक भक्तजन इस ऐतिहासिक और अभिनव शृंगार के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। बाबा का 20, 50, 100, 200, 500 रुपये के नोट और सिक्कों से मनमोहक शृंगार किया गया। ज्ञात हो कि बीते वर्ष भी 21 लाख रुपये के नोटों से बाबा का आकर्षक शृंगार किया गया था।

बड़नगर के बुद्धेश्वर धाम में नोटों से सजाए गए बाबा बुद्धेश्वर महादेव। -नईदुनिया

जल सुरक्षा व विश्व शांति का संदेश देंगे चंबल के पूर्व दस्यु

- **जल पुरुष राजेंद्र सिंह बोले, चिंता नहीं की तो बेपानी होगी दुनिया**
- **करौली में 21 मार्च को जारी किया जाएगा जल आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप**

आगरा में पत्रकारों से बात करते जल पुरुष राजेंद्र सिंह (मध्य में)। जागरण

जागरण संवाददाता, आगरा

वर्ष 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष दुनिया के 80 देशों में चुनाव होना है। राजनीतिक दलों को पानी की चिंता नहीं होगी तो यह दुनिया बेपानी हो जाएगी। राजस्थान के करौली स्थित महावीर जी में 20-21 मार्च को जल एवं शांति लोक सम्मेलन में चंबल के पूर्व दस्यु जल संरक्षण का संदेश देंगे। 21 मार्च को जल आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप भी जारी किया जाएगा।

जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने रविवार को बताया कि देश के सतत आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा व खुशहाली के लिए जल सुरक्षा जरूरी है। लोगों के पास उनकी घरेलू व आजीविका की जरूरत के लिए जब पर्याप्त पानी होगा, तभी वे सम्मान के साथ जी सकेंगे। राजनीतिक दलों को चुनाव घोषणा पत्र में जल संरक्षण की स्पष्ट रणनीति बतानी होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम जल शांति वर्ष है। बताया कि चंबल का क्षेत्र कभी बंदूकों की आवाज से गूंजता था। पानी की कमी के कारण खेती संभव नहीं थी। परिवार का पेट भरने के लिए लोगों ने हथियार उठा लिए थे। तरुण भारत संघ ने जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित किया। पानी आया तो लोगों ने बंदूकें छोड़ दीं और खेती शुरू कर दी।

'डार्क मैटर' व बीएयू के रहस्यों को सुलझाने को पेश किया नया माडल

- **आइआइटी-गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने विज्ञानियों के साथ किया अनुसंधान**

नई दिल्ली, प्रेट्र : ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में 'डार्क मैटर' और ब्रह्मांड की बेरियोन एसिमेट्री (बीएयू) के रहस्यों को सुलझाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय विज्ञानियों संग मिलकर नया माडल पेश किया है। इसे 'फिजिकल रिव्यू डी' में प्रकाशित किया गया है। विज्ञानियों के अनुसार ब्रह्मांड का पांच प्रतिशत हिस्सा तारे और आकाशगंगा जैसे दिखने वाले या बेरियोनिक 'मैटर' से बने हैं। इस दृश्य 'मैटर' का पांच गुना 'डार्क मैटर' से बना है। 'डार्क मैटर' ऐसा पदार्थ होता है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। वहीं दृश्य मैटर बेरियोन (मैटर) व एंटीबेरियोन (एंटीमैटर) के बने होते हैं।

आइआइटी, गुवाहाटी में भौतिकशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर देबाशीष बोरा ने बताया, शुरुआत में ब्रह्मांड में मैटर व एंटीमैटर के समान मात्रा में होने की उम्मीद की जाती थी पर आज हम अधिशेष मैटर देखते हैं। यह रहस्य है, जिसे ब्रह्मांड के बेरियोन एसिमेट्री (बीएयू) के रूप में जाना जाता है। इस पहेली को सुलझाना बड़ी चुनौती है। बोरा ने बताया कि हमारे माडल के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड में, तापमान के प्रभाव के कारण डार्क मैटर आर्डिनरी मैटर में बदल जाता है, जिससे मैटर व एंटीमैटर में असंतुलन पैदा होता है। हम अद्वितीय प्रकार के डार्क मैटर का प्रस्ताव करते हैं। इसके अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जावान रूप से व्यवहार्य क्षय के कारण, डार्क मैटर आंशिक रूप से क्षय के कारण साधारण मैटर बनकर बीएयू बनाता है। जैसे ही ब्रह्मांड ठंडा होता है, डार्क मैटर स्थिर हो जाता है, जिससे आज डार्क मैटर के अवशेष के रूप देखा जाता है।

अंतरराष्ट्रीय अनुसंधानकर्ताओं में अमेरिका स्थित पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के अर्नब दासगुप्ता, विलियम एंड मैरी विश्वविद्यालय में 'हाई एनर्जी थ्योरी ग्रुप' के मैथ्यू नोज और दक्षिण कोरिया में क्यूंगपुक नेशनल यूनिवर्सिटी के रिशव रोशन शामिल हैं।

डल झील किनारे फार्मूला-4 कार शो में रफ्तार और जोश का जुनून

- **कार और बाइक सवारों ने करतब भी दिखाए, ललित घाट से नेहरू पार्क तक हुआ आयोजन**

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे रविवार को फार्मूला-4 कार शो में रफ्तार, रोमांचक और हैरतअंगेज करतबों ने युवाओं का जोश बढ़ाया। पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए करियर विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार फार्मूला-4 कार शो हुआ। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में करीब 1.7 किमी लंबी फार्मूला-4 कार रेस में पेशेवर चालकों ने ललित घाट से नेहरू पार्क तक करतब दिखाए। सुबह 10 बजे शुरू हुआ शो दोपहर दो बजे समाप्त हुआ। इवेंट के दौरान जेके टायर मोटरस्पोर्ट्स की टीम ने स्टंट और ड्रिफ्टिंग के डेमो दिखाए, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।

लोगों को रोमांचित करने के लिए जेके मोटरस्पोर्ट्स की टीम के सदस्य भी उत्साहित दिखे। उनके अनुसार ऐसे शो न केवल युवाओं को इस खेल में आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे बल्कि कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को लाभ पहुंचेगा। चालकों ने युवाओं के साथ कार स्पोर्ट्स के बारे में अनुभव साझा किया। रेसिंग इवेंट पर्यटन विभाग के तत्वावधान में फार्मूला-4 और इंडियन रेसिंग लीग के सहयोग से हुआ। आयोजकों ने कहा कि यह आयोजन केवल गति और प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं है बल्कि एकता का उत्सव है। कुछ वर्षों में कश्मीर ने मोटरस्पोर्ट्स आयोजनों के क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल की है। ये फार्मूला ड्राइवर फार्मूला-4 खेल में करियर बनाने के लिए हमारे युवाओं का मनोबल बढ़ाएंगे।

प्लास्टिक बैरिकेड में दो कारें घुस गईं

फार्मूला-4 रेस में दर्शकों की सुरक्षा के लिए लगे प्लास्टिक बैरिकेड में दो कारें घुस गईं। कोई घायल नहीं हुआ।

****

दैनिक जागरण
राष्ट्रीय संस्करण
सोमवार 18 मार्च, 2024
आजकल
14
www.jagran.com

राष्ट्रवाद को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पारित किया रौलेट एक्ट

ब्रिटिश सरकार ने 1919 में आज ही रौलेट एक्ट पारित किया था। इस कानून से सरकार को किसी भी व्यक्ति को मुकदमे के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति मिल गई थी। गांधी जी और अन्य नेताओं ने इस दमनकारी कानून के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था, जिसे रौलेट सत्याग्रह कहा जाता है।

अंतरिक्ष में चलने वाले पहले इंसान बने एलेक्सी लियोनोव

सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव 1965 में आज ही के दिन अंतरिक्ष में चलने वाले पहले इंसान बन गए थे। उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकल कर 12 मिनट 9 सेकेंड तक चहलकदमी की। हालांकि, इस दौरान उनका स्पेससूट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था।

विश्व के महान क्षेत्ररक्षकों में गिने जाते हैं एकनाथ सोलकर

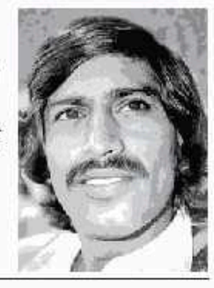

पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एकनाथ सोलकर का जन्म 1948 में आज ही बांबे (अब मुंबई) में हुआ था। सोलकर ने नेट में अपनी गेंदबाजी से बांबे के खिलाड़ियों को प्रभावित किया। 1966-67 में बांबे के लिए पहला रणजी मैच खेला। टेस्ट करियर की शुरुआत 1969 में न्यूजीलैंड के खिलाफ की। सोलकर ने भारत के लिए कुल 27 टेस्ट और 7 वनडे खेले। टेस्ट में एक शतक और 6 अर्धशतक लगाया और 53 कैच लिए। उनका प्रति मैच 1.96 कैच का रिकार्ड शानदार है। 26 जून, 2005 को उनका निधन हो गया।

पांच हजार साल पुराने कंकालों में डाउन सिंड्रोम के 'लक्षण'

- सात शिशुओं की प्राचीन हड्डियों के डीएनए से डाउन सिंड्रोम का लगाया पता
- प्रागैतिहासिक काल में स्पेशल चाइल्ड्स से कैसा वर्ताव करते थे, चलेगा पता

वैज्ञानिकों ने सात शिशुओं की प्राचीन हड्डियों के डीएनए से डाउन सिंड्रोम का निदान किया है, जिनमें से एक की उम्र 5,500 वर्ष है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित उनकी पद्धति, शोधकर्ताओं को यह जानने में मदद कर सकती है कि प्रागैतिहासिक समाज डाउन सिंड्रोम और अन्य दुर्लभ स्थितियों वाले लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते थे।

विज्ञानियों ने कंकालों का डीएनए टेस्ट कर किया अध्ययन। फाइल

700 में से एक शिशु को होता था डाउन सिंड्रोम

वर्तमान में 700 शिशुओं में से 1 में डाउन सिंड्रोम के लक्षण पाए जाते हैं। यह क्रोमोसोम-21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है। अतिरिक्त क्रोमोसोम अतिरिक्त प्रोटीन बनाता है, जो हृदय दोष और सीखने की अक्षमताओं सहित कई परिवर्तनों का कारण बन सकता है। इसी आधार पर विज्ञानियों ने जानने की कोशिश की कि प्रागैतिहासिक काल में यह अनुपात कितना था।

कम उम्र में मां बनने से बच्चे में पाई जाती है बीमारी

वर्तमान में महिलाओं के अधिक उम्र में मां बनने से ऐसी विसंगतियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। वहीं प्रागैतिहासिक काल में कम उम्र में मां बनने से बच्चे में डाउन सिंड्रोम व हृदय रोग जैसी कई बीमारियां होती थीं। अंतर सिर्फ इतना है कि उस समय चिकित्सकीय सुविधा नहीं होने से ऐसी बीमारियों से ग्रसित बच्चे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते थे, जिससे डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियां यदा-कदा होती थीं।

कंकालों के टुकड़े हो जाने की वजह से उनके गुणसूत्र भी टूट गए

बर्लिन में जर्मन पुरातत्व संस्थान की मानवविज्ञानी डा. जूलिया ग्रेस्की ने कहा कि बौनेपन का पता लगाना तो आसान है, लेकिन डाउन सिंड्रोम जैसे लक्षणों का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वह उतनी संख्या में जीवित नहीं रहते थे। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार हड्डियों से ही कुछ दुर्लभ स्थितियों जैसे बौनापन या आंखों के आकार व चेहरे-मोहरे की पहचान कर सकते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम जैसी स्थितियों का पता लगाना वाकई कठिन है, क्योंकि मृत्यु के बाद गुणसूत्र टूट जाते हैं।

5,500 साल पुराने मकबरे में दफन छह साल के बच्चे के कंकाल में मिले डाउन सिंड्रोम के लक्षण

2020 में, ट्रिनिटी कालेज डबलिन में आनुवंशिकीविद् लारा कैसिडी और उनके सहयोगियों ने डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे का निदान करने के लिए पहली बार प्राचीन डीएनए का उपयोग किया। वे पश्चिमी आयरलैंड में 5,500 साल पुराने मकबरे में दफन किए गए कंकालों से जीन की जांच कर रहे थे। छह महीने के बच्चे की हड्डियों में क्रोमोसोम 21 से असामान्य रूप से उच्च मात्रा में डीएनए पाया गया था, यानी इसके विपरीत आनुवंशिक रूप से डाउन सिंड्रोम की पहचान करना मुश्किल नहीं है, कम से कम जीवित लोगों में ऐसा नहीं देखा गया है। हाल के वर्षों में आनुवंशिकीविद् प्राचीन हड्डियों में संरक्षित करने के लिए डीएनए पर अपने तरीकों का परीक्षण कर रहे हैं।

आइसलैंड ज्वालामुखी में विस्फोट

आइसलैंड के दक्षिण-पश्चिम में स्थित ग्रिंडाविक के ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद पूरा आसमान सुर्ख हो गया। लावा और धुआं कई किमी की ऊंचाई तक फैल गया। ज्वालामुखी से लावा के फव्वारे निकल रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में साढ़े तीन किमी लंबी दरारें हो गई हैं, जिनसे लावा फूट रहा है। चार माह में इस ज्वालामुखी में तीसरी बार विस्फोट हुआ है। पहला विस्फोट दिसंबर 2023 और दूसरा इसी वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह में हुआ था। यूनिवर्सिटी आफ पोटरसमाउथ में ज्वालामुखी विशेषज्ञ कार्मेन सोलाना के अनुसार, यह क्षेत्र रीएक्टीवेट हो चुका है। एएफपी

इधर-उधर की

... इसलिए एक माह परिवार से दूर रहता है यह शख्स

नाइजीरिया, एजेंसी: लोग जिंदगी में एक तरह की दिनचर्या से ऊब जाते हैं। इससे उबरने के लिए कोई छुट्टियां लेकर घूमने निकल जाता है या घर पर ही कुछ दिन परिवार के साथ बिताता है। पर एक शख्स ऐसा भी है जो हर साल एक महीने के लिए परिवार से ब्रेक लेता है और पत्नी व बच्चों से दूर रहता है। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, अदामु सालिसु नाम का 35 साल का व्यक्ति नाइजीरिया के लापाई शहर का रहने वाला है। पेशे से कंटेंट राइटर अदामु के तीन बच्चे हैं और उनकी 27 साल की पत्नी माइमोना सालिसु घरेलू महिला हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे इस काम को परिवार के लिए भी फायदेमंद बताते हैं।

हर साल परिवार से एक माह का ब्रेक लेते हैं अदामु ● फोटो: सांकेतिक

प्रयोगशाला में बनाए मिनी किडनी व फेफड़े

भ्रूण को संभाल कर रखने वाले द्रव्य में से कोशिकाएं निकालकर विकसित किए गए अंग

12 गर्भवतियों के गर्भ से जमा की कोशिकाएं

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

विज्ञानियों ने लैब में छोटे आकार के फेफड़े और अन्य अंग उगाने में कामयाबी हासिल की है। यह सफलता आने वाले समय में गर्भवती महिलाओं के इलाज की दिशा में बड़े रास्ते खोल सकती है। विज्ञानियों के अनुसार गर्भ में भ्रूण को संभाल कर रखने वाले द्रव्य में से कोशिकाएं निकालकर उनसे ये अंग विकसित किए गए हैं. विज्ञानियों ने इन्हें आर्गनोएड्स नाम दिया है।

ये छोटे-छोटे अंग नई दवाएं विकसित करने के साथ-साथ अंगों की कार्य-प्रक्रिया समझने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी कालेज लंदन और ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट हास्पिटल के शोधकर्ताओं ने 12 गर्भवती महिलाओं के गर्भ से कोशिकाएं जमा कीं। ये सैंपल नियमित जांच के दौरान ही लिए गए। उन कोशिकाओं से पहली बार ये मानव अंगों के छोटे माडल विकसित किए गए। इस खोज पर 'नेचर मेडिसिन' पत्रिका में एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है।

यूनिवर्सिटी कालेज लंदन की शोधकर्ता मातिया गेरली इस खोज को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने जो स्टेम सेल गर्भ से निकाले थे, वे दरअसल भ्रूण द्वारा उतारी गई कोशिकाएं थीं। गर्भावस्था के दौरान यह आम प्रक्रिया है। इसे बनाने की प्रक्रिया के दौरान विज्ञानियों ने कहा उन कोशिकाओं को अलग-अलग करके उनकी पहचान की गई कि वे किस अंग से आए हैं। उनमें से फेफड़े, गुर्दे और आंत से आई कोशिकाओं को अलग-अलग किया गया और फिर उनका इस्तेमाल अंग विकसित करने में किया गया। आर्गनाएड बनाने का यह पहला प्रयास नहीं है, लेकिन अब तक जो आर्गनाएड बनाए गए हैं वे वयस्क कोशिकाओं से लिए गए थे। लेकिन वयस्क कोशिकाओं से स्टेम सेल लेने के बहुत से नियम-कानून हैं। गर्भ में मौजूद अमोनिक द्रव्य से कोशिकाएं लेना इन नियमों के दायरे से बाहर हैं इसलिए वैज्ञानियों के लिए यह प्रक्रिया आसान है।

नैतिकता पर बहस : ब्रिटेन में गर्भपात के लिए आमतौर पर 22 हफ्ते की सीमा निर्धारित है। उसके बाद गर्भ से कोशिकाएं नहीं ली जा सकतीं। इस वजह से उस सीमा के बाद वे भ्रूण के विकास का अध्ययन कोशिकाओं के जरिए नहीं कर सकते। बाकी दुनिया में भी गर्भपात को लेकर अलग-अलग लेकिन कड़ी सीमाएं तय हैं। ऐसे में फिलहाल इस प्रक्रिया को करने के लिए नियत समय तय किए है।

गर्भ में मौजूद द्रव्य से विकसित किए जाते हैं अंग। फाइल

छह हफ्ते लगे आर्गनाएड्स बनाने में

अमोनिक द्रव्य से लैब में आर्गनाएड्स बनाने में चार से छह हफ्ते लगते हैं तो अगर अजन्मे बच्चे में कोई समस्या नजर आती है तो उसका इलाज जन्म से पहले करने के लिए काफी समय मिल सकता है।

यह होगा फायदा : विज्ञानियों का मानना है कि उनकी खोज भविष्य में डक्टरों को बच्चे के जन्म से पहले ही जन्मजात बीमारियों के इलाज में मदद कर सकती है। इसके अलावा गर्भ में ही बच्चे के लिए जरूरी पोषण मुहैया कराया जा सकता है।

हृदय रोग के जोखिम कारक निम्न व मध्यम आय वाले देशों में अधिक

अनुसंधान

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में गरीबी में रह रहे लोगों में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी स्थितियां अधिक होती हैं, जो हृदय रोग का कारण बन सकती हैं। शोधकर्ताओं ने गरीबी और हृदय रोगों (सीवीडी) के बीच संबंधों की जांच की। कहा, निष्कर्षों ने एक आम धारणा का खंडन किया है कि गरीबी में रहने वाले लोगों के शारीरिक श्रम से जुड़ी जीवनशैली जैसे पर्यावरणीय कारक हृदय रोग जोखिम कारकों से रक्षा करते हैं। अध्ययन का यह निष्कर्ष हाल में जर्नल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया कि हृदय रोग के खतरे निम्न व मध्यम आय वाले देशों में अधिक पाए गए। टीम ने पाया कि जोखिम कारक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, धूमपान, मोटापा और डिस्लिपिडेमिया (रक्त में असामान्य लिपिड स्तर) गरीबी में क्रमशः 17.5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 10.6 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत के बीच मौजूद थे। अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने 78 देशों में 100 से अधिक राष्ट्रीय प्रतिनिधि घरेलू सर्वेक्षणों के डाटा का विश्लेषण किया।

30 लाख से अधिक लोगों के डाटा को शामिल करते हुए शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि यह वैश्विक आबादी का 53 प्रतिशत और भारत सहित निम्न व मध्यम आय वाले देशों में रहने वाले 64 प्रतिशत को कवर करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के सहायक प्रोफेसर पास्कल गेल्डसेट्जर ने कहा कि यह अध्ययन वैश्विक समाज के गरीब वर्गों के लोगों के लिए स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए एक अहम अनुभवजन्य आधार प्रदान करता है। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

करीना कपूर ने भी बढ़ाए दक्षिण की ओर कदम

कन्नड़ फिल्म से दक्षिण भारतीय सिनेमा में होगा करीना का पदार्पण। फाइल

अखिल भारतीय फिल्मों के बढ़ते बाजार ने कलाकारों को भी भाषाई बंदिशों से आगे बढ़ते हुए दूसरे भाषाओं की फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया है। इस क्रम में पति और अभिनेता सैफ अली खान की तरह अभिनेत्री करीना कपूर भी दक्षिण भारतीय सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। इसकी पुष्टि स्वयं करीना ने की। सैफ तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट वन से दक्षिण भारतीय सिनेमा में पदार्पण करने जा रहे हैं। उनके अलावा अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की भी यह पहली दक्षिण भारतीय फिल्म होगी। दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपने पदार्पण का रहस्योद्घाटन करीना ने हाल ही में प्रशंसकों से बातचीत के दौरान किया। वीडियो काल पर हुई इस बातचीत का वीडियो फिलहाल इंटरनेट मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें करीना कहती हैं, 'अब जैसा कि मैंने कहा है कि मैं एक बड़ी साउथ इंडिया फिल्म कर सकती हूं। अब तो पैन इंडिया (अखिल भारतीय) फिल्मों का दौर है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं इसकी शूटिंग कहां करूंगी। हालांकि, अपने सारे प्रशंसकों को यह बताते हुए मैं उत्साहित हूं कि मैं पहली बार साउथ इंडियन फिल्म करने जा रही हूं।' करीना ने अपनी पहली दक्षिण भारतीय फिल्म के लेकर कोई जानकारी तो नहीं साझा की। हालांकि, इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि वह केजीएफ फेम अभिनेता यश की अगली कन्नड़ फिल्म टाक्सिक से दक्षिण भारतीय सिनेमा में पदार्पण कर सकती हैं।

कठिन दौर जैसा कुछ नहीं होता

अभिनेता अरबाज खान अभिनय के साथ फिल्म निर्माण में भी सक्रिय हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस तले फिल्म पटना शुक्ला का निर्माण किया गया है। रवीना टंडन और मानव विज अभिनीत यह फिल्म रोल नंबर बदलने की धांधली को लेकर है। डिज्नी प्लस हाट स्टार पर यह फिल्म 29 मार्च को रिलीज होगी। उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश:

● दबंग जैसी कमर्शियल फ्रेंचाइजी के बाद अब आप कंटेंट प्रधान फिल्में बनाने की तैयारी में है?

– मैं मुख्य रूप से दिलचस्प कहानी देखता हूं। वो अगर दिलचस्प होगी तो उसे पसंद करने या कमर्शियल होने की संभावना बढ़ जाती है। आप सिर्फ यह सोच कर फिल्म नहीं बना सकते कि यह एंटरटेनिंग होगी। शायद जो मुझे एंटरटेनिंग लगे वो दूसरों को न लगे। कोई चीज अगर दिलचस्प होगी और आपको बांधकर रखेगी तो वो अपने आप एंटरटेनिंग होगी। पटना शुक्ला अच्छा विषय है, सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। घोटाले होते हैं लेकिन यह किसी व्यक्ति विशेष की जिंदगी पर आधारित नहीं है। पीड़िता का मुकदमा लड़ रही महिला वकील कामकाजी होने के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी संभाल रही है। किरदार अच्छे हैं। हमने एक गंभीर विषय को एंटरटेनिंग और बांध कर रखने वाली फिल्म में तब्दील किया है।

● आप इसे थिएटर में भी रिलीज कर सकते थे...

– यह पहले से तय था कि इस फिल्म को ओटीटी पर लाना है। ओटीटी पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो का प्रेशर नहीं होता है। इसे अपनी सुविधानुसार देखा जा सकता है। थिएटर में यह सुविधा हमेशा के लिए नहीं होती। मैं नहीं चाहता था कि भीड़ में अच्छी चीज गुम जाए। अगर कोई बड़ी फिल्म रिलीज हो और हमारी फिल्म को स्क्रीन न मिले। यह सब दिक्कतें यहां पर नहीं थीं। हमें लगा कि यहां पर प्रतिक्रिया ज्यादा मिलेगी। कल को इस फ्रेंचाइजी की महत्ता बढ़ जाए और लोग, उसे थिएटर में लाने की मांग करें तो हम लाएंगे।

● फ्रेंचाइज के तौर पर आगे बढ़ाने का इरादा है ?

– हो सकता है। हमारे दिमाग में इसे लेकर कई चीजें हैं। यह फ्रेंचाइज अलग-अलग तरीके की कहानियां लेकर आ सकता है। फिल्म की रिलीज के बाद दर्शकों और ओटीटी का फीडबैक मिलेगा कि इसका सीक्वल बनाओ या कुछ और।

● जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा है ?

– मेरे हिसाब से जिंदगी में कठिन दौर जैसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि हर स्टेज पर आप कुछ सीखते हैं। यही सबसे अच्छी चीज है। जीवन का मतलब अनुभवों से है, बुरे दौर जो सिखा जाते हैं शायद अच्छे दौर से आप नहीं सीख सकते। वह कहीं न कहीं आपको जागरूक कर देते हैं।

● बेटे अरहान की इंडस्ट्री में आने की तैयारी है?

– मेरा बेटे के पास खुद के लिए अच्छी योजना है। वह बहुत मेहनती और ईमानदार है। उसके पास हमारे पूरे परिवार की गाइडेंस हैं। उसके पास मौके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह क्या करना चाहता है, इसे लेकर बहुत कांफिडेंट है। वह अपनी कार्य योजना पर काम भी कर रहा है। मुझे लगता है कि बतौर एक्टर उसके आने की संभावना ज्यादा है। उसकी इसमें दिलचस्पी है।

● दबंग 4 बना रहे थे। उसका क्या हुआ? उसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं?

– (मुस्कुराते हुए) दबंग 4 तो इंशाअल्लाह बनेगी। पर वो कब बनेगी हम उसके बारे में सुनिश्चित नहीं है। पर बनेगी जरूर। उसके अलावा वेब सीरीज तनाव 2 के पहले एपिसोड के आसपास मेरा काम है। एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग मैंने पूरी की है। वह काफी दिलचस्प फिल्म है। नवाजुद्दीन सिद्दिकी के साथ सेक्शन 108 फिल्म की है। उसके अलावा दो फिल्में हैं।

(रिमिता श्रीवास्तव)

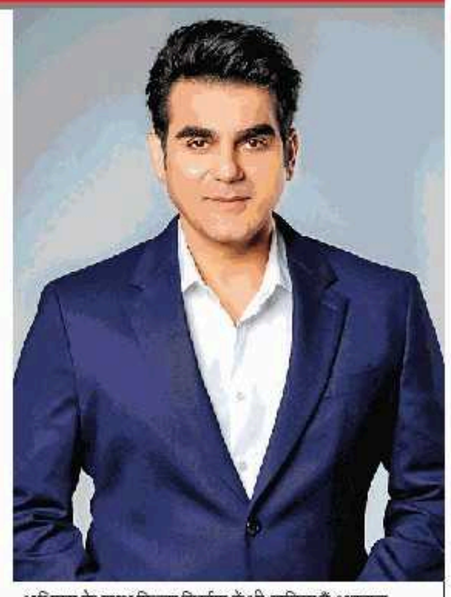

अभिनय के साथ फिल्म निर्माण में भी सक्रिय हैं अरबाज ● टीम अरबाज

● आपने करियर की शुरुआत दरार फिल्म में निगेटिव भूमिका से की थी। उस समय रिस्क नहीं लगा?

– उस वक्त मैं ऐसे स्टेज पर आ गया था कि मुझे बस काम करना है। एक उम्र होती है, जब लगता है कि अब आपको फलां काम करना है, लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा तो जो अच्छा मिल रहा होता है उसे स्वीकार लेते हैं। मैं करीब 26 साल का था, जब मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला। उससे पहले ऐसा नहीं था कि मैं काम देख नहीं रहा था। अब्बास मस्तान बड़े निर्देशक थे। चिंटूजी (ऋषि कपूर) और जूही चावला थे फिल्म में। मुझे लगा कि निगेटिव है किरदार अच्छा है। लोग पहचानेंगे, कर लेते हैं। अभी करियर पड़ा है छवि बदलने के लिए तो कर लिया। उस समय वही बेस्ट आफर था। मुझे काम शुरू करना था तो लगा कि यही समय अपनी प्रतिभा को दिखाने का है। आज 25 साल बाद भी बतौर कलाकार मुझे काम मिल रहा है। मैं काफी व्यस्त हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सलमान खान, शाह रुख खान या आमिर खान बन गया हूं लेकिन मेरे पास काम तो है। इन सुपरस्टार के अलावा भी बाकी पात्रों के लिए कलाकार चाहिए। तो हम उनमें से आ जाते हैं, जिन्हें काम मिलता है। मैं अभी एक टाक शो भी कर रहा हूं। निर्माता हूं। मेरे पास अपने और परिवार के लिए समय भी है। अगर बहुत सफल कलाकार होता तो शायद यह सब करने का मौका ही नहीं मिलता।

बायोपिक फिल्म चकदा एक्सप्रेस की राह में फिर आई लाल झंडी

कई बार निर्माण से प्रदर्शन के पड़ाव तक पहुंचने में फिल्मों को काफी उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। इस मामले में पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक फिल्म चकदा एक्सप्रेस ताजा उदाहरण है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के भाई तथा निर्माता कर्णेश शर्मा ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर किया है। अनुष्का इसमें केंद्रीय भूमिका में हैं। फिल्म बनकर तैयार है, लेकिन अब एक बार फिर इसके प्रदर्शन की राह में रोड़े आ गए हैं। हाल में नेटफ्लिक्स ने इस साल प्रदर्शन की कतार में शामिल अपने करीब 22 प्रोजेक्ट्स की सूची जारी की। इस सूची में चकदा एक्सप्रेस का जिक्र कहीं नहीं किया गया। इसके पीछे कर्णेश की प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स और नेटफ्लिक्स के बीच मतभेद बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्णेश व नेटफ्लिक्स के बीच हुए करार से नेटफ्लिक्स ने हाथ पीछे खींच लिया है। इसके पीछे रचनात्मक असहमति और बजट की समस्या है। ऐसे में कर्णेश और नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन में बन रही दो फिल्मों चकदा एक्सप्रेस तथा अफगानी शो की रिलीज अटक गई है। अफगानी शो में विजय वर्मा के साथ अभिनेत्री तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं।

चकदा एक्सप्रेस में पूर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की भूमिका में होंगी अनुष्का। फाइल

गाना लिखने के बाद सबसे पहले इन्हें सुनाते हैं इक्का

कोई भी रचना तैयार करने के बाद कलाकारों के लिए उसके प्राथमिक श्रोताओं या दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत अहम होती है। इसलिए कई गीतकार, संगीतकार और गायकों की आदत हैं कि वे गाना बनने के बाद उसे सबसे पहले अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सुनाते हैं। रैपर और गायक इक्का रचनाएं सबसे पहले अपने दोस्तों को सुनाते हैं। इस बारे में उनका कहना है, 'कोई भी गाना लिखने के बाद मैं सबसे पहले उसे दोस्तों और टीम को सुनाता हूं। मैं बस सुनाता हूं, उनसे पूछता नहीं कि गाना कैसा है या कैसा नहीं है। सही बात दुनिया बताती है कि सच में कैसा है?' वहीं अंकित सिंह पटियाल से इक्का बनने का सफर भी दिलचस्प है। वह बताते हैं, 'मेरा नाम अंकित सिंह पटियाल है। स्कूल के दिनों में मैंने पापा से कहा भी कि आपने ये कैसा नाम रखा है, इसको बदल दो। तो पापा ने कहा अब तो तुम्हारा नाम रखा जा चुका है, उसका कुछ नहीं कर सकता हूं। हां, छोटा कर सकते हो। उन्होंने सुझाव दिया कि इसको अक्की कर देते हैं। अंग्रेजी में अक्की लिखने के बाद जब मैंने उसकी स्पेलिंग उल्टी कर देखी तो इक्का नाम बन रहा था। तो मैंने अपना नाम इक्का रख लिया।'

आगामी दिनों में कई इंडिपेंडेंट गाने लाएंगे इक्का। Instagram (@ikkamusic)

खुद को चाकलेटी ब्वाय नहीं मानते हैं माधवन

अभिनेता आर माधवन ने अपने तीन दशक के करियर में विविध भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि उनकी चाकलेटी हीरो की छवि रही है। जबकि माधवन कभी खुद को इस छवि में स्वीकार नहीं पाए हैं। चाकलेटी ब्वाय बुलाए जाने को लेकर एक साक्षात्कार के दौरान माधवन ने कहा कि कोई खुद को इस तरह की पदवी कैसे दे सकता है? यह लोग आपको देते हैं। जब भी मुझे कोई कांप्लीमेंट दिया जाता है मैं उसे स्वीकार नहीं पाता हूं। जब मुझे लेकर यह सब कहा जाता है तो मुझे लगता है कि किसी और के बारे में बात हो रही है। मेरी पत्नी सरिता कहती हैं जब आपके बारे में बात होती है तो बच्चों की तरह बुद्धू वाले भाव आपके चेहरे पर आते हैं। आप बहुत आसानी से बातचीत का विषय बदल लेते हैं। आप उसे विनम्रता से क्यों स्वीकार नहीं करते हैं। जब भी मुझे चाकलेटी ब्वाय बुलाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं तो आर्मी कमांडो था यह चाकलेटी ब्वाय क्यों बुला रहे हैं। पर आश्चर्यजनक से वही किरदार मेरे पास आ रहे थे। अगर आप हिंदी फिल्मों को देखें तो सिर्फ फिल्म रहना है तेरे दिल में चाकलेटी ब्वाय की छवि थी। उसके बाद अलग-अलग फिल्में की। बता दें कि माधवन एनसीसी के छात्र रह चुके हैं। उन्हें एनसीसी के सात कैडेट के साथ इंग्लैंड जाकर ब्रिटिश आर्मी द रायल आर्मी के साथ ट्रेनिंग का मौका मिला था। वह हालिया रिलीज फिल्म शैतान में नकारात्मक भूमिका में नजर आए हैं।

तीन दशक के करियर में माधवन ने निभाए हैं वैरायटी किरदार। फाइल

टिकट खिड़की पर नहीं लड़ पाई सिद्धार्थ की योद्धा, बस्तर भी धड़ाम

योद्धा के बाद सच्ची घटना पर आधारित फिल्म करने की है सिद्धार्थ की तैयारी ● जागरण आर्काइव

इस साल के लगभग ढाई महीनों में हिंदी सिनेमा में फाइटर, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, आर्टिकल 370 और शैतान फिल्मों ने टिकट खिड़की पर ठीक-ठाक कमाई तो की, लेकिन कोई भी ब्लाकबस्टर नहीं हुई। इस सप्ताह दो हिंदी फिल्में सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत योद्धा और अदा शर्मा अभिनीत बस्तर : द नक्सल स्टोरी प्रदर्शित हुई। यह दोनों फिल्में भी टिकट खिड़की पर उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाईं। सागर अंब्रे और पुष्कर ओझा के संयुक्त निर्देशन में बनी फिल्म योद्धा के लिए समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं कुछ खास नहीं रही। फिल्म ने शुक्रवार को 4.25 करोड़ रुपये की ओपनिंग की। वहीं दूसरे दिन बढ़त के साथ शनिवार को फिल्म की कमाई 6.01 करोड़ रुपये रही। इस तरह प्रदर्शित होने के पहले दो दिनों में फिल्म ने कुल 10.26 करोड़ रुपये कमाए।

वहीं फिल्म द केरल फाइल्स की सफलता से उल्लासित निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन को फिल्म बस्तर : द नक्सल स्टोरी से भी वैसी ही उम्मीदें थी। हालांकि, यह फिल्म टिकट खिड़की पर बिल्कुल नहीं चल पा रही है। इस फिल्म को शुक्रवार को सिर्फ 40 लाख रुपये की ओपनिंग मिली। दूसरे दिन थोड़ी बढ़त के साथ फिल्म की कमाई करीब 75 लाख रुपये रही।

****